चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

06 अक्टूबर–12 अक्टूबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

राहत देने वाला खुद आफत में

पेज-03

वरुण के नाम पर इतनी चिल्लपों क्यों!

पेज-06

रिलायंस ने घुटने टेके

पेज-07

साईं की महिमा

पेज-12

हरियाणा की जींद रैली से

नीतीश की ललकार

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि देश में एक सशक्त व स्थिर सरकार हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में एक सशक्त व विश्वसनीय विपक्ष हो. देश में आज एक स्थिर सरकार मौजूद है, लेकिन विपक्ष कहां है? कांग्रेस पार्टी की साख इतनी ख़त्म हो गई कि उसके पास नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ज़रूरी लोकसभा सांसदों की संख्या तक नहीं है. लोगों का भरोसा कांग्रेस से टूट चुका है. दूसरी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी जनता के भरोसे को वापस पाने के लिए कुछ कर भी नहीं रही है. चुनाव के बाद से राहुल गांधी और सोनिया गांधी निष्क्रिय हो गए हैं. तो सवाल उठता है कि क्या देश में फिर से वन पार्टी डोमिनेन्स का दौर चल पड़ेगा, जो देश में प्रजातंत्र के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. कांग्रेस अगर शिथिल पड़ जाती है, तो यह ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय दलों की होगी कि वे आगे आएं और एक सशक्त विपक्ष का निर्माण करें. हरियाणा के जींद में लाखों लोगों की रैली में नीतीश कुमार ने जनता परिवार को एकजुट करने की मुहिम चलाकर अपना कर्तव्य निभाया है, नई राजनीति की शुरुआत की है.

मनीष कुमार

25 सितंबर को भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का केंद्र जींद हरियाणा की राजनीति का केंद्र बन गया. सुबह से ही हरियाणा की सड़कों पर इंडियन नेशनल लोकदल के झंडे लहरा रहे थे और समर्थकों में जींद पहुंचने की होड़ लगी थी. यहां से क़रीब 60 किलोमीटर दूर रोहतक से ही सड़कें वाहनों से खचाखच भर चुकी थीं. नेशनल हाइवे नंबर–41 के बाईं और दाईं ओर तथा सड़क के बगल की पगडंडियों पर इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थकों का कारवां चल रहा था. हर जगह जाम और हर जगह नारेबाजी. सड़कों का यह माहौल बता रहा था कि इनमें से कोई भी जींद नहीं पहुंच पाएगा या फिर रैली ख़त्म होने के बाद ही पहुंच पाएंगे. जिन लोगों ने दिमाग दौड़ाया, उन्होंने हाइवे से हटकर कच्ची सड़कों पर खेतों के बीच गाड़ियां उतार दीं और समय पर रैली स्थल पहुंच गए. यह कहना पड़ेगा कि जींद में लाखों की रैली थी, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस सरकार की तरफ़ से कोई इंतजाम नहीं था. इंडियन नेशनल लोकदल बधाई का पात्र है कि वह बिना पुलिस और बिना सरकारी व्यवस्था के लाखों लोगों की रैली को शांतिपूर्वक आयोजित करने में सफल रहा.

रैली स्थल जींद शहर के बाहर सफैदों बाईपास पर था. क़रीब एक किलोमीटर तक लोगों का हुजूम मौजूद था. ज़्यादातर लोगों ने पारंपरिक हरियाणवी साफे के साथ सफेद पोशाक धारण कर रखी थी और हाथ में हरा झंडा लेकर रैली में शामिल होने आए थे. हर तरफ़ सिर्फ़ लोग ही लोग थे. जिन लोगों को लगता था कि स्वर्गीय देवीलाल और चौटाला परिवार को हरियाणा के लोगों ने भुला दिया है या पीछे छोड़ दिया है, उनकी हर दलील को इस रैली ने नि:शब्द कर दिया. इंडियन नेशनल लोकदल की जींद रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित हुई. कई लोगों का मानना है कि हरियाणा में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई. सही मायने में इस रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए. जितने लोग पंडाल के अंदर थे, उससे कहीं ज़्यादा पंडाल के बाहर मौजूद थे. पंडाल भी इतना बड़ा कि उसके बीचोबीच खड़े होकर भी यह बताया नहीं जा सकता कि स्टेज पर कौन–कौन मौजूद है. यह रैली वैसे तो ओमप्रकाश चौटाला ने महान किसान नेता एवं अपने पिता चौधरी देवीलाल के सौवें जन्म दिवस पर उनके सम्मान में आयोजित की थी, लेकिन यह पूरी तरह से चुनावी रैली थी. स्टेज पर इंडियन नेशनल लोकदल के सभी उम्मीदवार मौजूद थे. इस जनसैलाब को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार आईएनएलडी की बनेगी और वह तिहाड़ जेल में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. लेकिन, इस रैली को महज हरियाणा चुनाव की एक रैली कहना गलत होगा, क्योंकि इस रैली से भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय का बीजारोपण हुआ है.

नीतीश कुमार नेता-विपक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी की वजह से बिहार में गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री पद का त्याग किया. वह देश के अकेले नेता हैं, जो मोदी से सार्वजनिक रूप से दो-दो हाथ करते हैं. उनका मोदी विरोध वैचारिक, अव्यक्तिगत और सम्मानित है. अगर भविष्य में जनता परिवार इकट्ठा होता है, तो सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की होगी.

इस रैली में जनता परिवार को एकजुट करने की मुहिम शुरू हुई है. जींद की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि शिवपाल यादव के अलावा कई जाने–माने लोग मौजूद थे. सभी नेताओं ने इस बात पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अवसरवादी राजनीति का युग

संतोष भारतीय

अंतिम रूप से यह मान लेना चाहिए कि विचारधारा का दौर देश की राजनीति से ख़त्म हो चुका है और सत्ता में पहुंचने का कोई भी, कैसा भी, जैसे भी हो, रास्ता तलाशना ही अब एक नया सिद्धांत बन गया है. महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीन दयाल उपाध्याय और इसके आगे अगर कोई नाम लें, तो हम गुरु गोलवरकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं. ये सारे लोग आज की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं. इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए कि देश से विचारधारा के युग की पूर्णत: विदाई हो चुकी है.

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक राय की हैं, चाहे वह राय हिंदुत्व की हो, चाहे वह राय मुसलमानों को लेकर हो, चाहे वह राय विकास के तरीके को लेकर हो. ये दोनों वैचारिक रूप से इसीलिए साथ आई थीं कि एक अलग तरह की राजनीति करेंगे. पर इन दोनों में टूट विचारधारा को लेकर नहीं हुई, बल्कि सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसे सत्ता से हटाकर पूर्णत: अपने दल को सत्ता पर काबिज कराया जा सकता है, मुख्य कारण अलग होने का यही रहा. दूसरी तरफ़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सिद्धांत लगभग एक थे, जिसकी वजह से ये साथ आए. इन सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता थी, ग़रीबों को विकास की दौड़ में शामिल करना था और इन सिद्धांतों में कहीं न कहीं किसान थे, भले ही वे बड़े किसान रहे हों. इनके बीच भी महाराष्ट्र में टूट इसलिए हुई, क्योंकि सिद्धांत की जगह किसके ज़्यादा मंत्री हों और कौन मुख्यमंत्री बने और कौन दूसरे को लंगड़ी मारकर सत्ता के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर ले, यह स्वार्थ हावी हो गया.

दरअसल एक भ्रम पैदा हो गया है. वह भ्रम यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभाओं की सारी सीटें जीत सकती है. दूसरी तरफ़ लोकसभा के बाद बिहार एवं उत्तर प्रदेश के परिणामों ने यह संकेत दिया है कि नरेंद्र मोदी का नाम राज्यों में उतना नहीं चलेगा. तो, शिवसेना यहां पर ज़्यादा सीटें जीत सकती है. कांग्रेस और एनसीपी को भी यह लगा कि लोकसभा चुनाव में पैदा हुआ आवेग समाप्त हो चुका है इसलिए वे ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं और इस भ्रम ने विचार के आधार पर जुड़ी हुई पार्टियों को तोड़ दिया और फिर से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि सत्ता को अपने हाथ में लेना ही एकमात्र सिद्धांत बन गया है.

जनता परिवार एक होने की बात कर रहा है. हरियाणा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही तार्किक ढंग से इस सवाल को खड़ा किया, लेकिन नीतीश कुमार के ही साथी जनता परिवार को एकजुट करने में बहुत उत्साहित नहीं हैं और इस वजह से जनता परिवार 1989 के बाद लगभग हर जगह धीरे-धीरे हाशिये पर चला गया. नीतीश कुमार की इस मसले में तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बिहार में लालू यादव के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसका उन्हें परिणाम देखने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

हरियाणा की जींद रैली से नीतीश की ललकार

पृष्ठ एक का शेष

जोर दिया कि अब सभी को एकजुट होना होगा. नीतीश ने कहा कि जनता दल परिवार के सदस्य यदि एकजुट होंगे, तो देश में नई राजनीति का शंखनाद होगा. शरद यादव ने कहा कि नया भारत बनाने के लिए पुराने साथियों को एक साथ आने की ज़रूरत है. पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कहा कि जनता दल बनवाने में चौधरी देवीलाल का बड़ा योगदान था और आज फिर जनता दल के पुराने परिवार को एकजुट होने की ज़रूरत है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए. मतलब यह कि इस रैली को सिर्फ़ हरियाणा चुनाव के नज़रिये से नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीति की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन तैयार करने की सोची–समझी योजना के रूप में देखना चाहिए.

रैली हरियाणा में हुई. यह रैली हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र इंडियन नेशनल लोकदल ने आयोजित की थी. पार्टी को इसमें जबरदस्त सफलता मिली और इस रैली ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया. लेकिन, इस रैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हीरो बनकर उभरे. वह इस रैली में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में नज़र आए. उनका भाषण सबसे जबरदस्त रहा. उनके भाषण को हरियाणा के लोगों ने खूब सराहा. नरेंद्र मोदी पर किए गए कटाक्षों पर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं. उन्होंने यह कहकर ललकारा कि कहां गया वह 56 इंच का सीना? चीन की फौज हमारी सीमा में घुस आती है और पाकिस्तानी हमारे सिपाहियों पर गोलियां चलाते हैं. नीतीश ने इस रैली में जब यह कहा कि भाजपा अच्छे दिनों का झूठा सपना दिखाकर चुनाव जीती है और लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो माहौल तालियों से गूंज उठा. इन तालियों से अर्थ निकलता है. एक यह कि लोग सचमुच यह मानने लगे हैं कि अच्छे दिन महज एक चुनावी नारा था, जो पूरा नहीं होने वाला है और दूसरी बात यह कि लोग नीतीश कुमार को भाजपा के विरुद्ध संघर्ष करते देखना चाहते हैं. यही वजह है कि नीतीश कुमार ने यह साफ़ कर दिया कि भाजपा को रोकने के लिए जनता परिवार का एकजुट होना ज़रूरी है. नीतीश कुमार का भाषण पूर्ण रूप से राजनीतिक था. उनकी भाषा सरल थी, लेकिन शब्द सटीक और तीखे थे. इसके अलावा उनका पूरा भाषण प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित था. उन्होंने अपने हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्हें सुनकर ऐसा लगा कि अगर भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ देश में कोई सशक्त विपक्ष का नेता है, तो वह नीतीश कुमार ही हैं.

राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक उपस्थिति पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की थी. प्रकाश सिंह बादल की पार्टी भाजपा की सहयोगी है. पंजाब में वह कई

आज के राजनीतिक हालात में एक सशक्त विपक्ष के रूप में देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए जनता परिवार का एकजुट होना ज़रूरी है. कांग्रेस विपक्ष का रोल नहीं निभा सकती है. विपक्ष का उसे अनुभव नहीं है और फिलहाल कांग्रेस हारे हुए व्यक्ति की मानसिकता से ग्रसित है. जनता परिवार को एकजुट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास वैचारिक प्रतिबद्धता हो, दूरदर्शिता हो, आम लोगों के विकास की योजना हो और सबसे ज़रूरी यह कि आपस में एकता हो.

सालों से मिलजुल कर चुनाव लड़ते रहे हैं. उनकी बहू मोदी सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री भी हैं. वैसे पंजाब की ज़मीनी हकीकत यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान अमृतसर से जेटली की हार का ठीकरा भाजपा ने अकाली दल पर फोड़ा था. भाजपा के कई लोग बताते हैं कि यह गठबंधन अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है. प्रकाश सिंह बादल देश के वरिष्ठ राजनेताओं में हैं. वह एक अनुभवी राजनेता हैं. राजनीति की हर चाल वह सोच–समझ कर और भविष्य की संभावनाओं को देखकर चलते हैं. इस हिसाब से जींद की रैली में प्रकाश सिंह बादल का होना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है. यह अकाली दल का भाजपा को संकेत है कि उसके सामने विकल्प खुले हुए हैं. दूसरा संकेत यह है कि अकाली दल को भी यह महसूस होने लगा है कि जिन वादों के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव जीती है, उन्हें पूरा करना संभव नहीं है. इस रैली में मुलायम सिंह यादव को भी आना था, लेकिन बताया गया कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वह नहीं आ सके.

जनता परिवार के एकजुट होने का औचित्य

कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूट चूका है. वह हर राज्य में सिमट रही है. महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एनसीपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस का चुनाव हारना तय माना जा रहा है. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की संख्या क्षेत्रीय दलों से दो–चार सीट ही ज़्यादा है. कांग्रेस पार्टी और भाजपा की नीतियों में अब भेद करना मुश्किल हो गया है. दोनों की आर्थिक नीतियां एक ही हैं. ए के एंटनी ने अपने बयान में लोकसभा चुनाव में हार की वजह कांग्रेस का प्रो–मुस्लिम होना बताया. ए के एंटनी सोनिया गांधी के चहेते सिपहसालार हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों से लग रहा है कि वह एक सॉफ्ट–हिंदुत्व पार्टी में तब्दील होने लगी है. सवाल यह है कि देश में अगर प्रजातंत्र है, तो विपक्ष का महत्व भी है. विपक्ष ऐसा हो, जो वैचारिक और नीतियों के तौर पर भिन्न हो. भारत पिछले 25 सालों से नव–उदारवाद और बाज़ारवाद की गुत्थियों में उलझ कर नुक़सान झेल रहा है. लोग परेशान हो रहे हैं. ज़िंदगी का गुजारा पहले से ज़्यादा कठिन और दु:खदायी होता जा रहा है. जब तक इन नीतियों को बदला नहीं जाएगा, तब तक लोगों की परेशानियों का स्थायी हल नहीं निकाला जा सकता. जनता परिवार में शामिल पार्टियां वैचारिक तौर पर एक जैसी हैं. इनकी विचारधारा किसानों, मज़दूरों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए समर्पित है. ये जयप्रकाश नारायण और लोहिया के समाजवाद की अनुयायी हैं. यह कहना पड़ेगा कि भूतकाल में इन पार्टियों ने अपनी विचारधारा को छोड़कर सिर्फ़ सत्ता की राजनीति की है, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में इन्हें अपनी मूल विचारधारा पर वापस लौटना होगा. यह इनके लिए और देश के लिए भी अनिवार्य है. वर्तमान केंद्र सरकार के सामने आज कोई विपक्ष नहीं है. विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस आज तक खरी नहीं उतरी. अब तो उसके पास पर्याप्त संख्या भी नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव की यह ज़िम्मेदारी है कि वे केंद्र सरकार के सामने एक सशक्त विपक्ष का रोल अदा करें और देश के प्रजातंत्र को बचाएं.

आज के राजनीतिक हालात में एक सशक्त विपक्ष के रूप में देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए जनता परिवार का एकजुट होना ज़रूरी है. कांग्रेस विपक्ष का रोल नहीं निभा सकती है. विपक्ष का उसे अनुभव नहीं है और फिलहाल कांग्रेस हारे हुए व्यक्ति की मानसिकता से ग्रसित है. जनता परिवार को एकजुट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास वैचारिक प्रतिबद्धता हो, दूरदर्शिता हो, आम लोगों के विकास की योजना हो और सबसे ज़रूरी यह कि आपस में एकता हो. साथ ही अलग–अलग पार्टियों के एकजुट होने से प्राकृतिक रूप से पैदा हुए विरोधाभास से निपटने की क्षमता भी होनी चाहिए. विचारधारा के अलावा यह भी ज़रूरी है कि जनता परिवार का एक नेता हो. वह भी सर्वमान्य. सर्वमान्य का मतलब यह नहीं कि सिर्फ़ नेताओं के बीच उसकी मान्यता हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी ग़रीबों, मज़दूरों, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के बीच मान्यता हो और जिस पर भ्रष्टाचार का दाग न हो. ऐसा व्यक्ति, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाजपा की सांप्रदायिकता का मुक़ाबला कर सके. जनता परिवार का एक आर्थिक एजेंडा होना भी ज़रूरी है. उसे महंगाई ख़त्म करने के उपाय बताने होंगे. युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ज़रूरी हैं. जल–जंगल–ज़मीन के मुद्दे पर भी एकजुटता ज़रूरी है. उसे विकास का एक मॉडल पेश करना होगा. युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा और उनके हुनर का इस्तेमाल आने वाली सरकार कैसे करेगी, इसकी रूपरेखा भी सामने रखनी होगी. सांप्रदायिकता से कैसे लड़ना है, इसका ब्लूप्रिंट भी जनता के सामने रखना होगा. 2014 का भारत एक्शन चाहता है, समस्याओं का समाधान चाहता है. एक ऐसा नेता चाहता है, जिसे युवा स्वीकार कर सकें. जींद की रैली में लोगों का जो रिस्पांस था, वह इस बात का सबूत है कि नीतीश नेता–विपक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं. नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की वजह से बिहार में गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री पद का त्याग किया. वह देश के अकेले नेता हैं, जो नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से दो–दो हाथ करते हैं. उनका मोदी विरोध वैचारिक, अव्यक्तिगत और सम्मानित है. अगर भविष्य में जनता परिवार इकट्ठा होता है, तो सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की होगी. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 31
दिल्ली, 06 अक्टूबर–12 अक्टूबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ओम प्रकाश चौटाला जननेता हैं

जींद की रैली की सफलता का सबसे बड़ा कारण ओम प्रकाश चौटाला रहे. 20 महीनों से वह हरियाणा की जनता से दूर थे. यही वजह है कि उनकी पुकार पर हरियाणा के हर ज़िले और कस्बे से लोग जींद पहुंचे. यह रैली हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी. इसमें दस लाख लोग शामिल हुए. कई लोगों ने इस रैली की तुलना चौधरी देवीलाल की ऐतिहासिक रैली से की. ज़्यादातर लोग इस रैली में ओम प्रकाश चौटाला को देखने और सुनने आए थे. इस रैली से यह साबित होता है कि ओम प्रकाश चौटाला न सिर्फ़ हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, बल्कि वह एक मास–लीडर हैं यानी जननेता. उनके पहुंचते ही रैली का माहौल गरमा उठा. इस रैली ने हरियाणा चुनाव का माहौल बदल कर रख दिया है. इस रैली के बाद चौटाला परिवार और इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थकों का हौसला बुलंद हुआ है और वह हरियाणा चुनाव जीतने का प्रबल दावेदार बन गया है. ■

अवसरवादी राजनीति का युग

पृष्ठ एक का शेष

को मिला. दरअसल जनता परिवार का सबसे बड़ा अंतर्विरोध एक–दूसरे को अपने समकक्ष न मानना है. जनता परिवार का हर नेता सबसे बड़ा और सबसे महान है और इन नेताओं ने यह भी साबित किया है कि जब वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ होते हैं, तो उनका सारा इगो, उनका सारा अहम दूर हो जाता है और वे पिछलग्गुओं की तरह काम करते हैं, लेकिन जब वे आपस में बैठते हैं, तो सबसे बड़े सिद्धांतशास्त्री होते हैं, सबसे बड़े नेता हो जाते हैं और देश के सबसे बड़े भावी भाग्यविधाता हो जाते हैं.

इस मानसिकता ने जनता परिवार की विचारधारा को भी तोड़ा है. ग़रीबों के लिए लड़ने के हौसले को भी तोड़ा है और एक सार्थक विपक्ष बनने की संभावनाओं को भी समाप्त किया है. दूसरी तरफ़ अफ़सोस इस बात का है कि जनता परिवार का कोई भी नेता अपनी किसी भी गलती से हुए नुक़सान से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है. अब नीतीश कुमार ने जनता परिवार के एक होने की बात की है और शायद नीतीश कुमार से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि वे कौन लोग हैं, जो जनता परिवार को एक होने नहीं देना चाहते हैं. जनता परिवार को एक करने का दूसरा बड़ा काम मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं. मुलायम सिंह यादव वादा करके भी जींद (हरियाणा) की रैली में नहीं पहुंचे, जहां उनके बाकी साथी पहुंचने वाले थे. शायद मुलायम सिंह यादव की तबीयत ख़राब थी. उन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को जींद भेजा और शिवपाल यादव ने वहां पर एक जोरदार भाषण भी दिया, पर उपस्थिति मुलायम सिंह की आवश्यक थी. शिवपाल यादव ने उस कमी को एक हद तक पूरा किया, पर यदि मुलायम सिंह यादव वहां पहुंच जाते, तो लोगों को विश्वास होता कि जनता परिवार के एक होने का रास्ता निकल रहा है.

क्या हम यह मानें कि अब किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा के आधार पर राजनीति करने की इच्छाशक्ति नहीं बची है या सारे राजनीतिक दल उस जगह पहुंच गए हैं, जहां से किसी भी प्रकार सत्ता में पहुंचने का रास्ता निकलता है. अगर यह बात सत्य है, तो फिर एक दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी मिल सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों सहित जितने भी राजनीतिक दल हैं, वे किसी न किसी दल के साथ गठजोड़ बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी कर सकते हैं. इसमें ख़तरा एक ही है कि इस सब कवायद के बीच जनता कहीं दूर हैं और जनता के लिए होने वाले काम कहीं दूर हैं. इस सारी कवायद में फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉरपोरेट सेक्टर को होने वाला है. दूसरा यह कि इस सारी कवायद को कराने के पीछे कहीं न कहीं देश के बड़े पूंजीपति या बड़े कॉरपोरेट घराने शामिल हैं. कॉरपोरेट घराने नहीं चाहते कि इस देश में 70 प्रतिशत के पास कुछ आए. हालांकि यह खेल बहुत ख़तरनाक है. अगर 70 प्रतिशत विकास की धारा से बाहर रहेगा और उसके पास कुछ नहीं पहुंचेगा, तो फिर इस देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. और, वह अपने अंतिम तार्किक परिणाम पर जा पहुंचेगी, जहां देश में लोकतंत्र के प्रति कम, तानाशाही के प्रति ज़्यादा विश्वास पैदा होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

किसी भी आपदा के समय अकेले कोई संस्था या विभाग चाहकर भी कुछ ख़ास नहीं कर सकता. ऐसे में ज़रूरी है कि आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान प्रणाली बने. सुस्त और नाकारा नौकरशाही की वजह से प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं बन सकी है. केंद्रीय जल आयोग के पास 173 करोड़ रुपये का बजट है और देश भर में उसके पास 5,000 कर्मचारी हैं. पर्याप्त मानव संसाधन होने के बावजूद आयोग कुछ ही राज्यों को बाढ़ का पूर्वानुमान देता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2011 में 250 करोड़ रुपये रिस्पांस रिजर्व के रूप में अलग रखे जाने का प्रस्ताव किया था, ताकि आपदा आने पर राज्य सरकार को मदद दी जा सके.

आपदा प्रबंधन

राहत देने वाला खुद आफत में

अभी जम्मू–कश्मीर में आई बाढ़ ने फिर से अपना भयानक रूप दिखाया. अगर सेना के जवान चौकस न होते और उनकी मदद न मिलती, तो क्या हाल होता, इसका अंदाजा लगाने में भी डर लगता है. सेना ने वायुसेना की मदद से कईयों की जान बचाई. लेकिन इस सबके बीच एनडीएमए कहां था और क्या कर रह था, किसी को नहीं मालूम. इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि फिलहाल इस संस्था के वाइस चेयरमैन शशिधर रेड्डी सहित 5 सदस्यों ने जून 2014 में ही इस्तीफ़ा दे दिया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि किसी भी आपदा के वक्त यह तत्काल लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करेगा. लेकिन, दु:ख की बात यह है कि इस संस्था की हालत इतनी दयनीय है कि खुद इसे अभी राहत पहुंचाए जाने की ज़रूरत है. वर्ष 2004 में सुनामी का कहर बरपा था. इसी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था. इसका मुख्य काम है आपदा के वक्त राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ सरकार का तालमेल बैठाना. इसके अलावा चिकित्सा कार्यों में मदद देना, सूचनाओं का एकत्रीकरण, मृतकों एवं गुमशुदा लोगों के आंकड़े जुटाना और बीमारियों की जानकारी देना. एनडीएमए के पास केंद्र से लेकर ज़िला स्तर तक उचित तरीके से आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने का काम है. जाहिर तौर पर इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन आज यह संस्था क़रीब–क़रीब निष्क्रिय हो चुकी है.

अभी जम्मू–कश्मीर में आई बाढ़ ने फिर से अपना भयानक रूप दिखाया. अगर सेना के जवान चौकस न होते और उनकी मदद न मिलती, तो क्या हाल होता, इसका अंदाजा लगाने में भी डर लगता है. सेना ने वायुसेना की मदद से कईयों की जान बचाई. लेकिन इस सबके बीच एनडीएमए कहां था और क्या कर रह था, किसी को नहीं मालूम. इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि फिलहाल इस संस्था के वाइस चेयरमैन शशिधर रेड्डी सहित 5 सदस्यों ने जून 2014 में ही इस्तीफ़ा दे दिया है. चार महीने बीतने के बाद भी अभी तक इस संस्था में वाइस चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है. ग़ौरतलब है कि एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं. ऐसे में रोजमर्रा का काम तो उपाध्यक्ष ही करता है. चूंकि, शशिधर रेड्डी यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसलिए जब नई सरकार बनी, तो उसके बाद रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया. अब ऐसे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिना उपाध्यक्ष, बिना सदस्य के कोई संस्था क्या और कितना काम कर सकती है? बिना नेतृत्व के यह संस्था कैसे सक्रिय रह सकती है? इस तरह जब कश्मीर में आपदा आई, तो यह संस्था अपना मूल दायित्व भी निभा पाने में अक्षम रही. यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं है.

वैसे एक और अहम तथ्य है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्यों के आपदा प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता. यानी उसकी ज़िम्मेदारी सीधे–सीधे किसी राज्य में आपदा प्रबंधन कार्य में शामिल होना नहीं है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मूल काम है नीतियां बनाना, नीतियों का क्रियान्वयन कराना और उसके लिए जितना आवश्यक हो, संसाधन उपलब्ध कराना.

शशिधर रेड्डी

राज्यों में आपदा प्रबंधन का काम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ज़िला आपदा प्रबंधन प्रशासन का होता है. इसके लिए ज़रूरी है कि आपदा के वक्त राहत कार्य के लिए इन संस्थाओं के पास विशेष किस्म की टीम हो, जो ऐसी आपदा से सफलतापूर्वक निपट सके. कश्मीर मामले में देखें, तो एनडीएमए की निष्क्रियता के साथ–साथ राज्य सरकार की टीम, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ज़िला आपदा प्रबंधन प्रशासन यानी सबके सब असफल साबित हुए.

वर्ष 2004 में सुनामी का कहर बरपा था. इसी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था. इसका मुख्य काम है आपदा के वक्त राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ सरकार का तालमेल बैठाना. इसके अलावा चिकित्सा कार्यों में मदद देना, सूचनाओं का एकत्रीकरण, मृतकों एवं गुमशुदा लोगों के आंकड़े जुटाना और बीमारियों की जानकारी देना.

वर्ष 2012 में जम्मू–कश्मीर सरकार ने त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार ने आकस्मिक आपदा से लड़ने के लिए एक अलग विभाग नहीं बनाया. यह काम क्षेत्र के उपायुक्तों को सौंप दिया गया था. ग़ौरतलब है कि ऐसे अधिकारियों के पास इसके अलावा, पहले से भी और कई अहम काम होते हैं. ध्यान देने की बात है कि 2013 में घाटी में भूकंप आया था, बावजूद इसके आपदा प्रबंधन से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं को लेकर सरकार या एनडीएमए ने कोई मजबूत क़दम नहीं उठाया. वैसे एनडीएमए का यह मानना है कि इस मामले में मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है. एनडीएमए के मुताबिक वह सिर्फ़ सलाह दे सकता है, राज्य प्रशासन को बार–बार प्रक्रिया का पालन करने के लिए कह सकता है. आपदा प्रबंधन के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं. मसलन, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए आपदा संचार नेटवर्क स्थापित करना. ऐसी प्रणाली अगर हमारे पास मौजूद होती, तो कश्मीर में आई बाढ़ के कहर से निपटने में मदद मिलती. इस प्रणाली से संचार सेवा स्थापित करने में काफी मदद मिलती. ग़ौरतलब है कि बाढ़ के दौरान पूरे कश्मीर में संचार व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गई थी. बाढ़ पीडित अपने लोगों से संपर्क भी स्थापित नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह एक बार फिर विभिन्न संस्थाओं के बीच उचित समन्वय की कमी है. एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की विभिन्न मसलों पर असहमति के चलते यह परियोजना धरी की धरी रह गई.

एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये मिलते हैं, लेकिन आज तक यह बाढ़ संभावित क्षेत्रों की ठीक–ठीक पहचान नहीं कर पाया है. उदाहरण के लिए कश्मीर में आई बाढ़ के कहर से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां कभी बाढ़ भी आ सकती है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नक्शों में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जम्मू–कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है. इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राज्य को आकस्मिक बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र माना है. ध्यान देने की बात यह है कि 1992 में भी यहां बाढ़ तबाही मचा चुकी है, उससे भी ज़्यादा बड़ी आपदा यहां 1959 में आई थी, तब भी राज्य में बड़े पैमाने पर जान–माल का नुक़सान हुआ था. एक और गंभीर लापरवाही राज्य सरकार और प्रशासन ने की. श्रीनगर से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर संगम स्टेशन है, जिसका संचालन केंद्रीय जल आयोग करता है. इस स्टेशन ने बता दिया था कि 3 सितंबर को यहां जो जलस्तर 5.7 मीटर था, वह 4 सितंबर को बढ़कर 10.13 मीटर हो गया है.

ग़ौरतलब है कि इस स्तर पर किसी भी सामान्य घर की पहली मंजिल डूब सकती है. केंद्रीय जल आयोग के अन्य दो स्टेशनों ने भी बताया कि 3 एवं 4 सितंबर की दोपहर के बीच जलस्तर में 3 मीटर से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. इन तीनों केंद्रों से तेजी से बढ़ते जलस्तर की ख़बर मिलते ही राज्य प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए था और आने वाली गंभीर आपदा से निबटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था. राज्य आपदा प्रबंधन प्रशासन को सक्रियता दिखानी चाहिए थी. अगर ऐसा होता, तो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने, विशेष सहायता टीमों की तैनाती और राशन की आपूर्ति के लिए उसे पूरे 24 घंटे मिल जाते. दु:ख की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. प्रशासन ने इस चेतावनी को यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि बाढ़ प्रबंधन से इसका क्या लेना–देना. इसे आपदा की स्थिति नहीं माना गया और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस बारे में एक–दूसरे से संपर्क साधने की ज़रूरत ही नहीं समझी. इसके बाद जो हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस धरती की जन्नत एक पखवाड़े से भी अधिक समय तक दोजख में तब्दील रही.

किसी भी आपदा के समय अकेले कोई संस्था या विभाग चाहकर भी कुछ खास नहीं कर सकता. ऐसे में ज़रूरी है कि आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान प्रणाली बने. सुस्त और नाकारा नौकरशाही की वजह से प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं बन सकी है. केंद्रीय जल आयोग के पास 173 करोड़ रुपये का बजट है और देश भर में उसके पास 5,000 कर्मचारी हैं. पर्याप्त मानव संसाधन होने के बावजूद आयोग कुछ ही राज्यों को बाढ़ का पूर्वानुमान देता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2011 में 250 करोड़ रुपये रिस्पांस रिजर्व के रूप में अलग रखे जाने का प्रस्ताव किया था, ताकि आपदा आने पर राज्य सरकार को मदद दी जा सके, लेकिन वित्त मंत्रालय ने आपदा कोष आवंटित करने के प्रस्ताव को हर बार नामंजूर कर दिया. इससे भी अहम था एनडीएमए के तहत आपदा के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय ले सकने में सक्षम एकीकृत कमान प्रणाली का गठन. कृषि, रक्षा एवं गृह मंत्रालय को इस कमान का हिस्सा बनना था. इन मंत्रालयों के अधिकारियों ने रूस की इंसीडेंट रिस्पांस प्रणाली को समझने के लिए वहां का दौरा भी किया था. इसके बावजूद आज तक ऐसी कोई प्रणाली तैयार नहीं हो सकी है.

कश्मीर में हुई भारी तबाही भारत की बदहाल और चरमराती आपदा प्रबंधन प्रणाली का ताजा उदाहरण है. उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया गया. और, एक साल बाद कश्मीर में वही कहानी दोहराई गई. विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियां आपस में संवाद स्थापित करने में असफल रहीं. उत्तराखंड की तरह जम्मू–कश्मीर में हुए जान–माल के नुक़सान ने यह साफ़ कर दिया है कि देश अभी ऐसी आपदाओं से निपटने में, ज़िला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, न तो तैयार है और न सक्षम. एनडीएमए और ज़्यादातर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निरर्थक साबित हुए हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि उनके पुनर्गठन पर फिर से ध्यान दिया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> सैलाब आने के दो सप्ताह बाद, 20 सितंबर को सोशल मीडिया द्वारा एक ख़बर यह आई कि पुलवामा के 43 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और वहां फंसे लोगों को अति शीघ्र सहायता की ज़रूरत है. हालांकि कुछ स्थानीय युवक उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधनों के अभाव के चलते वे भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे. कुछ गांव तो ऐसे भी थे, जहां केवल हेलिकॉप्टरों द्वारा ही पहुंचा जा सकता था. हो सकता है कि इस ख़बर के फैलने के बाद सेना वहां पहुंची हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में पूरी तरह असफल रही है.

आपदा के बाद कश्मीर

> *पांच सितंबर की मध्य रात्रि श्रीनगर में पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा. उस समय अधिकतर लोग अपने घरों में सो रहे थे. भारी बारिश और पानी के तेज़ बहाव से पैदा होने वाली आवाज़ ने जब उन्हें नींद से जगाया, तो यह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि पानी उनके घरों में अंदर तक घुस आया है. उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह पानी 12-14 फिट तक भर जाएगा. वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ़ भागे. जो लोग तीन-चार मंज़िला इमारतों में रहते थे, वे अपने घर की ऊपरी मंज़िलों की तरफ़ भागे.*

डॉ. क़मर तबरेज़

सड़कों, घरों एवं गलियों में 12 फिट तक भरा हुआ पानी. पानी में बहती हुई कार एवं गैस के सिलेंडर. घर की छतों पर भूखे-प्यासे, सरकारी मदद का इंतज़ार करते लोग. पेड़ों पर लटकी और पानी में बहती इंसानों एवं जानवरों की लाशें. हवाई जहाज़ के इंतज़ार में एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़. बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूबे हुए शहर एवं गांव. अपने प्रियजनों की तलाश में हैरान-परेशान लोग. यह था वह मंज़र, जो छह सितंबर को कश्मीर में देखने को मिला. लगातार चार दिनों तक होने वाली बारिश और उससे आने वाली बाढ़ ने लोगों को बदहाल कर दिया था. सवाल यह है कि जब जम्मू के बाढ़ नियंत्रण विभाग (फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट) ने 2010 में ही आशंका जता दी थी कि श्रीनगर में भारी बारिश से कभी भी सैलाब आ सकता है, तब भी राज्य सरकार ने बचाव की कोई तैयारी क्यों नहीं की?

लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब पूरे राज्य में चार सितंबर से लगातार बारिश हो रही थी और नदियों में जलस्तर तेज़ी से बढ़ने लगा था, तब भी सरकार क्यों नहीं चेती कि इससे कभी भी भयावह सैलाब आ सकता है? सरकार ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को कोई चेतावनी क्यों नहीं दी और समय रहते उन्हें वहां से किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? उमर अब्दुल्ला सरकार ने अगर थोड़ी भी सक्रियता दिखाई होती, तो आज शायद तबाही का यह मंज़र हमें देखने को नहीं मिलता. सैलाब में फंसे लोग बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री श्यामलाल शर्मा को ढूंढते रहे, लेकिन वह अपने मंत्रालय के पूरे अमले के साथ ग़ायब रहे. यही हाल सरकार के दीगर मंत्रियों एवं सचिवों का भी रहा. जनता त्राहि-त्राहि करती रही और मुख्यमंत्री यह कहते रहे कि बाढ़ ने पूरी सरकारी मशीनरी को ही प्रभावित कर दिया है, सरकार के लोग ख़ुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं. क्या जनता ने इसीलिए सरकार को चुना था कि वह उसे मुसीबत की घड़ी में छोड़कर भाग जाएगी?

पांच सितंबर की मध्य रात्रि श्रीनगर में पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा. उस समय अधिकतर लोग अपने घरों में सो रहे थे. भारी बारिश और पानी के तेज़ बहाव से पैदा होने वाली आवाज़ ने जब उन्हें नींद से जगाया, तो यह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि पानी उनके घरों में अंदर तक घुस आया है. उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह पानी 12-14 फिट तक भर जाएगा. वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ़ भागे. जो लोग तीन-चार मंज़िला इमारतों में रहते थे, वे अपने घर की ऊपरी मंज़िलों की तरफ़ भागे. अगले दिन जब उजाला हुआ, तो चारों तरफ़ पानी ही पानी था. अधिकतर मकान डूब चुके थे, सड़कों का नामो-निशान नहीं था. अगले चार-पांच दिनों तक लोग वहीं फंसे रहे. जब तक उनके पास खाने-पीने का सामान था, उसे खाते-पीते रहे, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो सामने खड़ी मौत ने उन्हें डराना शुरू कर दिया. वह बेसब्री से सरकारी मदद का इंतज़ार करने लगे. सरकारी मदद तो नहीं पहुंची, अलबत्ता कुछ दिनों के बाद सेना और आसपास के लोग फरिश्तों की शक्ल में उन्हें बचाने के लिए वहां ज़रूर पहुंच गए, लेकिन ऐसे ख़ुश नसीब लोगों की संख्या कम ही थी.

ग़रीब, मज़दूर एवं कम हैसियत वाले लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई. वे न तो अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके और न अपने बाल-बच्चों या अपने मवेशियों की. कुछ हिम्मत वाले लोग ऐसे ज़रूर थे, जो 15-20 किलोमीटर पानी में चलकर किसी सूखे स्थान तक पहुंचने में सफल तो हुए, लेकिन हफ़्तों तक उन्हें न तो खाना मिला और न पानी. अब बहुत धीमी रफ़्तार से उन तक सरकारी सहायता पहुंच रही है, जो उनके लिए काफ़ी नहीं हैं. लोग भूखे-प्यासे तो हैं ही, कई रातों से सोए भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जिससे उनके बीमार पड़ने का ख़तरा बढ़ गया है. दूसरी तरफ़, बाढ़ का पानी अधिकतर इलाक़ों में अब भी ठहरा हुआ है, जिससे महामारी फैल सकती है. अस्पतालों की हालत भी ठीक नहीं है, वहां भी पानी भरा हुआ है और बिजली न होने से बहुत-सी मशीनें ख़राब हो चुकी हैं.

चौथी दुनिया ने जब कश्मीर के कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, तो पता चला कि जिन जगहों पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, वहां तो कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची, लेकिन जहां कोई नुक़सान नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है, वहां के लोगों को मदद ज़रूर मिल रही है. जो लोग सैलाब से प्रभावित नहीं हुए हैं, वे भी ख़ूब मज़े लूट रहे हैं, क्योंकि सरकार उन तक राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. सरकार के इस रवैये से बाढ़ से प्रभावित लोगों में काफ़ी गुस्सा है. स्थानीय लोगों को यह भी शिकायत है कि शुरू में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को बाहर निकाला गया, जो पर्यटन के लिए यहां आए थे या फिर जो मंत्रियों एवं अधिकारियों या रसूखदारों के रिश्तेदार थे. आम जनता को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया. लोग कहते हैं कि अगर उनके अपने रिश्तेदारों या दूसरे स्थानीय लोगों ने उनकी मदद न की होती, तो आज वे जीवित न बच पाते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति प्रोफ़ेसर मोहम्मद असलम अपनी आपबीती बयान करते हुए कहते हैं कि छह सितंबर की रात दो बजे अगर उनके मित्र अपने बेटे के साथ वहां पहुंच कर एक सरकारी गेस्ट हाउस से उन्हें बाहर निकालने में पांच मिनट की देरी कर देते, तो आज शायद वे भी ज़िंदा न होते, क्योंकि उनके वहां से निकलने के पांच मिनट बाद गेस्ट हाउस पानी में पूरी तरह डूब गया था. प्रोफ़ेसर असलम अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दो सितंबर को श्रीनगर पहुंचे थे. वे सात सितंबर को दिल्ली वापस लौटने वाले थे, लेकिन तभी छह सितंबर को आई बाढ़ में फंस गए और बड़ी मुश्किल से 13 सितंबर को दिल्ली पहुंच पाए. उस रात जब उन्होंने ख़ुद को सैलाब में घिरा हुआ पाया, तो अपने एक मित्र को फ़ोन करके मदद मांगी. प्रोफ़ेसर असलम ख़ुशक़िस्मत थे कि उनके दोस्त अपने बेटे के साथ, जो एक पुलिस अधिकारी है, गाड़ी लेकर उन्हें बचाने वहां पहुंच गए. लेकिन, कश्मीर में ऐसे ख़ुशक़िस्मत लोग कम ही थे, जो समय पर किसी प्रकार की सहायता पाने में सफ़ल रहे.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफ़ेसर अमिताभ मट्टू भी बाढ़ के समय अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ श्रीनगर के गोगजी बाग़ में स्थित अपने घर में फंसे हुए थे. प्रोफ़ेसर मट्टू बताते हैं कि 6 सितंबर की दोपहर में जब वह अपने घर से निकल कर डल झील जाने वाली बुलीवर्ड सड़क पर गए, तो यह देखकर डर गए कि झेलम नदी में पूरी तरह भर चुका पानी अब बाहर निकलने ही वाला है. यह देखकर वह तेज़ी से अपने घर की तरफ़ भागे. वह इस बात पर हैरान थे कि सरकार की तरफ़ से कोई चेतावनी नहीं दी जा रही है, जबकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. प्रोफ़ेसर मट्टू बताते हैं कि सात सितंबर को गोगजी बाग़ पूरी तरह पानी में डूब चुका था. वह सवाल करते हैं कि श्रीनगर में माहिर तैराकों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें बचाव कार्य में क्यों नहीं लगाया? वह कहते हैं कि आठ सितंबर को उनकी और उनके माता-पिता की जान उस वक़्त बची, जब कुछ सैनिक नाव (बोट) लेकर गोगजी बाग़ पहुंचे और सबको रामबाग़ में एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे. प्रोफ़ेसर मट्टू यह देखकर हैरान थे कि वहां एक भी पुलिसकर्मी या कोई सरकारी कर्मचारी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था. हालांकि, रामबाग़ पुलिस स्टेशन के अंदर तब तक पानी नहीं घुसा था और पुलिस स्टेशन में कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

सैलाब आने के दो सप्ताह बाद, 20 सितंबर को सोशल मीडिया द्वारा एक ख़बर यह आई कि पुलवामा के 43 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और वहां फंसे लोगों को अति शीघ्र सहायता की ज़रूरत है. हालांकि कुछ स्थानीय युवक उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधनों के अभाव के चलते वे भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे. कुछ गांव तो ऐसे भी थे, जहां केवल हेलिकॉप्टरों द्वारा ही पहुंचा जा सकता था. हो सकता है कि इस ख़बर के फैलने के बाद सेना वहां पहुंची हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में पूरी तरह असफल रही है. अच्छी बात यह है कि अब कश्मीर के अधिकतर इलाक़ों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है. इस समय राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो लोग इस प्राकृतिक आपदा से किसी न किसी प्रकार बच गए हैं, उनका पुनर्वास जल्दी कैसे हो, क्योंकि एक महीने बाद ही सर्दी का मौसम आ जाएगा. अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए जल्द ही एक अदद छत का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो बर्फ़ पड़ने के दिनों में उनकी जान बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा. इसके साथ ही तहस-नहस हो चुके अस्पतालों को भी जल्दी ठीक करना ज़रूरी है. इन अस्पतालों में अधिकतर मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, जिन्हें ठीक कराने या फिर नई मशीनें लगवाने की सख्त ज़रूरत है. मुसीबत की इस घड़ी में पूरे देश से कश्मीरियों के लिए सहायता सामग्री पहुंच रही है. ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी ज़मीन पर नज़र आएं और ज़रूरतमंदों तक उक्त सामग्री पहुंचाने में तेजी लाएं. हो सकता है कि उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़े, लेकिन अगर वे इससे घबराएंगे, तो कभी भी किसी पीड़ित की सहायता नहीं कर पाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर ख़बर अब आपके Android फ़ोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उपचुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा की हार के चलते पहले से ही टीम तीरथ से नाराज़ चल रहे हैं. इस वजह से उन्होंने टीम तीरथ को नई दिल्ली में मिलने का समय तक नहीं दिया. अब ड्राफ्ट प्रकरण ने पार्टी के अंदर दिल्ली से लेकर देवभूमि तक भूचाल खड़ा कर दिया है. टीम तीरथ विरोधी लॉबी ने ड्राफ्ट मामले को लेकर भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी है कि खास रणनीति के तहत ही पार्टी के एक ज़िम्मेदार पदाधिकारी ने शहीदों के आश्रितों तक यह धनराशि पहुंचाने की कोशिश नहीं की.

झारखंड

रालोसपा और लोजपा को कम मत आंकिए

सरोज सिंह

झारखंड में हर पार्टी अपने-अपने हिसाब से समीकरण बनाने में जुट गई है. कांग्रेस ने तो साफ़ कर दिया है कि वह बिहार की तरह झारखंड में भी महा-गठबंधन की कवायद का समर्थन करेगी, ताकि भाजपा को बढ़त लेने से रोका जा सके. इस दिशा में राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अंदरखाने तैयारी भी शुरू कर दी है. दूसरी तरफ़ भाजपा यहां पूरे दम-खम के साथ चुनावी जंग में उतरने और फतह की रणनीति बनाने में जुट गई है. लेकिन, जहां तक सहयोगी दलों को साथ लेने का सवाल है, तो उसे लेकर पार्टी में फिलहाल कोई एक राय नहीं बन पाई है. गठबंधन को लेकर भाजपा में दो धाराएं हैं. एक धारा का मानना है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और जनता परिवर्तन करने के लिए बेताब है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी का जादू तो चलेगा ही. लेकिन, भाजपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जो हाल में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित हैं. उनका मानना है कि सहयोगी दलों को साथ लेने में ही भलाई है और सरकार बनाने के लिए भाजपा को अपना दिल बड़ा करना ही होगा. बिहार में भाजपा की सहयोगी रालोसपा एवं लोजपा को पूरा भरोसा है कि झारखंड में भी भाजपा उनकी ताकत और भावना का पूरा सम्मान करेगी.

ग़ौरतलब है कि मौजूदा झारखंड विधानसभा में लोजपा एवं रालोसपा का कोई विधायक नहीं हैं, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को आशातीत सफलता मिली. झारखंड में भी इस गठबंधन का पूरा असर पड़ा और बिहार से सटी सीटों पर लोजपा एवं रालोसपा के समर्थकों ने सक्रिय होकर भाजपा का साथ दिया. मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 18 विधायक हैं. 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के 18, कांग्रेस के 13, झाविमो के 11, आजसू के छह, राजद के पांच एवं जदयू के दो विधायक जीतकर आए थे. यहां यह समझना ज़रूरी है कि आख़िर भाजपा को लोजपा एवं रालोसपा का साथ क्यों चाहिए? सीधा कारण यह है कि बिहार से सटे झारखंड के ज़िलों में कुशवाहा और पासवान बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में हैं, जो राजनीतिक तौर पर भी हमेशा सक्रिय रहे हैं. झारखंड विधानसभा की 18 सीटों पर कुशवाहा और पासवान बिरादरी के वोट किसी की हार एवं जीत को तय करते हैं. यही वजह है कि भाजपा का एक खेमा चाहता है कि रामविलास पासवान एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ तालमेल करके यहां चुनाव लड़ा जाए, ताकि इन 18 सीटों पर जीत हासिल की जा सके. इन सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा. यहां पासवान एवं कुशवाहा एक बड़ी राजनीतिक ताकत हैं.

झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह एवं देवघर ज़िले के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो बिहार से सटे हुए हैं और बिहार की राजनीति यहां पूरी तरह से प्रभावी है. इसी का परिणाम था कि पूर्व के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान

झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक विधायक बिहार विधानसभा में पहुंचा था. लालू यादव के नेतृत्व वाले राजद के टिकट पर देवघर से विधायक बने सुरेश पासवान झारखंड में कैबिनेट मंत्री हैं. इसके अलावा कोडरमा की विधायक अन्नपूर्णा देवी, जो कैबिनेट मंत्री पद पर आसीन हैं, राजद से ही चुनाव जीतती आ रही हैं. झारखंड में रालोसपा के लिए भी संभावनाएं कम नहीं हैं. कोयरी-कुशवाहा जाति के मतदाताओं की अच्छी-खासी तादाद झारखंड में है, जो पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुदेश महतो की पार्टी आजसू का साथ देती रही है. अगर उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा-सा भी समय झारखंड को देते हैं, तो वह कई नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकते हैं.

लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जो बिहार की सीमा से सटे हैं और जहां बिहार की तर्ज पर जाति आधारित राजनीति चलती आई है. झारखंड में पासवानों की संख्या भी काफी है. ऐसे में रामविलास पासवान एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का तालमेल भाजपा के साथ कायम रहता है, तो उनके विधायक भी आने वाले समय में झारखंड विधानसभा में देखे जा सकते हैं. फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे राजनीतिक दलों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य में रालोसपा और लोजपा का संगठन अभी तक बहुत मजबूत आकार नहीं ले सका है. इसलिए रालोसपा और लोजपा के शीर्ष नेता पूरे झारखंड की बजाय उन्हीं 18 सीटों पर फोकस करना चाहते हैं, जहां उनका मजबूत आधार है. जानकारों के अनुसार, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उनका भाजपा के साथ सीटों का तालमेल हो और मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए. अगर किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया, तो यह भी तय है कि रालोसपा और लोजपा यहां अपने बलबूते चुनाव मैदान में कूदेंगी और ऐसे में नुक़सान भाजपा को हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुदेश महतो ने किया शक्ति प्रदर्शन

मंगलानंद

आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने रांची के प्रभात तारा मैदान से झारखंड में सक्रिय सभी दलों के नेताओं को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया. इस अवसर पर पूरे प्रदेश से आए आजसू के 50 हज़ार से अधिक स्वयंसेवकों ने राज्य के विकास के लिए शपथ भी ली. सुदेश महतो ने इस शपथ ग्रहण के बहाने राज्य की बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर देने की चुनौती दे दी है. पार्टी के कार्यकर्ता-समर्थक भारी बारिश होने के बावजूद मैदान में डटे रहे. रैली को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि गांव के विकास के बगैर राज्य और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है. आजसू ने 50 हज़ार स्वयंसेवक तैयार किए हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं. उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर पार्टी का विजन ग्रामीणों तक पहुंचाएं और ऐसे काम करें, जिनसे गांव के विकास के साथ-साथ राज्य का नाम विश्व स्तर पर लिया जाए. महतो ने कहा कि सही नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता, बल्कि वह होता है, जो जनता के समक्ष सही बातें पहुंचा सके. महतो ने कहा कि सभी दलों के नेता गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आजसू गांव जाने की तैयारी में जुटी हुई है. हमारी पार्टी ऐसा काम करेगी, जिससे यहां की महिलाओं को अधिकार और युवाओं को रोज़गार मिल सके. महतो ने कहा कि जिस सपने को लेकर राज्य के तमाम महान अगुवाओं ने बलिदान दिया, उसे साकार करने के लिए आजसू वचनबद्ध है. पार्टी प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि सिल्ली और रामगढ़ की तर्ज पर पूरे झारखंड का विकास किया जाएगा. विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य के विकास के लिए किसने क्या किया, इस पर चर्चा न करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रखंड, पंचायत एवं ज़िला स्तर पर काम करना होगा. विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का काम किया जाएगा. विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि आजसू के 50 हज़ार स्वयंसेवक राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए काम करेंगे. विधायक कमल किशोर भगत ने कहा कि सुदेश महतो के नेतृत्व में ही राज्य का कल्याण हो सकता है. विधायक एवं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पार्टी के स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभियान शुरू किया जा रहा है, उसका लाभ आने वाले समय में राज्य की जनता को मिलेगा. ■

उत्तराखंड

कहां गए 15 लाख के ड्राफ्ट?

राजकुमार शर्मा

सितंबर, 2013 में भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में आए 15 लाख यानी पांच-पांच लाख के तीन ड्राफ्ट जहां पहुंचने थे, वहां नहीं पहुंचे. उक्त ड्राफ्ट आईटीबीपी के तीन शहीद जवानों के आश्रितों तक पहुंचने थे. इस खुलासे के बाद यह प्रकरण तीरथ सिंह रावत और उनकी टीम के लिए गले की फांस बन गया है. प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी कि शहीद जवानों के आश्रितों को अब तक पांच-पांच लाख रुपये की उक्त सहायता राशि नहीं मिल सकी है, जिसे पाने के लिए वे दर-दर भटकते रहे, लेकिन सबने उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी.

ग़ौरतलब है कि सवा साल पहले प्रदेश में आई भीषण आपदा के दौरान आईटीबीपी के तीन जवान शहीद हो गए थे. भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शहीदों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये पार्टी फंड से देने की घोषणा की थी. यह धनराशि उनकी ओर से उत्तराखंड भाजपा कार्यालय को ड्राफ्ट के रूप में समय पर भेज भी दी गई, लेकिन दु:ख की बात यह है कि उक्त ड्राफ्ट शहीदों के आश्रितों को आज तक नहीं मिल सके. जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसे शहीदों का अपमान मानते हुए पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उत्तराखंड भाजपा द्वारा बरती गई लापरवाही के बारे में एक नोट भी लिखा है. शाह ने तत्काल टीम तीरथ से इस बावत रिपोर्ट मांगी है कि आख़िर किस वजह से भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से भेजे गए 15 लाख रुपये अब तक शहीदों के आश्रितों तक नहीं पहुंचाए गए.

भाजपा के एक अन्य गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि टीम तीरथ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, वह ड्राफ्ट प्रकरण पर निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे प्रकरण में टीम तीरथ ही शामिल है. लिहाजा यदि वह इस मामले की जांच-पड़ताल करेगी, तो वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उपचुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा की हार के चलते पहले से ही टीम तीरथ से नाराज़ चल रहे हैं. इस वजह से उन्होंने टीम तीरथ को नई दिल्ली में मिलने का समय तक नहीं दिया. अब ड्राफ्ट प्रकरण ने पार्टी के अंदर दिल्ली से लेकर देवभूमि तक भूचाल खड़ा कर दिया है. टीम तीरथ विरोधी लॉबी ने ड्राफ्ट मामले को लेकर भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी है कि खास रणनीति के तहत ही पार्टी के एक ज़िम्मेदार पदाधिकारी ने शहीदों के आश्रितों तक यह धनराशि पहुंचाने की कोशिश नहीं की. यह लॉबी सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की मांग कर रही है. भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शहीदों के आश्रितों तक ड्राफ्ट न पहुंचना एक बहुत बड़ी गलती है. प्रदेश भाजपा के एक गुट ने ड्राफ्ट प्रकरण की जांच केंद्रीय स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कराने की मांग की है.

भाजपा के एक अन्य गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि टीम तीरथ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, वह ड्राफ्ट प्रकरण पर निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे प्रकरण में टीम तीरथ ही शामिल है. लिहाजा यदि वह इस मामले की जांच-पड़ताल करेगी, तो वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी. मालूम हो कि इस प्रकरण के कई साल भी पहले पार्टी फंड में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए प्रदेश स्तर पर एक टीम गठित की गई थी, लेकिन फंड में हुई उक्त गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी. इसलिए अच्छा यह होगा कि ड्राफ्ट प्रकरण की जांच-पड़ताल केंद्रीय नेताओं की टीम करे. बताते हैं कि संघ ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया है. संघ का स्पष्ट कहना है कि भाजपा सवा साल पहले प्रदेश में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेरती और उस पर हमले करती रही है. ऐसे में टीम तीरथ की ओर से बरती गई इस लापरवाही से पूरे प्रदेश में पार्टी के ख़िलाफ़ एक गलत संदेश गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वह पूरी तरह सच है. भारतीय मुसलमानों ने हमेशा देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं. भारत के विकास के लिए मुसलमानों ने उल्लेखनीय योगदान किया है. समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं पत्रकार शाहिद सिद्दीकी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान सत्य वचन है. उन्होंने यह कहकर मुसलमानों के दिलों को छू लिया कि भारत का मुसलमान भारत के लिए जीता है और भारत के लिए मरेगा.

वरुण के नाम पर इतनी चिल्लपों क्यों!

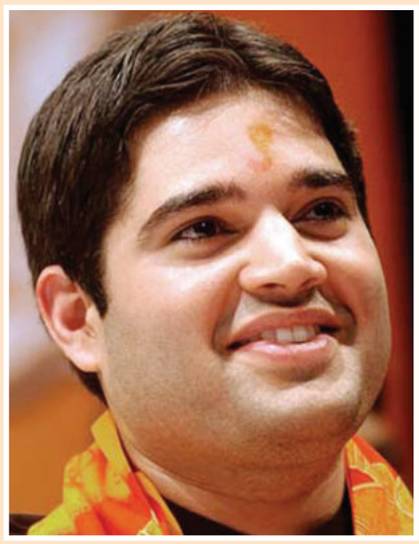

प्रभात रंजन दीन

भारतीय जनता पार्टी खुद यह तय नहीं कर पा रही कि उसे गांधी के नाम से एलर्जी है या घबराहट. वरुण गांधी का नाम सामने आते ही भाजपा के कुछ खास वरिष्ठ नेताओं में कुछ अधिक ही बेचैनी दिखने लगती है. लोकसभा चुनाव का पूरा श्रेय लूटने वाले नेताओं को वे नेता कतई नहीं सोहा रहे, जो अपने बूते चुनाव जीतकर आए और श्रेय का गणित समझते हैं तथा ऐसे तत्वों की ज़मीनी राजनीति की दीर्घजीविता का भी उन्हें एहसास है. लिहाजा, वरुण की संभावना पर कुल्हाड़ी चलाने का काम तेजी से किया जा रहा है. पार्टी का भविष्य संवारने में कथित तौर पर सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस काम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं. ऐसा न होता, तो वह अपने वादे से न मुकरते और संगठन में वरुण को कोई न कोई ज़िम्मेदारी ज़रूर देते. स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी की इच्छा और सहमति के बगैर वह एक फूंक तक नहीं सरकाते. साफ़ है कि वरुण गांधी भाजपा के मौजूदा झंडाबरदारों के लिए डर का फैक्टर बने हुए हैं.

वरुण गांधी की मां मेनका गांधी अगर अपने बेटे के लिए कुछ बोलें, तो पार्टी में चिल्लपों शुरू हो जाती है. लेकिन वहीं अन्य नेता अगर अपने-अपने बेटों का राजनीतिक करियर संवारने के लिए नैतिकता ताख पर रख दें, तो चुप्पी सधी रहती है. निवर्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपने बेटे लिए बोलें, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने बेटे को सांसद बनवा लें और मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग करें, वरिष्ठ नेता लालजी टंडन अपने बेटे को विधायक बनवाने के लिए जोड़-तोड़ करें, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने बेटे को सांसद के साथ-साथ मंत्री बनवाने के लिए सिफारिशें कराएं, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा अपने बेटे को सांसद बनवाने के लिए शहादत दे दें, तो कोई कुछ न बोले. लेकिन, मेनका गांधी ने अपने बेटे को उपयुक्त मौक़ा न दिए जाने पर कुछ कह दिया, तो पार्टी में शोर मचने लगता है. नेतृत्व के कुछ खास गुर्गे, जो सड़क से संसद तक अवसरवादी मौन साधे रहते हैं, ऐसे मौक़ों पर जन-आंदोलन चलाने की धमकी देने का हास्य पैदा करने लगते हैं.

ताजा उदाहरण वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के क़रीब इलाहाबाद में देखने को मिला. सूत्रधारों के इशारे पर इलाहाबाद के स्थानीय नेता श्याम चरण गुप्ता मेनका गांधी एवं वरुण गांधी पर ऐसे बरसने लगे, जैसे उन्हें राष्ट्रीय मान्यता मिली हो. उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद वरुण गांधी को पार्टी में मुख्य भूमिका दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद से भाजपा सांसद श्याम चरण गुप्ता ने मेनका गांधी के बेटे के ख़िलाफ़ इस तरह बोलना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें ततैये ने काट खाया हो. उन्होंने कहा कि यूपी में मां-बेटे खुद ही एक-दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. फिर वह पार्टी नेतृत्व के मनोवैज्ञानिक भय पर आ गए और बोले, बड़ी मुश्किल से देश को गांधी-नेहरू से मुक्ति मिली है. पार्टी में फिर से कोई गांधी नाम आए, यह नहीं होने दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि उपचुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद राज्य के कई इलाकों में वरुण गांधी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिनका कहना था कि उपचुनाव में पार्टी की इस दुर्गति के लिए जुझारू नेता वरुण गांधी को हाशिये पर रखा जाना भी एक मुख्य वजह है. कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान तक सौंपे जाने की मांग की.

तभी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस ज़रूरत पर जोर दिया कि वरुण गांधी को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए. मेनका ने भाजपा की सांगठनिक टीम में वरुण को न रखे जाने पर आपत्ति जताई. मेनका पहले यह भी कह चुकी हैं कि उनके बेटे को यूपी के मुख्यमंत्री के बतौर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए. मेनका के बयान पर चिहुंकने वाले नेताओं को प्रदेश के कई नेताओं के खुले बयानों का तात्पर्य समझ में नहीं आता, जो यह बार-बार कहते रहे हैं कि वरुण गांधी राज्य में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं. बिजनौर से भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने भी कहा कि जबसे राजनाथ सिंह केंद्र में गए हैं, यूपी में हमारे पास कोई चेहरा नहीं है. प्रदेश में पार्टी के संभावनाशील नेताओं की कमी है और वरुण गांधी जैसे चेहरे इस कमी को पूरा कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा उप-चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद हर तरफ़ यह सवाल उठ रहा है कि अब पार्टी नेतृत्व क्या क़दम उठाएगा? पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जिन्हें शाह-दल ने हाशिये पर रख छोड़ा है, ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्री एवं पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी ने अगर वरुण को आगे लाने की बात कह दी, तो क्या गलत कहा! मेनका ने वरुण गांधी को राज्य के हित के लिए प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी, तो क्या गलत कहा और उनके इस बयान से पार्टी नेतृत्व ने किनारा क्यों कर लिया!

ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के जबड़े में हाथ डालकर 8 सीटें छीन लीं. उक्त सभी 11 सीटें पहले भाजपा के पास थीं. लोकसभा चुनाव का श्रेय लूटने वाले नेता उपचुनाव की श्रेयहीनता का बोझ उठाने से भाग रहे हैं. इसी नेतृत्व ने उपचुनाव में प्रचार के लिए किसी भी राष्ट्रीय नेता को यूपी आने से मना कर दिया था. भाजपा के जितने भी प्रदेश स्तरीय नेता मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में हैं या हो सकते हैं, उनमें सबसे करिश्माई चेहरा वरुण गांधी का है. हालांकि भावी मुख्यमंत्रियों की कतार में भाजपा कार्यकर्ता मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और फायर ब्रांड सांसद योगी आदित्य नाथ के नाम भी लेते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे ने इन नेताओं के चेहरे धूमिल कर दिए हैं.

बहरहाल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सांगठनिक टीम में वरुण गांधी को मौक़ा न दिए जाने को लेकर जो वादाख़िलाफ़ी हुई, उसकी चर्चा भी कम रोचक नहीं है. 15 अगस्त की रात अमित शाह ने वरुण गांधी को फोन करके कहा कि वह उत्तर प्रदेश को ही राजनीति का केंद्र बिंदु बना लें. अमित शाह ने वरुण से यह भी पूछा था कि उनके परिवार के लोगों ने देश की राजनीति की है. ऐसे में क्या वह यूपी की राजनीति में आगे जाना चाहेंगे? इस पर वरुण ने अपनी सहमति दे दी. और, जब टीम का ऐलान हुआ, तो उसमें राष्ट्रीय महासचिव वाले खाने से वरुण गांधी का नाम गायब था. पार्टी के कुछ नेता बताते हैं कि इसके पहले भी अमित शाह ने वरुण गांधी को दिल्ली बुलाकर इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी. स्वाभाविक है कि इसके बाद अमित शाह ने इस पर नरेंद्र मोदी से भी बात की होगी. यह भी स्वाभाविक है कि उसके बाद ही वरुण गांधी का पत्ता काटने का निर्णय लिया गया होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष शामिल किए गए. पार्टी के संविधान के अनुसार दो और महासचिव बनाए जा सकते थे, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में महासचिव रहे वरुण गांधी का नाम काट दिया गया. भाजपा नेताओं की नीयत और नियति साफ़ है... ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री का बयान

मुसलमान खुश, नेता मायूस

मुसलमानों को राष्ट्रभक्त कह देना सियासतदानों को अखर गया, लेकिन इस्लाम धर्म के अलमबरदारों ने इसकी जमकर सराहना की. उत्तर प्रदेश इस मामले में अव्वल रहा, क्योंकि जहां सांप्रदायिक तनाव फैलाकर वोट बटोरने का कुचक्र रचा जाता हो, वहां प्रधानमंत्री के बयान को सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, तो यह पहल उल्लेखनीय है. उत्तर प्रदेश के इस्लामी प्रमुखों के रुख ने सियासतदानों को करारी सीख दी है. जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी की बात अलग है, क्योंकि वह हमेशा से अपने अलग नकारात्मक राग के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अपने ही धर्म में कोई बहुत तरजीह नहीं मिलती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही, उसे समझने के बजाय सियासी खुद-मुख्तारों ने तीखी बयानबाजी शुरू कर दी. स्वाभाविक है कि इस पर सियासत गरमाती. अब तो एक अलग किस्म की धर्मोन्मादी राजनीति शुरू हो गई है. नरेंद्र मोदी ने एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि आतंकवादी संगठन अलकायदा अगर यह सोचता है कि भारत के मुसलमान उसके इशारों पर नाचेंगे, तो वह भ्रम में है, क्योंकि यहां का मुसलमान देश के लिए जीता है और देश के लिए ही मरता है. वह किसी भी क़ीमत पर देशभक्ति के साथ समझौता नहीं करेगा. भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता.

मोदी का यह कथन एक तरफ़ दुनिया भर के देशों के लिए संदेश था, तो दूसरी तरफ़ मुसलमानों के लिए मरहम जैसा. हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने लव जिहाद और मदरसों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नाम पर मुसलमानों को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया और विपक्ष ने इस मामले में मोदी की चुप्पी पर उन्हें निशाना भी खूब बनाया था. इसका नकारात्मक असर भाजपा को झेलना पड़ा और उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के उपचुनाव में उसके लिए नाक बचाना मुश्किल हो गया. अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल ने सवाल भी कुछ ऐसे ही पूछे थे. जैसे कि अलकायदा भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करने में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल पर ही मोदी ने भारतीय मुसलमानों के लिए वह बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी देश या नस्ल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर एक संकट है. चैनल ने पूछा कि देश में 17 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन अलकायदा में भारतीय मुसलमान गिने-चुने ही क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने इस सवाल पर इतना ही कहा कि देश का मुसलमान ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे देश का अहित होता हो.

उत्तर प्रदेश स्थित इस्लामी धर्मपीठों के गुरुओं एवं समुदाय के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के बयान की सराहना की और उसे सकारात्मक करार दिया. इसके उलट सियासी दलों के नेताओं ने उसे उपचुनाव में भाजपा की हार और मोदी के फ्रस्ट्रेशन से जोड़ दिया. सहारनपुर के देवबंद स्थित इस्लामिक पीठ दारुल उलूम के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय मुसलमानों के बारे में सच समझ में आया है, यह सराहनीय है. नोमानी ने कहा कि भारतीय मुसलमान किसी आतंकी गतिविधियों का कभी भी समर्थन नहीं करता. लखनऊ स्थित फरंगी महल के मौलाना खालिद राशिद ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान एक सकारात्मक क़दम है. हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर कोई शक नहीं किया जा सकता. मौलाना राशिद ने कहा कि मोदी का यह बयान देश में विभाजनकारी राजनीति और उसका प्रचार करने वालों का मुंह बंद करने वाला है.

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और मौलाना कल्बे सादिक ने भी मोदी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि इससे मजहब आधारित राजनीति पर लगाम लगेगी और देश सुरक्षित रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारतीय जनता पार्टी के दीगर नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर भी असर पड़ेगा. लखनऊ में शिया समुदाय के धर्मगुरु यासुब अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि वतन से मुहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और बिना इसके वह मुसलमान हो ही नहीं सकता. यासुब अब्बास ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस अच्छे बयान का स्वागत होना चाहिए. इस्लाम भी कहता है कि देश से मुहब्बत ईमान का हिस्सा है (हुबुलवतन मिनल इमान). अगर हम अपने वतन के नहीं हो सके, हम अपने मुल्क के नहीं हो सके, तो फिर हम किसी के नहीं हो सकते. शिया धर्मगुरु ने कहा कि अलकायदा प्रमुख अल-जवाहिरी और उनके जैसे लोग दाढ़ियां बढ़ाकर, नीचे कुर्ते पहन कर, कंधे पर एके-47 रखकर खूनी खेल खेल रहे हैं. चाहे आईएसआईएस वाले हों या अल-जवाहिरी, सब के सब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं. इस्लाम का आतंकवाद से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं. सच्चा इस्लाम आतंकवाद को पसंद नहीं करता.

दिल्ली स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वह पूरी तरह सच है. भारतीय मुसलमानों ने हमेशा देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं. भारत के विकास के लिए मुसलमानों ने उल्लेखनीय योगदान किया है. समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं पत्रकार शाहिद सिद्दीकी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान सत्य वचन है. उन्होंने यह कहकर मुसलमानों के दिलों को छू लिया कि भारत का मुसलमान भारत के लिए जीता है और भारत के लिए मरेगा. अलकायदा जैसे संगठन कभी कामयाब नहीं हो सकते. भारतीय मुसलमान उसके इशारों पर नहीं नाच सकते. मुसलमानों ने एक बार नहीं, बल्कि हज़ार बार यह करके दिखाया है.

अब देश के सियासतदानों का हाल. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कटाक्ष की भाषा में कहते हैं, मोदी ने जो कहा, उसमें सच्चाई क्या है, मैं नहीं जानता. अगर मोदी का हृदय परिवर्तन हुआ है, तो यह अच्छा है, लेकिन किसी के एक बयान से उसकी सोच नहीं समझी जा सकती. कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के इस बयान को अमेरिका यात्रा से पहले इमेज मेकओवर करने यानी बिगड़ी छवि सुधारने की कोशिश करार दिया. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने मोदी के बयान के समय पर सवाल उठाया और कहा कि यह उपचुनाव में हार चुके भाजपा नेता का इमेज मेकओवर है. अगर नरेंद्र मोदी इतने ही गंभीर हैं, तो उत्तर प्रदेश में दो साल से विभाजनकारी राजनीति कर रहे अपनी पार्टी के नेताओं के ख़िलाफ़ कोई क़दम क्यों नहीं उठाते? चौधरी ने पूछा कि क्या मुसलमानों की देशभक्ति को किसी के प्रमाण-पत्र की ज़रूरत है?

राज्य के वरिष्ठ मंत्री राम गोविंद चौधरी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति को लेकर दिया गया बयान अमेरिका को खुश करने के लिए है. वरिष्ठ मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि मोदी को बयान देने से पहले मुसलमानों में अपनी पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए. बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भला कहां चुप रहने वाली थीं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की देशभक्ति पर मोदी का बयान केवल राजनीतिक स्वार्थ है और कुछ नहीं. मायावती ने पूछा कि उनका अपना, उनकी पार्टी एवं उनके सहयोगी संगठनों का चरित्र, आचरण और व्यवहार इस बयान के विपरीत क्यों है? जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने अपना पुराना रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि मुसलमानों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. ■

लव जिहाद करने वाले को जान से मार देना चाहिए

झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में लव जिहाद की ख़बरों पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने कहा कि उन मुस्लिम युवकों को जान से मार दिया जाना चाहिए, जो लव जिहाद में शामिल रहे हैं या शामिल हैं. कल्बे सादिक ने कहा कि माता-पिता को लव जिहाद में फंसी अपनी औलादों के साथ कठोर रुख अपनाना चाहिए. सच्चा मुसलमान ऐसे मनुष्यता विरोधी चक्करों में नहीं पड़ता है. इश्क और शादी के नाम पर मजहब अपनाना इस्लाम में जायज नहीं है, घोर पाप है. लेकिन, लव जिहाद के नाम पर पूरी कौम को बदनाम किया जाना भी गलत है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम सलीम का कहना है कि किसी भी तरह का झूठा वादा करके निर्दोष लड़कियों को फुसलाना इस्लाम में न सिर्फ़ सख्त मना है, बल्कि इसे घृणित काम भी बताया गया है. उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

दादरी पॉवर प्लांट भूमि अधिग्रहण प्रकरण

रिलायंस ने घुटने टेके

किसान को विकास का अगुवा और संस्कृति का खुदा कहा गया है, लेकिन जैसे-जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे-वैसे किसान हाशिये पर चला गया. रील लाइफ से रियल लाइफ तक किसान का चरित्र हमेशा से हारने वाला रहा है. वह कभी मौसम से हारता है, कभी साहूकार से, तो कभी सरकार से, लेकिन संघर्ष किसान के डीएनए में है. और शायद इसीलिए, रिलायंस जैसी बड़ी आर्थिक ताकत को दादरी के किसानों की ज़िद के आगे घुटने टेकने पड़े.

नवीन चौहान

उत्तर प्रदेश के दादरी में किसानों ने इतिहास रचा है. देश में पहली बार किसी ज़मीन अधिग्रहण के मामले में व्यवसायिक घराने को अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं. दादरी पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन वापस पाने के लिए पिछले दस सालों से संघर्ष कर रहे किसानों ने जीत हासिल की है. रिलायंस ने अधिग्रहीत की गई ज़मीन पर अपना दावा छोड़ दिया है. किसानों के लिए यह जीत इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि उनके सामने देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने ने घुटने टेके हैं. रिलायंस का दादरी में ज़मीन पर दावा छोड़ना शायद पहली घटना है, जहां किसानों की सीधे तौर पर जीत हुई है.

क़रीब दस साल पहले वर्ष 2004 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पॉवर ने ग़ाजियाबाद के दादरी में गैस आधारित 7480 मेगावाट का प्लांट लगाने की योजना बनाई थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 हज़ार करोड़ रुपये के इस पॉवर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2500 एकड़ ज़मीन अधिग्रहीत करके रिलायंस पॉवर को दे दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी में इस ज़मीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 का इमरजेंसी क्लॉज लगाकर किया था. इस प्रावधान के अंतर्गत स्कूल- कॉलेज, अस्पताल एवं सड़क आदि के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन रिलायंस पॉवर जैसी निजी कंपनी के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल किया. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित किसानों की राय लेना ज़रूरी नहीं था.

22 फरवरी, 2004 को सरकार ने दादरी में पॉवर प्लांट लगाने की घोषणा की. दादरी के सात गांवों यानी बझेड़ा, कैराना, धौलाना, जादौपुर, नंदगांवपुर, बहरमपुर एवं छहरा की 2500 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के दायरे में आई. सरकार के इस क़दम से तक़रीबन 5,700 किसान प्रभावित हुए थे. सरकार के इस फ़ैसले के विरोध में 5 अगस्त, 2004 को प्रभावित किसान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए. किसानों का कहना था कि यह सब गलत हो रहा है, उनकी मर्जी के बगैर उनकी ज़मीन कैसे ली जा सकती है? लेकिन सरकार नहीं मानी. किसान 14 अक्टूबर, 2004 तक धरने पर बैठे रहे और पॉवर प्लांट का लगातार विरोध करते रहे. बावजूद इसके सरकार ने 28 जून, 2005 को भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. सरकार के इस क़दम के बाद किसानों ने महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति एवं भारतीय किसान मंच के तत्वावधान में 25 नवंबर, 2005 को बझेड़ा खुर्द में धरना शुरू किया. प्रशासन के प्रतिनिधि किसानों से बातचीत करने के लिए आते-जाते रहे, लेकिन किसान सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए. किसानों के पक्ष में जन-समर्थन लगातार बढ़ता गया.

> दस साल की लंबी लड़ाई के बाद किसानों के पक्ष में फ़ैसला आया है. देश में पहली बार भूमि अधिग्रहण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में फ़ैसला किसानों के हित में हुआ है. आने वाले दिनों में यह फ़ैसला देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल बनेगा.
>
> ***-विनोद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मंच***
>
> रिलायंस को पहले ही मालूम हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हुआ है. उसने अपनी फजीहत होने से बचाने के लिए अंतिम समय में याचिका वापस लेने का निर्णय लिया. सही मायने में यह किसानों की एकता की जीत है.
>
> ***-युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया, महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति***

8 जुलाई, 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह किसानों के समर्थन में धरना देने बझेड़ा खुर्द पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके ठीक पहले 7 जुलाई, 2006 को रात 11 बजे पुलिस ने अचानक किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए. पुलिस ने अगले दिन सुबह छह बजे एक बार फिर किसानों पर हमला बोल दिया. पुलिस की गोली से एक किसान घायल हो गया. इसके बाद विरोध प्रदर्शन के लिए वीपी सिंह ने खेतों पर ट्रैक्टर चलाकर संकेत दिया था कि यह ज़मीन किसानों की है और किसानों की रहेगी. किसानों ने भी कहा था कि यह हमारी ज़मीन का सवाल है. हम अपना खेत छोड़कर क्यों जाएं. हमें तो कफ़न बांधकर चलना है. हम मरेंगे भी यहीं और मरने के बाद दफन भी यहीं होंगे.

किसान मंगू सिंह एवं बाबू सिंह ने सरकार के भूमि अधिग्रहण के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. अदालत ने भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी. मामले की सुनवाई के बाद 4 दिसंबर, 2009 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण को ग़ैर-क़ानूनी ठहराते हुए अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना अंशत: रद्द कर दी. अदालत ने कहा कि सरकार ने रिलायंस पॉवर जैसी निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के इमरजेंसी प्रावधानों का इस्तेमाल किया, जो ग़ैर-क़ानूनी था. अदालत ने कहा कि जिन किसानों को अधिग्रहण पर आपत्ति है, वे मुआवजा वापस करें. हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद 145 किसानों ने मुआवजे में मिले 32 करोड़ रुपये सरकार को वापस कर दिए. हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि सरकार नए सिरे से किसानों की आपत्तियां सुनकर दोबारा अधिसूचना जारी कर सकती है. उसके बाद सरकार और रिलायंस पॉवर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. उधर प्रशासन ने यह कहकर मुआवजा वापस लेना बंद कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अब वह जो फ़ैसला करेगा, वही मान्य होगा.

इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. फ़ैसला आने से पहले 22 अगस्त, 2014 को रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके मुकदमा वापस लेने और ज़मीन पर दावा छोड़ने की बात कही. उसने इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को आधार बनाते हुए कहा कि सरकार नई परियोजनाओं के लिए गैस की उपलब्धता की गारंटी नहीं दे सकती. रिलायंस पॉवर लिमिटेड ने अपनी अर्जी में कहा कि वह अपील वापस लेना चाहती है, क्योंकि दस साल की लंबी अवधि के दौरान परिस्थितियां बदल गई हैं. घरेलू प्राकृतिक गैस की देश में भारी कमी है. प्लांट चलाने के लिए प्राकृतिक गैस का कोटा हासिल करना होगा, जो इस समय बेहद मुश्किल काम है. मौजूदा परिस्थितियों में गैस की अनुपलब्धता के कारण वह पॉवर प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहती. रिलायंस के ख़िलाफ़ लड़ने वाली महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति के महासचिव युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया का कहना है कि रिलायंस को यह पहले ही मालूम हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ जाने वाला है, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अंतिम समय में याचिका वापस ले ली.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कंपनी द्वारा अपील वापस लेने का आवेदन स्वीकार करते हुए कहा कि याचिका वापस लिए जाने की स्थिति में यह मामला सुनवाई योग्य नहीं रह गया. लिहाजा इसे खारिज किया जाता है. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला बहाल हो गया. अब किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिल जाएंगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, क़ानून में दिए गए निश्चित समय के भीतर राज्य सरकार ने धारा छह के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी नहीं की. किसानों के घर में एक बार फिर उत्साह का माहौल है. लोगों के चेहरों पर खुशी साफ़ देखी जा सकती है. बात केवल मुआवजे की रकम वापसी पर अटकी हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुआवजे की रकम कैसे वापस होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस की ओर से दिए गए मुआवजे की रकम वापसी के मुद्दे को खुला रखा है. अदालत ने कहा है कि कंपनी ने निजी निवेश किया है. सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था और मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया गया था. इसलिए पैसा वापस लेने की हक़दार सरकार है. अगर आपको लगता है कि आपको पैसा वापस मिलना चाहिए, तो आप अलग तरीके से अदालत आएं. किसानों ने गलत अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की रकम न लौटाने का पक्ष रखा है, जबकि कंपनी इस मामले में पहले राज्य सरकार से संपर्क करेगी और उसके बाद क़ानूनी रास्ते पर आगे बढ़ेगी. रिलायंस पॉवर के वकील ने कहा कि कंपनी मुआवजे के तौर पर दी गई 85 करोड़ रुपये की रकम वापस लेने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करेगी, जो किसानों को ज़मीन के एवज में दी गई थी.

विधान सभा चुनाव

महाराष्ट्र में बहुकोणीय मुकाबला

शफीक आलम

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और यूपीए के घटकों के बीच चल रही रस्साकशी समाप्त हो गई. जहां भाजपा और शिव सेना ने अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी ने अपने 15 साल पुराने गठबंधन को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया. इस घटनाक्रम ने राज्य विधान सभा चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है. जहां पहले ये चुनाव एकतरफ़ा नज़र आ रहे थे, अब सभी बड़ी पार्टियों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से बहुकोणीय हो गए हैं. दरअसल महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव कई लिहाज़ से महत्वपूर्ण हैं. हरियाणा के साथ होने वाले यह चुनाव लोक सभा चुनावों के बाद होने वाले सबसे अहम चुनाव हैं जिसमें सभी बड़े दलों की प्रतिष्ठ दांव पर लगी हुई है. जहां एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश करने में जी-जान से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हालिया उपचुनावों में ख़राब प्रदर्शन की वजह से बैकफूट पर नज़र आ रही भाजपा को भी ये साबित करना है कि अब भी उसका जादू बरक़रार है. शुरू में भाजपा कम से कम इस चुनाव में किसी तरह का जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं दिख रही थी. वहीं शिव सेना इस स्थिति को भली भांति समझते हुए सीटों के बटवारे को लेकर लोक सभा चुनावों में मिली शानदार कामयाबी से उत्साहित भाजपा से शह और मात की जंग में उलझाए हुई थी. लोक सभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की स्थिति को एनसीपी समझती थी इसलिए वह भी सीट शेयरिंग के नए फॉर्मुले की मांग कर रही थी.

दरअसल यह चुनाव शिव सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के लिए भी परीक्षा की घड़ी है. क्योंकि पार्टी के वजूद में आने से लेकर अब तक यह पहला मौक़ा है जब पार्टी अपने संस्थापक बाल ठाकरे के बिना चुनाव मैदान में उतरी है. सीटों के बटवारे को लेकर उद्धव लोक सभा चुनावों की कामयाबी से उत्साहित भाजपा को कोई बहुत ज्यादा फायदा देने पक्ष में नहीं थे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि राज्यों के हालिया उपचुनाव में भाजपा के ख़राब प्रदर्शन ने उन्हें भाजपा पर हमले करने के मौके दिए, तो वह इस मौके का लाभ उठाने से भी नहीं चूके. इन चुनावों में भाजपा को 33 सीटों में से केवल 13 पर ही संतोष करना पड़ा था. इस बीच वे कभी आक्रामक मुद्रा दिखाते हुए भाजपा पर हमले किये तो भाजपा का सख्त रुख देख कर नर्म भी पड़े. उद्धव ठाकरे यह भलीभांति जानते थे कि उनके लिए भाजपा के बिना सत्ता तक पहुंचना बहुत ही कठिन है.

वहीं दूसरी ओर लोक सभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी की वजह से राज्य की राजनीति जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही भाजपा 1989 में हुए शिव सेना-भाजपा गठबंधन के समझौते में बदलाव की मांग पर डटी रही. 1989 के समझौते के मुताबिक शिव सेना राज्य की 288 विधान सभा सीटों में से 171 पर चुनाव लड़ती थी, जबकि बाकी की सीटें भाजपा के खाते में जाती थीं और लोक सभा में भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती थीं और शिव सेना को कम. लोक सभा चुनावों के इलावा भाजपा की इस मांग की एक वजह यह भी कि अगर शिव सेना-भाजपा गठबंधन के इतिहास को देखा जाए तो जीत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा का प्रदर्शन अपने सीनियर पार्टनर से बेहतर रहा है. मिसाल के तौर पर अगर 2009 के विधान सभा नतीजों पर ही निगाह डाली जाये तो यह तथ्य उजगर हो जाते हैं कि 2009 के विधान सभा चुनाव में भाजपा के हिस्से में कुल 119 सीटों आईं थीं जिनमें से उसने 46 सीटों पर जीत हासिल की थी वहीं शिव सेना ने 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे जिसमें से सिर्फ 44 उम्मीदवार ही जीत का स्वाद चख सके थे. वर्ष 2014 आम चुनाव में भी भाजपा का जीत प्रतिशत शिव सेना से बेहतर था. भाजपा ने कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें उसे 23 सीटें मिलीं जो 2009 की तुलना में 14 अधिक थीं. शिव सेना ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उससे 18 सीटों पर जीत मिली थी. 2009 की तुलना में भाजपा के मत प्रतिशत में 9.13 प्रतिशत का इजाफा हुआ था वहीं शिव सेना के मत प्रतिशत में 3.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी.

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को पिछले लोक सभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली शानदार जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के सर बांधा गया था. चूंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की सियासत में शिव सेना, भजपा, कांग्रेस और एनसीपी सभी पार्टियों का संगठनात्मक ढांचा मज़बूत है. अब ऐसी स्थिति में भाजपा के वोट प्रतिशत में आए 9.13 प्रतिशत का उछाल पार्टी के लिए एकला चलो की निति अपनाने के लिए काफी था. या यह कहें कि कम से कम वह अपनी शर्तों पर शिव सेना से सीटों के बंटवारे का समझौता करती या फिर 24 साल पुराने गठबंधन को समाप्त कर देती. भाजपा ने आखिरी विकल्फ को अपनाकर एक जोखिम उठाया. वहीं दूसरी और भाजपा की परेशानी की एक वजह राज्य के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की असमय मौत भी है. मुंडे एक ऐसे नेता थे जिनका अपना एक जनाधार था जो इस चुनाव में भी असरदार साबित होता.

सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह की रस्साकशी भाजपा और शिवसेना में चल रही थी कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का था. भाजपा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद एनसीपी ने मौके का फायदा उठाते हुए ज्यादा सीटों की मांग शुरू कर दी. भाजपा की तरह उनका भी यही तर्क था कि लोकसभा में उन्हें ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए. पिछले कुछ वर्षों में एनसीपी ने जिस तरह के इशारे दिए हैं उससे कांग्रेस यह को भरोसा नहीं था कि नतीजे के बाद एनसीपी उसके साथ रहेगी या नहीं इसलिए कांग्रेस एनसीपी को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं थी. जिस तरह एनसीपी ने भाजपा के तुरंत बाद गठबंधन तोड़ने की घोषणा की उससे इस विचार को मजबूती मिलती है कि जैसे एनसीपी पहले ही गठबंधन तोड़ने का मन बना चुकी थी. हालांकि राज्य की सभी बड़ी पार्टियां इस हकीकत से वाकिफ थीं कि दोनों में से जो भी गठबंधन बना रहेगा, वह फायदे की अवस्था में होगा.

महाराष्ट्र में दोनों गटबंधनों के टूटने से सत्ता की लड़ाई चौतरफा और बहुत ही दिलचस्प हो गई है. और सभी दावेदारों के एकला चलो की नीति अपनाने की वजह से किसी एक दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, इसलिए चुनाव के बाद के समीकरण भी चुनाव के ही तरह से दिलचस्प होंगे. अगर कुल मिला कर देखा जाये तो इस स्थिति से सबसे ज्यादा फायदे में एनसीपी दिख रही है क्योंकि वह चुनाव के बाद शिव सेना के साथ भी जा सकती है भाजपा के साथ भी जा सकती है और कांग्रेस के साथ भी रह सकती है. कांग्रेस अगर एनडीए गटबंधन के टूटने के बाद एनसीपी के साथ अपना गठबंधन बचा लेती तो उससे इस चुनाव में फायदा हो सकता था. पहले नवनिर्माण सेना अकेले खेल बिगाड़ने वाली पार्टी थी जो शिव सेना और भाजपा का खेल ख़राब करती थी इस बार असददुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कांग्रेस और एनसीपी का खेल ख़राब करने के लिए मैदान में मौजूद है. बहरहाल, यह तो 19 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र के सियासी बिसात पर किसके मोहरे पिटे और किसने बाज़ी मारी, लेकिन फ़िलहाल चुनाव को लेकर कयासआरियों का बाज़ार गर्म है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

इस अफवाह में सच्चाई भी नज़र आती है. यह दुःखद है, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस, दोनों दलों का आधार है. अगर ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ नुक़सान ही होगा. हालांकि, यह सर्वविदित है कि शरद पवार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और वह शायद यह सोचते हैं कि चुनाव के बाद भाजपा और एनसीपी में कोई तालमेल हो सकता है, कोई डील हो सकती है और इस तरह वह केंद्र में भी अपनी पैठ बना सकेंगे. यह बेकार की सोच है.

गठबंधन तोड़ने का फ़ायदा क्या है?

महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. यहां दो गठबंधन थे. पहला, एनसीपी एवं कांग्रेस का और दूसरा भाजपा एवं शिवसेना का. दोनों वैचारिक तौर से एक दूसरे की पूरक थीं यानी दोनों के विचार मेल खाते थे और यह माना जाता था कि मतदाता किसे वोट दे, इसे लेकर एकदम स्पष्ट था. हालांकि, अब ये दोनों गठबंधन टूट चुके हैं. क्यों? भाजपा और शिवसेना के बीच महज दो या तीन सीटों के लिए असहमति थी. जैसी ख़बरें आ रही हैं, उसके मुताबिक एक भाजपा नेता ने एक सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, जो इस गठबंधन के टूटने का कारण बन गया. यह दोनों ही दलों के लिए बुरा हुआ, क्योंकि दोनों का वोट आधार एक ही है. अगर ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, तो दूसरी पार्टियों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा. वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस एवं एनसीपी गठबंधन के बारे में मुंबई में यह अफवाह थी कि अगर भाजपा एवं शिवसेना का गठबंधन टूट जाएगा, तो एनसीपी भी अपना गठबंधन तोड़ लेगी, क्योंकि चुनाव के बाद एनसीपी, जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी, उसके साथ जाना चाहती है.

इस अफवाह में सच्चाई भी नज़र आती है. यह दुःखद है, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस, दोनों दलों का आधार है. अगर ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ नुक़सान ही होगा. हालांकि, यह सर्वविदित है कि शरद पवार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और वह शायद यह सोचते हैं कि चुनाव के बाद भाजपा और एनसीपी में कोई तालमेल हो सकता है, कोई डील हो सकती है और इस तरह वह केंद्र में भी अपनी पैठ बना सकेंगे. यह बेकार की सोच है.

इस गठबंधन के टूटने के बाद असल में क्या होगा और अंतत: क्या परिणाम आता है, उसके बाद भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह के घपले और घोटाले हुए हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता. सिंचाई घोटाले का संबंध मुख्य रूप से एनसीपी से था. इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि गठबंधन टूटने का लाभ एनसीपी को मिले. अगर चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए एक साथ आना ही पड़ता है, तो फिर इस गठबंधन को तोड़ने का मतलब क्या है? जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, अब तक की स्थिति यही है.

इस गठबंधन के टूटने के बाद असल में क्या होगा और अंतत: क्या परिणाम आता है, उसके बाद भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह के घपले और घोटाले हुए हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता. सिंचाई घोटाले का संबंध मुख्य रूप से एनसीपी से था. इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि गठबंधन टूटने का लाभ एनसीपी को मिले. अगर चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए एक साथ आना ही पड़ता है, तो फिर इस गठबंधन को तोड़ने का मतलब क्या है?

हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, उसके मुकाबले हरियाणा को एक बेहतर सरकार की ज़रूरत है. अन्य राज्यों के चुनाव अभी दूर हैं. कश्मीर की हालत को देखते हुए वहां चुनाव करा पाना मुश्किल दिखता है.

मैं सोचता हूं कि चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करने से पहले कश्मीर को गवर्नर रूल से गुजरना पड़ेगा. एक तस्वीर यह आ रही है कि बाढ़ के दौरान की गई मेहनत की वजह से कश्मीर के आम लोगों के बीच सेना की छवि अच्छी बनी है. गिलानी की स्थिति कमजोर हुई है. उनकी सेना और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ बातें बेअसर साबित हुई हैं. प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर मामले में उठाया गया क़दम सराहनीय है. यह अच्छा संकेत है कि गिलानी द्वारा पाकिस्तान के उच्चायुक्त के यहां जाने की घटना को मुद्दा नहीं बनाया गया. बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक दुराग्रह के कश्मीर की मदद के लिए सारा देश एकजुट हुआ. मैं सोचता हूं कि कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर के लोगों का पुनर्वास किया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यक्तित्व ऐसा हो, जो प्रेरित करे

संवाददाता को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व भी संपादक का होना चाहिए. संवाददाता तभी अपनी जी-जान रिपोर्ट में लगाता है, जब उसकी संपादक पर श्रद्धा होती है. इसके लिए संपादक को यह वातावरण तैयार करना चाहिए कि यदि संवाददाता पर कोई भी परेशानी आएगी, तो वह उसके साथ खड़ा होगा. संपादक अगर यह विश्वास अपने संवाददाता को दिला दे, तो उसे ऐसी रिपोर्ट मिलेंगी, जो उसे, उसके अख़बार, पत्रिका या चैनल को प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगी. अन्यथा संवाददाता सामान्य या सामान्य से थोड़ी बेहतर रिपोर्ट लाएगा, पर असामान्य, असाधारण या देश को हिला देने वाली नहीं. संपादक कितना सतर्क व कुशल है, यह इस बात से पता चलता है कि उसका सूचना तंत्र क्या है. ज़्यादा से ज़्यादा अख़बार व पत्रिकाएं पढ़ने के साथ उसका संबंध उनसे भी होना चाहिए, जो शासन चलाते हैं. इसमें पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व राजनीतिज्ञ शामिल हैं. पढ़ने में तो उसे जो भी चीज मिले, पढ़नी चाहिए. दरअसल, यह सूचना तंत्र ही संपादक की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि एक संपादक के पास जानकारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. जानकारी का यह खजाना ही उसे अपने संवाददाताओं और संपादकीय टीम से अलग करता है, अन्यथा यदि वह भी उसी स्तर पर रहेगा, तो नेतृत्व दे ही नहीं सकता.

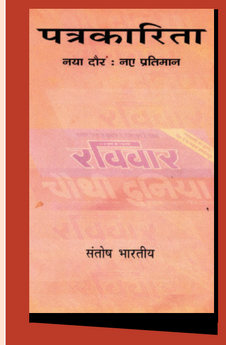

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

संपादक में न्यूज सेंस कितना है, यह भी उसका कद तय करता है. जानकारी आ रही हो, वह संपर्क भी रख रहा हो और वह तय न कर पाए कि इसमें से ख़बर क्या निकालनी है, तो उसके पास कितनी ही जानकारी हो, व्यर्थ है. तब वह रिफरेंस या कंप्यूटर में एकत्र जानकारी का पर्याय बनकर रह जाएगा. कौन-सी ख़बर कब काम आ सकती है तथा किस ख़बर को कितना महत्व देना है, इसका ज्ञान एक संपादक को होना ही चाहिए. ख़बरों की दुनिया में समय का बड़ा महत्व है. समय के पहले जो ख़बर दे देता है, वह सफल संपादक माना जाता है. ख़बरें हमेशा आसपास बिखरी होती हैं. पर उनमें से चुनकर जो संपादक देश को कुछ अलग दे देता है, याद रह जाता है, बाकी संपादकों की भीड़ में एक संपादक भर बनकर रह जाते हैं. रिपोर्ट, स्टोरी, न्यूज ब्रेक और स्कूप का अर्थ संपादक को पता होना चाहिए. बहुत से संपादकों को पता होता है, पर वे इसे याद नहीं रखते और न इसका इस्तेमाल करते हैं. रिपोर्ट वह होती है, जिसे सभी करते हैं और अक्सर एक ही तरह से करते हैं. घटना घट जाती है और सभी संवाददाता उसे कवर करते हैं. इसमें भाषा के बदलाव के अलावा कुछ नहीं होता.

स्टोरी वह होती है, जिसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं, पर संवाददाता उसे खोज कर ऊपर ले आता है. प्रशासन, राजनेता दबाने वाले तत्व होते हैं, पर संपादक को चाहिए कि उसे दबने न दे और यही दबी हुई चीज स्टोरी होती है. अक्सर रिपोर्ट और स्टोरी को एक समझने की गलती हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए. न्यूज ब्रेक वह है, जो घटना घटने के बाद सबसे पहले पाठकों या दर्शकों तक पहुंचाया जाए. आजकल चैनलों में देखा गया है कि एक ही घटना को कई न्यूज चैनल न्यूज ब्रेक के रूप में दिखाते हैं और दिखाते ही चले जाते हैं. जो सबसे पहले दिखाए, उसे ही न्यूज ब्रेक कहने का अधिकार है, बाकी को नहीं. यही समय के ख़िलाफ़ दौड़ है, रेस अगेंस्ट टाइम. चौथा शब्द है स्कूप. यह आजकल गायब-सा हो गया है. स्कूप उसे कहते हैं, जो केवल एक संपादक की टीम के पास होता है. जिसे वह छापता या दिखाता है और बाकी लोग बाद में उसका फॉलोअप करते हैं. स्कूप किसी भी तरह का हो सकता है, पर होता है यह चौंकाने वाला. संपादक का न्यूज सेंस भी स्कूप के लिए संवाददाता को प्रेरित कर सकता है, पर स्कूप के लिए संपादक सावधान रहे, अन्यथा खंडन आने की स्थिति में उसकी साख को धक्का लग सकता है.

संपादक को इस बात के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसके अख़बार, पत्रिका या चैनल का इस्तेमाल कोई निहित स्वार्थ से तो नहीं कर रहा. कोई स्टोरी या रिपोर्ट प्लांट तो नहीं करा रहा. असावधानीवश ऐसा हो जाता है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी संपादक की होती है. ख़बरों के संसार में रहने वालों को अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रहता कि किसी के बारे में गलत छप जाने से उस व्यक्ति का सामाजिक अपमान हो जाता है तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट आती है, जो बाद में खंडन छपने से भी वापस नहीं आती. संपादक का कर्तव्य है कि ऐसी रिपोर्ट, जिसमें व्यक्तिगत आरोप हों, उसकी छानबीन करने के लिए संवाददाता से अवश्य कह दे. सही बात रुकनी नहीं चाहिए और गलत बात जानी नहीं चाहिए. यह संपादक का एसिड टेस्ट है. एसिड टेस्ट इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि संवाददाता इसे गफलत में भूल जाए, पर संपादक भी भूल जाए, तो यह अन्याय होगा.

संपादक को इस बात के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसके अख़बार, पत्रिका या चैनल का इस्तेमाल कोई निहित स्वार्थ से तो नहीं कर रहा. कोई स्टोरी या रिपोर्ट प्लांट तो नहीं करा रहा. असावधानीवश ऐसा हो जाता है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी संपादक की होती है. ख़बरों के संसार में रहने वालों को अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रहता कि किसी के बारे में गलत छप जाने से उस व्यक्ति का सामाजिक अपमान हो जाता है तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट आती है, जो बाद में खंडन छपने से भी वापस नहीं आती.

संवाददाता रिपोर्ट भेजता है, पर हो सकता है कि वह रिपोर्ट ज़्यादा सपाट हो. उस रिपोर्ट को एंगल देना संपादक का कार्य है. रिपोर्ट को चुनते वक्त तथा उसे एंगल देते वक्त संपादक को देखना चाहिए कि उसका मानवीय पक्ष कहीं छूट तो नहीं रहा है? उसे यह भी देखना चाहिए कि जो रिपोर्ट जा रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसे क्यों दिया जा रहा है? उस ख़बर से समाज का कुछ भला होने वाला है या नहीं? अच्छे संपादक का बुनियादी कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति विशेष को दु:ख पहुंचाने वाली या किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली ख़बर न जाने दे, इसका पूरा ध्यान रखे कि ऐसा किसी भी हालत में न हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में कोयला घोटाले की रिपोर्ट को सच साबित कर दिया और उसने चार कोल ब्लॉक को छोड़कर (दो सरकारी कंपनियों एवं दो रिलायंस पॉवर) बाकी सभी को रद्द कर दिया. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला आया, वैसे ही कुछ टीवी चैनलों समेत कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस रिपोर्ट को सबसे पहले हमने दिखाया या हमने छापा और हमारी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सच साबित किया. उनकी इस बात को सिर माथे पर लेते हुए हम सिर्फ़ एक आग्रह करना चाहेंगे कि ये टेलीविजन चैनल और बाकी मीडिया, जिनमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है, यह बताएं कि इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट किस तारीख को छापी-दिखाई और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट किस तारीख को छापी-दिखाई तथा उस रिपोर्ट का सार क्या है?

संसद दलालों को चिन्हित और बहिष्कृत करे

यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पाठकों के साथ हमेशा छल होता है और इस बार भी यही छल हो रहा है. चौथी दुनिया ने इतिहास के सबसे बड़े कोयला घोटाले को 25 अप्रैल, 2011 को चौथी दुनिया की आमुख कथा के रूप में-सरकार ने देश को बेच डाला: 26 लाख करोड़ का महाघोटाला शीर्षक तले छापा था. हमने यह रिपोर्ट भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी और उनके सचिव श्याम जाजू को छपी हुई प्रति के साथ भेजी थी. इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, न इस सवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मजे की बात यह है कि इस मामले को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने उठाया था, पर अपने ही सांसद की बात को भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं विशेष कारणोंवश अनदेखा कर दिया. हमने इस छपी हुई रिपोर्ट को मार्क्सवादी पार्टी के सांसदों को भी भेजा, पर उन्होंने भी इसे अनदेखा कर दिया.

दरअसल, या तो वे समझ नहीं पाए कि यह घोटाला कितना बड़ा है और पढ़कर तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाए. या फिर उनके कुछ और स्वार्थ इस सवाल को न उठाने में रहे होंगे. हमने फिर इस रिपोर्ट को जून 2012 में छापा. और, हम ही थे, जिन्होंने इस सवाल को-मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं- हेडिंग लगाकर अपने अख़बार में छापा. कोयला घोटाले को लेकर चौथी दुनिया लगातार रिपोर्ट छापता रहा, लेकिन न संसद ने इसके ऊपर पर ध्यान दिया, न राजनीतिक दलों ने. और आज मीडिया में कुछ लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. हकीकत यह है कि चौथी दुनिया के इन सारे अंकों की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट जाती रहीं. हमने इन्हें आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भेजा. हम यह नहीं कह सकते कि प्रधान न्यायाधीश ने हमारी रिपोर्टों को पढ़कर या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों ने हमारी रिपोर्ट को पढ़कर कोई दिमाग बनाया, लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बधाई दे सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले के ऊपर नज़र न रखी होती, तो यह घोटाला हमारे सामने नहीं आता.

कोयले का यह घोटाला बताता है कि 1993 से लेकर 2014 तक जितनी सरकारें रही हैं, वे सब इस घोटाले को अनदेखा करने या इस घोटाले में अपनी भागीदारी साबित करने में किसी से पीछे नहीं रहीं. इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि कोयला घोटाले में कोई एक ऐसा ग्रुप काम कर रहा था, जो सरकारी अधिकारियों को भी बरसाता रहा था, मंत्रियों को भी बरसाता रहा था और जो साथ नहीं दे रहा था, उसे अपने पक्ष में कर रहा था. विपक्ष के भी प्रभावशाली लोगों को इस ग्रुप ने कोयला घोटाला न उठाने के लिए तैयार कर लिया. सवाल यह है कि सारे सबूतों के साथ छपी हुई रिपोर्ट पढ़कर भी विपक्ष का कोई नेता संसद में इस पर अड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे कोई बहुत मासूम कारण नहीं है कि हमें जानकारी नहीं थी, हम उसे देख नहीं पाए, हमारे पास वक्त नहीं था, हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त थे या हम विदेश गए हुए थे. इसीलिए, हमें (चौथी दुनिया) इस पूरे कोयला घोटाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाज़ है, हम सुप्रीम कोर्ट को फिर बधाई देते हैं.

सुप्रीम कोर्ट क्या इस सवाल को सिर्फ़ जुर्माना लगाकर रफा-दफा कर देगा या सीबीआई से कहेगा कि वह इस बात की जांच करे कि कैसे कोयला घोटाला इतने दिनों तक चलता रहा और इसके पीछे कौन-सी ब्यूरोक्रेटिक और राजनीतिक शक्तियां काम कर रही थीं? वह कौन सा ग्रुप था, जिसने सब लोगों को कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों के पक्ष में खड़ा कर दिया? हमने अपनी पहली ही रिपोर्ट में सारी कंपनियों के नाम छापे थे कि ये कंपनियां कोयला घोटाले में शामिल हैं. राजनीतिक दलों के कान पर जूं नहीं रगी और ब्यूरोक्रेसी तो शायद इसका साथ दे ही रही थी. कुछ इक्के-दुक्के अफसर थे, जिन्हें किसी न किसी तरह चुप करा दिया गया.

मुझे अब यह लगता है कि इस कोयला घोटाले की इतिश्री यहीं पर नहीं होनी चाहिए. राजनीतिक दल इस सवाल को नहीं उठाएंगे और मीडिया भी इस सवाल को नहीं उठाएगा. तत्कालीन सरकार में शामिल पार्टियों के सांसद, जिनकी कंपनियां इस कोयला घोटाले में शामिल हैं, कह रहे हैं कि गलती सरकार की थी और जुर्माना हमें भरना पड़ रहा है. सरकार से यह गलती कराई किसने? सरकार से यह गलती तात्कालीन कंपनियों के मालिकों ने कराई. इनमें से कुछ मालिक राज्यसभा में हैं और कुछ लोकसभा में. अब अगर हम यह कहें कि दरअसल, लोकसभा में एक छोटी संख्या और राज्यसभा में एक बड़ी संख्या देश के कॉरपोरेट घरानों के हितों के लिए लॉबिंग का काम रही है और गांवों की भाषा में कहें कि दलालों का काम कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. यह राज्यसभा और लोकसभा के उन सांसदों को बुरा लग सकता है, जो कॉरपोरेट घरानों की दलाली में लगे हुए हैं, पर सच्चाई यही है. और, इस सच्चाई के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को फिर से बधाई देनी चाहिए कि उसने भ्रष्टाचार के एक सतत चल रहे कैंपेन के ऊपर से पर्दा हटाने का काम किया है.

अब इसकी आपराधिक जांच होनी चाहिए और सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके दस्खतों से इतना बड़ा घोटाला हुआ. अगर यह नहीं होता है, तो फिर एक नज़ीर बन जाएगी कि अगर बड़े लोग अपराध करें, तो जुर्माना देकर छूट सकते हैं और अगर साधारण जनों से अनजाने में कोई अपराध हो जाए, तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. यह न्याय का दोहरा मानदंड है, जो नहीं चलना चाहिए. इस सारी प्रक्रिया के दौरान हमारे सामने एक और तथ्य आया कि इस कोयला घोटाले से बड़ा एक और कोयला घोटाला हुआ है यानी इस देश में कोयले ने काफी बड़ी राजनीति की है, बहुत छोटे पूंजीपतियों को बड़ा बना दिया और आज वे पूंजीपति देश के ऊपर राज करने का सपना देख रहे हैं. यह बड़ा कोयला घोटाला कैसे हुआ, इसे भी हम अगले अंकों में लेकर आएंगे.

लेकिन, इस मौजूदा कोयला घोटाले पर हम सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन करते हैं कि यह कोयला घोटाला न एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये का है, न एक लाख छियासी हज़ार करोड़ रुपये का है, बल्कि यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ रुपये का है. और, सुप्रीम कोर्ट से हमारा आग्रह है कि जिस दिन वह चाहेगा, हम उसे सारे कागजात दे देंगे, जिनमें 26 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला साबित होता है और इसे हम नहीं साबित करेंगे. इसे हम संसद की संसदीय समितियों की कार्रवाई और उनके आंकड़ों के जरिये साबित करेंगे. अपनी ही समितियों द्वारा की गई कार्रवाई को संसद और सरकार ने अनदेखा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट क्यों अनदेखा कर रहा है, यह हमारी समझ में नहीं आता. इसलिए हम एक लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करना चाहते हैं कि एक लाख छियासी हज़ार करोड़ या एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये के कोयला घोटाले की जांच को फिर से खोला जाए और इसे 26 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक अपराध के रूप में देखा जाए. और, जो लोग इस अपराध में शामिल हैं, उनके लिए क्या सजाएं हों, इसका निर्णय किया जाए.

राजनीति अच्छी चीज है और राजनीति बहुत बुरी चीज भी है. जब राजनीति लोगों के लिए हो, तो अच्छी है. और, जब राजनीति भ्रष्टाचार के लिए हो, तो बुरी है. इसलिए वक्त आ गया है कि राजनेता यह तय करें कि उनमें से कौन जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन कॉरपोरेट की दलाली का काम कर रहे हैं. अगर इसके ऊपर आज फैसला न हुआ या बातचीत न शुरू हुई, तो यह मानना चाहिए कि बहुत पहले एक अख़बार ने आरोप लगाया था, जिस पर संसद में बहुत हाय-तौबा मची थी, कि संसद दलालों का अड्डा बन गई है. मेरी प्रार्थना है कि उस हल्ले-गुल्ले को याद कर संसद स्वयं अपने कंरेक्टिव मेजर्स ले और उन लोगों को अपने बीच में से चिन्हित करे, जो कॉरपोरेट के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए दबाव ग्रुप का काम कर रहे हैं. मंत्रियों के यहां जा रहे हैं, सरकारों पर दबाव बना रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्ट करने में अपना रोल निभा रहे हैं. अगर इस संसद में कोई ऐसा नहीं है, तो हम चाहेंगे कि संसद कहे कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं है या कोई ग्रुप ऐसा नहीं है. तब हम, कौन लोग हैं और कौन लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर खुलासा करेंगे. लेकिन, उसके पहले हमारा विनम्र निवेदन है कि संसद खुद अपने बीच के ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उन्हें अपने बीच में बहिष्कृत करने का काम करे. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

समय आ गया है, अब मोदी को कहना चाहिए कि उन्हें इन सब चीजों के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है. वह देश को तेज विकास और रोज़गार देना चाहते हैं तथा विश्व में भारत की एक मजबूत पहचान कायम करना चाहते हैं. उन्हें इसके लिए कम से कम दस साल चाहिए. उन्हें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, जो सही राजनीतिक दिशा के साथ पूरी तरह समावेशी हो और सभी को साथ लेकर चलने वाली हो. नरेंद्र मोदी के बारे में बताया भी गया है कि उन्होंने गुजरात में संघ और विहिप को हाशिये पर लाकर विकास को तेज गति दी थी. यह उनके लिए आसान काम नहीं होगा.

क्रांतिकारी बनने का शानदार मौक़ा

लॉर्ड एक्शन ने कहा था कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण भ्रष्टाचारी. अब भाजपा कार्यकर्ताओं के नेता सत्ता में सौ दिन व्यतीत भी कर चुके हैं. इसके बावजूद नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए इतने बड़े बहुमत के बारे में पार्टी कार्यकर्ता यही मानते हैं कि यह सफलता उनकी वजह से मिली है, न कि मोदी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के चलते. इस सफलता को वे अपने सांप्रदायिक विश्वासों की पुष्टि के तौर पर भी देखते हैं. शायद यही वजह है कि उनके द्वारा दुर्व्यवहार शुरू हो गया है. लव जिहाद जैसे प्रबल मुस्लिम विरोधी शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा. निश्चित रूप से इसमें मुख्य निशाना अपनी लड़कियों को बनाया गया और यह बताया गया कि मुस्लिम युवक उन्हें फांस लेते हैं, फिर बलपूर्वक उनका धर्म-परिवर्तन करा देते हैं. लेकिन, हमारे लड़के उनकी लड़कियों के साथ विवाह कर लें, चाहे बलपूर्वक ही क्यों नहीं, तो यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है. गाय के मांस और उसके निर्यात को लेकर मुसलमानों के बारे में झूठे बयान भी आने शुरू हो गए, यहां तक कि एक मंत्री द्राग भी. मदरसे एक बार फिर आतंकियों की पनाहगाह बताए जाने लगे. गोवा के ईसाइयों से कहा गया कि वे अपने आपको हिंदू घोषित कर दें.

लेकिन, सौभाग्य से भारतीय मतदाता ज़्यादा संवेदनशील साबित हुए. उत्तर प्रदेश में उन्होंने घृणा की बात करने वालों को हरा दिया. इस वजह से अपने हनीमून पीरियड के दौरान ही भाजपा को जागृत करने वाला झटका लग गया है. लोगों ने मोदी को इसलिए चुना था, क्योंकि उनका संदेश सकारात्मक और समावेशी था, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई थी. मतदाताओं ने भाजपा को उस बात के लिए वोट नहीं दिया था, जो संघ सोचता है. आम मतदाता कांग्रेस के भ्रष्टाचार, असमर्थता और घमंड से आजिज आ चुका था. लोग मुद्रास्फीति, धीमी विकास दर और बेरोज़गारी से निराश हो चुके थे.

असली विषय हिंदुओं की पहचान और मुसलमानों की वफादारी नहीं थी, बल्कि जनता ने इस बात के लिए वोट दिया कि प्रशासन अच्छा हो. उसने इस बात के लिए वोट नहीं दिया था कि उसे इस तरह के वैचारिक ज़हर दिए जाएं. प्रधानमंत्री की एक अजीब प्रतिष्ठा इस बात के लिए बन गई है कि वह अपने मंत्रियों पर निगरानी रखते हैं. उनके बारे में कई कहानियां, हो सकता है झूठी भी, हैं कि वह मंत्रियों को गलत कपड़े पहनने पर वापस बुला लेते हैं या पंच सितारा होटल में किसी व्यापारी के साथ कॉफी पीने पर भी.

समय आ गया है, अब मोदी को कहना चाहिए कि उन्हें इन सब चीजों के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है. वह देश को तेज विकास और रोज़गार पहचान कायम करना चाहते हैं. उन्हें इसके लिए कम से कम दस साल चाहिए. उन्हें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, जो सही राजनीतिक दिशा के साथ पूरी तरह समावेशी हो और सभी को साथ लेकर चलने वाली हो. नरेंद्र मोदी के बारे में बताया भी गया है कि उन्होंने गुजरात में संघ और विहिप को हाशिये पर लाकर विकास को तेज गति दी थी. यह उनके लिए आसान काम नहीं होगा. दरअसल, ऐसा करने में उन्हें अपने मुख्य काम से ध्यान भी भटकाना पड़ सकता है. हो सकता है कि ऐसा करने के बाद भाजपा के नेतृत्व में उनके पास बहुत सारे दोस्त न बचें, लेकिन अगर इस पर कुछ भी न किया जाए, तो इसकी क़ीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है. महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की बीच अंदरूनी रार चल ही रही है. पृथ्वीराज चव्हाण भले ही अपनी पार्टी के चहेते न हों, लेकिन अभी तक पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों (महाराष्ट्र के) में उनकी छवि सबसे ज़्यादा साफ़ है. राज्य में चुनावों में निश्चित रूप से शिवसेना अपना सांप्रदायिक कार्ड खेलेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मराठी कार्ड भी खेलेगी.

मोदी ने देखा है, जो उनकी पार्टी बहुत पहले देख चुकी है, कि सिर्फ़ हिंदू वोट जीत का आधार नहीं है. हिंदू भी आपस में कई जातियों में विभाजित हैं. पिछले 25 सालों में दलित और पिछड़े वर्ग की पार्टियों की सफलता ने कांग्रेस पार्टी के सवर्ण प्रभुत्व वाले विचार को ख़त्म किया है. इसे समाजवाद के रूप में भी देखा गया. आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए इस उत्पीड़न को शर्म की बात बताया था. उन्होंने कहा कि पीड़ित जातियों ने खुद इस उत्पीड़न को स्वीकार किया था, क्योंकि मुस्लिम शासन के समय में उक्त जातियां अपने हिंदू (उच्च जाति के) उत्पीड़कों के साथ एकता प्रदर्शित करना चाहती थीं. अब जब इतिहास लेखन की बातें और तेज होंगी, तो इस तरह की और बातें भी सामने आने वाली हैं. लेकिन, यह बताता है कि हिंदू राष्ट्रवादी इस बात को जानते हैं कि हिंदू बहुलवाद एक कोरी कल्पना ही है. महान नेता अक्सर नए गठबंधन बनाते हैं और अपनी पार्टी को दोबारा सांगठनिक रूप से मजबूत करते हैं. फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने अफ्रीकी अमेरिकीयों को डेमोक्रेटिक पार्टी में रिक्रूट किया, यह जानते हुए कि उनका अब्राहम लिंकन की रिपब्लिकन पार्टी के साथ पुराना नाता है. मार्गरेट थैचर ने लेबर पार्टी से वर्किंग क्लास का वोट खींच लिया था. टोनी ब्लेयर अपने कार्यकाल में वह वोट वापस ले आए और उपनगरीय मध्यमवर्गीय मतों को टोरियों से छीन लिया. एक क्रांतिकारी बनने के लिए 64 वर्ष की उम्र पर्याप्त है. यह बात मोदी के लिए है. वह भारत का विकास भी करना चाहते हैं. हाल के समय में कुछ गतिरोधों को छोड़ दिया जाए, तो विपक्ष में एक खालीपन है ही है. मोदी को जन्मदिन की देर से शुभकामनाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोरारका फाउंडेशन

सौर लालटेन से रोशन होती जिंदगी

धर्मेंद्र कुमार सिंह

एक तो गरीबी और बचपन से ही विकलांगता की मार झेल रहे व्यक्ति के लिए न तो कोई सरकारी योजना बनाई जाती हैं और न ही उनकी मदद के लिए कोई आगे आता है. गरीबों के लिए सरकारे बड़े–बड़े वायदे, तो करती हैं, लेकिन न उन पर अमल होता है और न गरीबों को उसका लाभ मिल पाता है. कुछ लोग गरीबी के कारण शहर जाते हैं और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन जो विकलांग है वह शहर भी नहीं जा सकता उसे गांव में ही गरीबी के कारण मुफलिसी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है. ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के झुनझुनू जिला के शेखावती क्षेत्र नवलगढ़ के गांव घोरीवारा कलां में रहने वाली विकलांग नीलम कंवर और गांव चैनगढ़ के किसान धुड़ाराम की. वह भी गांव में गरीबी के कारण मुफलिसी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थे, लेकिन मोरारका फाउंडेशन की महत्वाकांक्षा सोलर लालटेन परियोजना उनके जीवन में एक रोशनी लेकर आई. मोरारका फाउंडेशन की सोलर लालटेन परियोजना की शुरूआत 2010 में हुई थी. सूरज की रोशनी को रात में भी लोगों के घरों तक पहुंचाने एवं उससे लोगों को रोजगार प्रदान के इरादे से मोरारका फाउंडेशन ने शेखावटी क्षेत्र में सौर उर्जा के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक कर अपनी भूमिका को पांच सालों से सफलता पूर्वक निभा रहा है. जब हम घोड़ीवारा कलां गांव में रहने वाली नीलम कंवर की दास्ता सुनते हैं, तो एक अनोखी तस्वीर उभर कर सामने आती है. नीलम कंवर के पास न कोई जमीन है और न परिवार चलाने के लिए उसके पास कोई रोजगार था. उसके पास रहने के लिए केवल एक छोटा सा मकान था. नीलम उसी मकान मेंअपने तीन बच्चों और मजदूर पति के साथ गरीबी और अपंगता से लड़ रही थी. मोरारका फाउंडेशन ने अपने इसी योजना के तहत नीलम कंवर का चयन कर सौर उर्जा पैनल एवं अन्य संसाधन लगाए और उसको 25 सौर उर्जा से चलित लालटेन वर्ष 2011 में प्रदान किए. नीलम को इसके व्यावसायिक उपयोग से रोजगार मिल गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया. वह इन लालटेनों को शादियों, समारोह, विद्यार्थियों और रात में खेतों में काम करने वाले किसानों को किराए पर देती हैं. बिजली न होने पर लोग इसका प्रयोग करते हैं और यह कम पैसे में लोगों को किराए पर प्राप्त हो जाता है. नीलम कंवर ने बताया कि वह अपने खर्चे बावजूद एक साल में 18 हजार रुपये की बचत की, जो कि एक गांव में विकलांगता की मार झेल रही महिला के लिए बहुत बड़ी बात है.

मोरारका फाउंडेशन ने सौर उर्जा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है और इसके इस्तेमाल द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है. धुड़ाराम कहता है कि मोरारका फाउंडेशन न केवल रोजगार बल्कि मेरे अंधकारमय जीवन को एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया और अब मैं इस रोजगार के साथ–साथ सौर उर्जा के उपयोग के बारे में अधिक से अधिक जानाकरी जुटाकर क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति जागरूक करूंगा और लगन से कार्य कर आय अर्जित करूंगा.

इस रोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाली नीलम कहती हैं कि अगर किसी में कार्य के प्रति जुनून हो तो किसी प्रकार की बाधा क्यों न आ जाए अर्थात मेहनत के प्रति सफलता अपने आप झुकती है. मेरे रोजगार के प्रचार–प्रसार हेतु मोरारका फाउंडेशन केंद्र पर रोजगार से संबंधित सारी सूचनाएं लिखवा रखा है तथा पम्पेलेट्स भी छपवा कर दे रखे हैं, जिन्हें आस–पास के गांवों में बांटकर अपने व्यवसाय का प्रचार कर इसके उपयोग से जो आय अर्जित होती है, उससे एक खुशहाल परिवार के रूप में जीवनयापन कर रही हूं. नीलम के चेहरे की खुशी बताती है कि उसके नि:शक्त जीवन को मोरारका फाउंडेशन ने सोलर लालटेन के जरिए रोजगार प्रदान कर एक नया आयाम दिया है. आगे बात करते हैं शेखावती क्षेत्र के चैनगढ़ गांव के किसान धुड़ाराम की जो एक सीमेंट फैक्टरी में काम करता था और कार्य के दौरान अपना एक हाथ गंवा बैठा. हाथ कटने के बाद कंपनी ने उसे बेसहारा छोड़ दिया. फिर क्या था एक हाथ गंवा बैठे धुड़ाराम गरीबी में जीवन–यापन करने लगा, लेकिन मोरारका फाउंडेशन ने इस वर्ष विकलांग धुड़ाराम जो गरीबी और बेरोजगरी से जुझ रहा था. धुड़ाराम का चयन कर सौर उर्जा पैनल व अन्य संसाधन लगाने एवं 25 सौर उर्जा से स्वचलित लालटेन प्रदान किए. फाउंडेशन इसके प्रचार–प्रसार हेतु क्रेंद्र पर पूरी सूचना दिया है और पम्पलेट्स छपवा कर दिया है, जिन्हें वो आस–पास गांवों में बांट कर प्रचार–प्रसार कर सके. फाउंडेशन ने धुड़ाराम को इसके उपयोग के बारे में बताया. फाउंडेशन ने सौर उर्जा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है और इसके इस्तेमाल द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है. धुड़ाराम कहता है कि मोरारका फाउंडेशन न केवल रोजगार बल्कि मेरे अंधकारमय जीवन को एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया और अब मैं इस रोजगार के साथ–साथ सौर उर्जा के उपयोग के बारे में अधिक से अधिक जानाकरी जुटाकर क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति जागरूक करूंगा और लगन से कार्य कर आय अर्जित करूंगा. इसी प्रकार फाउंडेशन ने कई विकलांगों की जिंदगियां सवारी है और कटराथाल गांव निवासी कालू भट, कोलसिया गांव निवासी राधेश्याम, कोलिडा गांव निवासी मुरारी शर्मा और बसावा गांव निवासी दीपक यादव इन सभी विकलांगों को सौर उर्जा लालटेन के द्वारा रोजगार प्रदान कर इनके सपनों को साकार किया है. फाउंडेशन ने अपने इस अभियान से गांव–गांव केवल प्रचार–प्रसार ही नहीं कर रहा है गरीबी की मार झेल रहे विकलांगों को इसके जरिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे अपने परिवार के साथ खुशी भरा जीवन जी सकते हैं. सरकार इस योजना को यदि पूर देश में लागू करे, तो विकालांग लोगों को गरीबी से झुटाकारा मिल सकता है, वे नीलम कवंर की तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर भविष्य भी संवार सकते हैं. विकलांगों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाएं, तो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, सरकार को मोरारका फाउंडेशन से सीखना चाहिए. मोरारका फाउंडेशन अपनी सौर लालटेन परियोजना से गरीबों के जीवन में रोशनी भर रहा है ■

त्वचा कैंसर जानलेवा नहीं है

त्वचा कैंसर क्या है?

त्वचा कैंसर में त्वचा की कोशिकाएं जरूरत न होने पर भी नई कोशिकाओं में बदलती रहती हैं. पुरानी कोशिकाओं का नई कोशिकाओं में बदलना शरीर के लिए सामन्य बात है, लेकिन अगर नई कोशिकाओं के जरूरत न होने पर भी त्वचा की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो त्वचा कैंसर हो सकता है.

त्वचा कैंसर के लक्षण

त्वचा पर रैशेज, तिल या लच्छन (बर्थ मार्क्स) में होने वाले बदलाव त्वचा के कैंसर का लक्षण हो सकता है. त्वचा के कैंसर के दौरान त्वचा पर कई तरह के बदलाव होते हैं जो मेलेनोमा (धूप से होने वाले) या नॉन–मेलेनोमा (बेहद गंभीर) कैंसर के लक्षण हो सकते हैं.

- शरीर के लच्छन यानी बर्थ मार्क्स, तिल में बदलाव, इसके आकार बढ़ने लगे, रंग बदलने लगे, इस पर खुजली हो या खून निकले या तिल के आस–पास का रंग बदले, तो त्वचा कैंसर के शुरूआती लक्षण हो सकते हैं.
- त्वचा पर अगर धब्बे चार हफ्तों से ज्यादा हों तो यह त्वचा के कैंसर का संकेत हो सकता है.
- एक्जिमा यानी खाज भी त्वचा के कैंसर का लक्षण हो सकता है. खासतौर पर अगर यह समस्या कोहनी, हथेली या घुटनों पर दिखे तो इसे लेकर लापरवाही न बरतें.
- त्वचा पर रोजेशिया की समस्या यानी बहुत अधिक लाली और जलन भी त्वचा के कैंसर का लक्षण हो सकता है. माथा, गाल, ठुड्डी और आंखों के आस–पास की त्वचा लाल हो और उसमें खूब जलन हो तो यह त्वचा कैंसर का संकेत हो सकता है.

त्वचा कैंसर के प्रकार

बेसल सेल कार्सिनोमा–यह कैंसर सबसे सामन्य होता है. यह त्वचा की निचली परत के मूल कोशिकाओं में बढ़ता है. यह धीरे–धीरे बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है. शुरू में ही इसका इलाज कराना जरूरी है. यह कैंसर शरीर के उस भागों में होता है जो कि धूप में अधिक आते हैं, जैसे चेहरा, कान, खोपड़ी आदि.

कारण

धूप में ज्यादा रहने वाले लोग बेसल सेल कैंसर का अधिक शिकार होते हैं. विशेषकर यदि वे श्वेत और नीली आंखों वाले हों या जिनकी त्वचा गोरी हो उन्हें यह बीमारी होने का खतरा अधिक होता है.

सैक्वमस सेल कार्सिनोमा–संयुक्त राज्य अमेरिका में सैक्वमस सेल कार्सिनोमा दूसरा सबसे आम पाया जाने वाला त्वचा कैंसर है.

कारण

सैक्वमस सेल कार्सिनोमा त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित करता है. ज्यादातर मामलों में सैक्वमस सेल कार्सिनोमा, त्वचा के असुरक्षित, दीर्घकालिक सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से होता है. ये आम तौर पर उन लोंगो में पाया जाता है जो लोग ज्यादा समय धूप में बिताते है, विशेष रूप से गोरे और नीली आंखों वाले लोग.

मेलेनोमा– मेलेनोमा कैंसर, यह तीन मुख्य प्रकार के त्वचा कैंसर में सबसे कम देखने को मिलता है, लेकिन यह सबसे घातक हो सकता है. इस कैंसर में गले में सूजन या खुजली महसूस कर सकते हैं, यह शरीर पर कहीं भी हो सकता है. मेलेनोमा में तेजी से घाव बढ़ जाते हहैं जो अक्सर बहु रंग, काले और गुलाबी रंग के होते हैं. जब त्वचा मेलेनोमा का उपचार नहीं किया जाता, तो यह त्वचा से परे शरीर के अन्य भागों में फैलता है, जिससे हालत बहुत गंभीर हो सकती है.

कारण

यह सूरज के संपर्क में ज्याादा रहने के जोखिम के कारण होता है. उन लोगों में आम होता है जिनको बुरा सनबर्न हो गया हो, बहुत सारे मोल्सब हो, गोरी त्वचा हो, या परिवार में किसी को मेलेनोमा हो.

ये तीनो कैंसर थोड़ा अलग दिख सकते हैं, लेकिन आप सभी प्रकार के त्वचा कैंसर के खतरे का उपचार एक ही प्रकार से कर सकते हैं. सूरज की हानिकारक किरणों से बचने के लिए आप एसपीएफ सनस्क्रीन लगाए, टोपी पहने और लंबी आस्तीन का उपयोग कर सकते है.

त्वचा कैंसर से बचाव

त्वचा कैंसर एक गंभीर रोग है और इसकी सही जानकारी और इसके प्रति गंभीर सोच बचाव का सबसे कारगर उपाय है. हालांकि इस समस्या से बचने के लिए कुछ अन्य सावधानियां भी बरती जा सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि त्वचा कैंसर से बचाव कैसे किया जाए.

सनस्क्रीन का प्रयोग

दरअसल सूरज की पराबैंगनी किरणें शरीर में भीतर जाकर कोशिकाओं की आनुवांशिक संरचना को ही बदल सकती हैं. इस कारण त्वचा का कैंसर हो सकता है. इसलिए तेज धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का प्रयोग करें. यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है. कुछ समय पूर्व ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया था कि सनस्क्रीन न सिर्फ सनबर्न से त्वचा की सुरक्षा होती है, बल्कि यह तीन प्रकार के त्वचा कैंसरों से लड़ने वाले सुपरहीरो जीन की भी रक्षा करने में सक्षम होता है.

यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन

अल्ट्रा वॉयलेट किरणें यूवीए और यूवीबी इन दो प्रकार की होती हैं. यूवीए किरणें त्वचा की पिग्मेंटेशन को बढ़ाती हैं, जबकि यूवीबी किरणें टैनिंग और स्किन कैंसर का कारण बनती हैं. इसलिए यूवीए से बचाव के लिए एसपीएफ का चिन्ह और यूवीबी से बचाव के लिए अपने सनस्क्रीन की जांच जरूर कर लें. यूवीबी किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन कम से कम एसपीएफ 30 वाला प्रयोग करें.

आहार भी है मददगार

विटामिन डी की सही मात्रा लें. यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ–साथ त्वचा को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाकर त्वचा कैंसर के खतरे को भी कम करता है. इसके अलावा चाय पिएं इसमें मौजूद एंटी–ऑक्सीडेंट यौगिक त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाते हैं. ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनल स्किन कैंसर से बचाव करता है. आप टमाटर और अंगूर भी खांए.

तेल लगाएं

त्वचा पर तेल मालिश करें. बादाम और नारियल के तेल में प्राकृतिक तौर पर एसपीएफ होता है. वहीं रसभरी के बीज के तेल में एसपीएफ 30 तथा गेहूं के तेल में विटामिन ई होता है जो आपको एसपीएफ 20 प्रदान करता है.

त्वचा का इलाज

सर्जरी–बेसल सेल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का आसानी से मामूली सर्जरी और त्वचा की सतह का दवाओं के साथ इलाज किया जा सकता. सर्जरी विकिरण या रसायन चिकित्सा के बाद की जाती है. सर्जरी शरीर में ऊतकों के एक क्षेत्र को नष्ट कर सकती हैं. हालांकि, इन तकनीकों में त्वचा को काटने के लिए नलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

रेडियोथेरेपी—ऊर्जा किरणों और कणों का उपयोग (प्रोटॉन, फोटॉनों या इलेक्ट्रानों) कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है. विकिरण उपचार शरीर के बाहर केंद्रित रहते हैं और त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी के साथ प्राथमिक उपचार भी किया जाता है. विकिरण भी अन्य उपचारों के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक्ससिशनल सर्जरी

इसमें कैंसर के आस–पास के त्वचा के साथ सुरक्षा के कारणों से उसके चारों तरफ के सामान्य त्वचा को हटाने के लिए स्केलपेल का प्रयोग करते हैं. सर्जरी के आस–पास के घाव को टांके के साथ बंद कर दिया जाता है. इससे इसका इलाज 92 प्रतिशत तक सही हो जाता है.

रेडिएशन

रेडिएशन से इलाज में कैंसर के ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है. ट्यूमर को ठीक करने के लिए सीधे एक्स–रे किरणे उस पर डाली जाती हैं इसके लिए मरीज को एनेसेथीसिया के जरिए बेहोश भी नहीं करना पड़ता. ट्यूमर को समाप्त करने कलिए लंबे उपचार की आवश्कता होती है, एक सप्ताह के दौरान ही कई बार इसकी देख–रेख करनी पड़ती है. इलाज के बाद सफल इलाज का प्रतिशत 85 से 95 प्रतिशत तक है. त्वचा के रोगों के लिए इस तरह के इलाज का प्रयोग किया जाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> कई तरह के शोधों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस आतंकी संगठन के लिए लडने वालों में 20 से 30 प्रतिशत संख्या ऐसे लोगों की है जो विदेशी हैं. इन शोधों में उन लोगों को बाहर रखा गया है जो सीरिया, इराक के आस–पास के देशों के हैं. अभी तक दुनिया में कोई भी वास्तविक राज्य ऐसा नहीं है जिसकी मिलिट्री में इतनी संख्या में विदेशी लडाके मौजूद हों. इसके मुकाबले में फ्रांस की लीजन आर्मी के बारे में बात की जाए तो इसकी संख्या देश की मुख्य आर्मी की सिर्फ 2 प्रतिशत है.

अन्य देशों के मुकाबले

कितना मजबूत है आईएसआईएस

दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका समेत कई देशों ने हमले शुरू कर दिए हैं. ये सभी देश इन आतंकियों की कमर तोड़कर इराक को इनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं. लेकिन इन हमलों के बीच यह जानना जरूरी है कि आखिर आईएसआईएस कितना मजबूत है? इसके पास कितने आतंकी हैं और इनकी आय का स्रोत क्या है, जिसके जरिए ये इतनी अमानवीय हरकतें कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं. ये आतंकी समूह सिर्फ जमीन पर ही आतंक नहीं फैला रहा है बल्कि यह आभासी दुनिया में सोशल साइटों पर भी काफी ज्यादा सक्रिय है. इसे लेकर हाल में अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें आईएसआईएस यानी इस्लामिक राज्य की तुलना विश्व के अन्य वास्तविक राज्यों से की गई. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट आईएसआईएस को वास्तविक राज्यों की तुलना में कहां खड़ा पाती है...

आईएसआईएस के आतंकियों ने इराक और सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं उसने बाकायदा पुराने इस्लामिक राज्य की तरह अपना खलीफा भी घोषित कर दिया. लेकिन जबकि ये अपने आपको एक स्वतंत्र राज्य कहता है बहुत सारे लोग इसे मानने को तैयार नहीं है. आखिर लोग इस बात को मानें ही क्यों? आखिर एक आतंकियों के साम्राज्य को एक वास्तविक देश के रूप में मान्यता क्यों मिले? लेकिन अलग–अलग क्षेत्रों में इसकी ताकत का जायजा लेने की आवश्यकता है कि आखिर जो देश इस पर हमला कर रहे हैं उन्हें किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है.

क्षेत्रफल

अमेरिका के नेशनल काउंटर टेरेरिज्म के हिसाब से आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा कब्जाया गया पूरा क्षेत्रफल लगभग 81,000 स्क्वायर मील का है. हालांकि इस क्षेत्रफल को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है. इसकी दो वजहें हैं. पहली, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन इलाकों में आतंकी लड़ रहे हैं उसे भी वे उनका जीता हुआ क्षेत्र मानते हैं जबकि कुछ विद्वान सिर्फ उन्हीं इलाकों को आईएसआईएस के अधीन मानते हैं जिन्हें उसने जीत लिया है. मतलब एक तरफ जहां जीते हुए इलाकों को ही इसके साम्राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं उन इलाकों को भी जीता हुआ मानकर चल रहे हैं जहां ये अभी लड़ ही रहे हैं.

दूसरी वजह, कुछ विद्वान सिर्फ उन्हीं इलाकों की गणना करते हैं जिनमें लोग रहते हैं जबकि कुछ उन इलाकों को भी आईएसआईएस के अधीन ही मानते हैं जहां पर कोई निवास नहीं करता है. अगर ऐसे इलाकों को जोड़ दिया जाए जहां कोई रहता नहीं है तो आईएसआईएस का पूरा क्षेत्रफल इंग्लैंड से कम नहीं निकलेगा. अगर ऐसे इलाकों को लिया जाए जहां लोग नहीं रहते हैं, तो आईएसआईएस का क्षेत्रफल लगभग अमेरिका के वर्जिनिया से इलियॉनायस की दूरी तक भी निकलेगा.

युद्ध में लगे सैनिकों और आतंकियों की तुलना

आईएसआईएस के बारे में माना जाता है कि उसके पास लगभग कुल 20,000 आतंकियों की फौज है. वहीं सीआईए के अनुमान के मुताबिक आतंकियों की संख्या 35,000 है. अगर इसे सही माना जाए तो इनकी आर्मी मेडागास्कर की मिलिट्री की संख्या 21,600 के बराबर है. जो लगभग दुनिया के चौथे सबसे बड़े द्वीप की सुरक्षा में तैनात हैं. कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले ऑस्टिंग लांग के मुताबिक अगर आप ऐसे आतंकियों की गणना करेंगे जो इस्लामिक राज्य की संकल्पना को तैयार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनकी संख्या काफी कम है. लेकिन अगर आप उनके बारे में बात करेंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बाद में इससे जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. दूसरे वाले समूह में ऐसे सुन्नी लोगों की संख्या ज्यादा है जो इराक से शियाओं की सरकार को गिराना चाहते हैं लेकिन वे खलीफा की अवधारणा में विश्वास नहीं करते. ऐसे लोगों का एकमात्र लक्ष्य शियाओं की सरकार को गिराना है न किसी आतंकी खलीफा को विश्व के मुसलमानों का नेता घोषित करना. उनके लक्ष्य क्षेत्रीय हैं और स्वार्थ.

विदेशी लडाकों की संख्या

हालांकि दुनियाभर के नेता इस बात पर काफी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि आखिर क्यों दुनिया के अलग–अलग इलाकों से मुसलमान आईएसआईएस का समर्थन कर लड़ाई लड़ रहे हैं. कई तरह के शोधों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है इस आतंकी संगठन के लिए लड़ने वालों में 20 से 30 प्रतिशत संख्या ऐसे लोगों की है जो विदेशी हैं. इन शोधों में उन लोगों को बाहर रखा गया है जो सीरिया, इराक के आस–पास के देशों के हैं. अभी तक दुनिया में कोई भी वास्तविक राज्य ऐसा नहीं है जिसकी मिलिट्री में इतनी संख्या में विदेशी लड़ाके मौजूद हों. इसके मुकाबले में फ्रांस की लीजन आर्मी के बारे में बात की जाए तो इसकी संख्या देश की मुख्य आर्मी की सिर्फ 2 प्रतिशत है. लीजन में सिर्फ विदेशी ही सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं.

तेल उत्पादन

इस्लामिक स्टेट द्वारा कब्जाई गई जमीन में बहुत से तेल के कुएं आते हैं. वाल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक इन कुओं से प्रतिदिन तकरीबन तीस हजार से सत्तर हजार बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है. संभव है कि यह संख्या एकदम सही न हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट उससे कम ही उत्पादन कर पाता है जितना कि साधारणतया दिखाया जाता है. वहीं अगर एक मोटे तौर पर इस्लामिक स्टेट के तेल उत्पादन के मुकाबले अगर बहरीन को रखा जाए तो हम पाएंगे कि प्रतिदिन यह देश पचास हजार बैरल ही तेल उत्पादन करता है. वहीं मिसीसिप्पी में प्रतिदिन 66,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है.

राजस्व

तेल उत्पादन, विदेशी और स्वदेशी नागरिकों के अपहरण से आने वाली कमाई, बैंक डकैती और दूसरे संस्थानों की लूट से आईएसआईएस प्रतिदिन लगभग 1 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई कर रहा है. उसकी यह कमाई वेटिकन की कमाई के बराबर है. हालांकि आईएसआईएस की कमाई के बारे में यह सिर्फ एक मोटा अनुमान है, क्योंकि उसकी कमाई के बारे में कोई एकदम सही डाटा मौजूद नहीं है. यह एक अनुमान है जो कई शोधों के जरिए निकाला गया है.

ट्वीटर पर समर्थन

इंटरनेट टेक्नोलॉजी के एक शोधकर्ता स्टेफैन टूवे के मुताबिक बीते 18 अगस्त से 3 सितंबर के बीच ट्वीटर पर इस्लामिक स्टेट के पक्ष में 27,000 बार ट्वीट किए गए. उन्होंने बताया कि हमने आईएसआईएस के बारे में बात करने वाले लगभग सभी ट्वीटर अकाउंट को खंगालने के बाद एक तरीका निकाला कि यह देखा जाए कि आखिर कौन लोग हैं जो इसके समर्थन में बोल रहे हैं. इसके लिए हमने एक शब्दावली तैयार की जिसमें ऐसे शब्दों को रखा गया जो इस्लामिक स्टेट के लिए नर्मदिल रखने वाले थे. हमने पाया कि लगभग ऐसे 27,000 ट्वीट थे. अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए तो आईएसआईएस के बार में बात करने वाले लोगों में लगभग 11 प्रतिशत ऐसे थे जो इस संगठन के साथ नर्मदिली रखते थे. वहीं जब हमने देखा कि इस्लामिक स्टेट पर ट्वीट करने वाले इन लोगों में फ्रांस के बारे में सिर्फ 13 प्रतिशत पक्ष में थे जबकि चीन के बारे में तो यह प्रतिशत सिर्फ 10 था. इसके अलावा एक और बात जो मुख्य रूप से बाहर निकलकर आई वह यह है कि इस्लामिक स्टेट ट्वीटर पर अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा विषय है जिस पर सबसे ज्यादा बात चीत हो रही थी. इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि जिस दौरान हमने यह रिसर्च किया उस दौरान सभी समाचार चैनल इस्लामिक स्टेट की खबरों से पटे पड़े हुए थे.

सोशल मीडिया पर सक्रियता

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाल में एक अभियान को लांच किया जिसका स्लोगन था रन, डू नॉट टॉक टू आईएसआईएस लैंड. इसकी लांचिंग में उन्होंने एक वीडियो का भी इस्तेमाल किया था. हाल के दौरान यह एक प्रवृत्ति देखी गई है कि उन अकाउटों को रोका जा रहा है, आईएसआईएस के बारे में ज्यादा चर्चा करते है. सिर्फ इतना ही नहीं इसमें उन समूहों को डिलीट भी किया जा रहा है जो ग्रुप बनाकर इसके बारे में बाते कर रहे हैं. लोगों इस बात से रोकने की कोशिशें हो रही हैं कि वे इन आतंकी संगठनों के बहकावे में न आ जाएं. लेकिन इसके बावजूद भी आईएसआईएस के आतंकी दूसरी साइटों के जरिए लोगों से संपर्क साधने में कामयाब हो रहे हैं.

शादी और बच्चों के लिए धन

शादी और उसके बाद बच्चों के लिए दिए जाने वाले धन को इस्लामिक स्टेट में काफी मान्यता मिली हुई है. सीरियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट के मुताबिक प्रत्येक लड़ाके को शादी के बाद 1200 डॉलर के अलावा रहने के लिए एक बेहतरीन अपार्टमेंट मिलता है. इसके अलावा प्रत्येक बच्चे और पत्नी के लिए उसे 50 और 100 डॉलर दिए जाते हैं. अगर इसके मुकाबले बात की जाए फीनलैंड जैसे देश की जो अपने नागरिकों का ख्याल रखने में बहुत आगे हैं, तो वे भी इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते. इस्लामिक स्टेट पत्नी को उसके पति का संपत्ति मानता है.

सस्ते उपहार

इस्लामिक स्टेट का स्लोगन लगे हुए टी शर्ट बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हैं. उसे वेबसाइटों के जरिए भी बेचा जा रहा था. अब इस तरह की वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई है. वहीं व्हाइट हाउस अपने प्रशंसकों से ऐसी ही टी शर्ट के लिए कम से कम 19 डॉलर की उम्मीद करता है. सिर्फ टी शर्ट ही नहीं ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो आईएसआईएस के नाम पर अन्य देशों की तुलना में कम दाम पर बिकते हैं. ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक कंपनी आईएसआईएस के स्लोगन वाली बिकनी भी बाजार में उतारी थी, लेकिन उसे बाजार में आते ही तुरंत रोक लगा दी गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढ़ेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढ़ेर को कैसे सुलगाया जाए. तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पडा. उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा देखो, हवा में चिंगारी उड रही है. इसे पकड़कर ढ़ेर के नीचे रखकर फुंक मारने से आग सुलग जाएगी. हां हां! कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे.

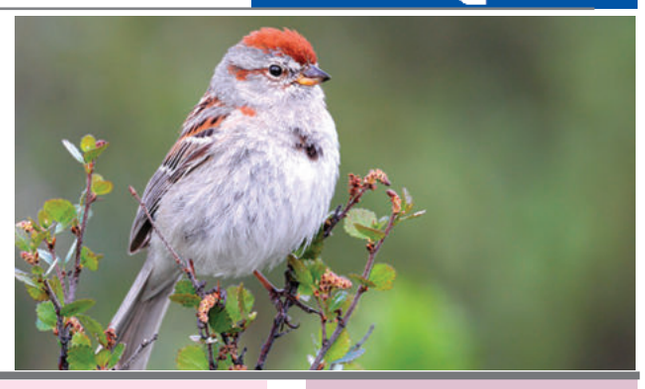

समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिरडी के साई बाबा योगी, फकीर और गुरु थे, जिन्हें हिन्दु और मुसलमान संत कहते हैं और उनकी आराधना करते हैं. साई बाबा ने प्रेम, क्षमा, मदद, सेवा, संतोष, मन की शांति व ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति का नैतिक पाठ पढ़ाया. हालांकि, साई बाबा ने लिखित रूप में कुछ नहीं छोड़ा. प्राणी मात्र की पीड़ा हरने वाले साई हरदम कहते हैं कि मैं मानवता की सेवा के लिए ही पैदा हुआ हूं. मेरा उद्देश्य शिरडी को ऐसा स्थल बनाना है, जहां न कोई गरीब होगा और न ही अमीर. कोई खाई, कैसी भी दीवार बाबा की कृपा पाने में बाधा नहीं बनती. बाबा कहते हैं, मैं शिरडी में रहता हूं, लेकिन हर श्रद्धालु के दिल में मुझे ढूंढ सकते हो. एक के और सबके. जो श्रद्धा रखता है, वह मुझे अपने पास पाता है. वह वही बोले, जो हर संत ने कहा. बाबा कहते हैं कि सबको प्यार करो, क्योंकि मैं सब में हूं. अगर तुम पशुओं और सभी मनुष्यों को प्रेम करोगे, तो मुझे पाने में कभी असफल नहीं होगे. यहां मैं का मतलब साई की स्थूल उपस्थिति से नहीं है. साई तो प्रभु के ही अवतार थे और गुरु भी, जो अंधकार से मुक्ति प्रदान करते हैं. इष्ट से सामीपता का संयोग ईश्वर के प्रति भक्ति और साई गुरु के चरणों में श्रद्धा से ही बनता है. सभी पापों का नाश करने वाले साई ने साफ कहा, एक बार शिरडी की धरती छू लो, हर कष्ट छूट जाएगा. बाबा के चमत्कारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन स्वयं साई नश्वर संसार और देह को महत्व नहीं देते थे. भक्तों को उन्होंने सांत्वना दी थी कि जब पार्थिव देह न होगी, तब भी तुम मुझे अपने पास

दूसरे दिन जब वह महिला बाबा के भक्त कलेकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण-कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है. दादा भट के घर जाकर पूरनपोली तैयार करो. अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ. कोली के दिन थे और इस समय केलकर मासिक धर्म से थी.

पाओगे. अहंकार से मुक्ति और संपूर्ण समर्पण के बिना साई नहीं मिलते. कृपापुंज बाबा कहते हैं, पहले मेरे पास आओ, ख़ुद को समर्पित करो, फिर देखो. वैसे भी जब तक मैं का व्यर्थ भाव नष्ट नहीं होता, प्रभु की कृपा कहां प्राप्त होती है. साई ने भी चेतावनी दी थी, एक बार मेरी ओर देखो, निश्चित रूप से मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा. वर्ष 1854 में बाबा शिरडी आए और 1918 में उन्होंने देह त्याग दी. चंद दशकों में वह सांस्कृतिक-धार्मिक मूल्यों को नई पहचान दे गए. मुस्लिम शासकों के पतन और ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत का यह समय सभ्यता के विचलन की वजह बन सकता था, लेकिन साई सांस्कृतिक दूत बनकर सामने आए. उन्होंने जन-जन की पीड़ा हरी और उन्हें जगाया, प्रेरित किया युद्ध के लिए. युद्ध किसी शासन से नहीं, कुरीतियों से, अंधकार से और हर तरह की गुलामी से भी! यह सब कुछ मानव मात्र में असीमित साहस का संचार करने के उपक्रम की तरह था. हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई और सिख, हर धर्म और पंथ के लोगों ने साई को अपना आदर्श माना और उनकी राह पर चले. इसी से जुड़ी एक कहानी का आगे जिक्र है. बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया. उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है. प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती. यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता न हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे. सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को उचित भोजन व शांति मिलती है तथा जब वे बलिख़रहती है, तब ही हम भक्ति और ईश्वर-प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं, इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन. भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है. बाबा की एक भक्त केलकर काशीबाई काननिटकर से बाबा के बारे में जानाकारी लेकर शिरडी आईं. वे यह निश्चय कर के आई थीं कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर तीन दिन तक उपवास करूंगी. उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा कलेकर से कहा कि मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नही देख सकता. यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहां वर्तमान में रहने का फायदा ही क्या है. दूसरे दिन जब वह महिला बाबा के भक्त कलेकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण-कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है. दादा भट के घर जाकर पूरनपोली तैयार करो. अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ. कोली के दिन थे और इस समय केलकर मासिक धर्म से थी. भट के घर में काना बनाने वाला कोई न था. इसलिए उन्होंने स्वयं भोजन तैयार किया और सबको खिलाकर स्वयं खाया. साई बाबा ने ऐसे ही विचारों से एक सुंदर शिक्षा दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाटकों की दुनिया

उम्मीदों पर खरा उतरेंगे मोदी

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं है. निश्चित रूप से भारतवासी परिवर्तन के सुनहरे युग में प्रवेश कर रहे हैं. इस बात की खुशी है कि अब भारतीय समजा जागृत हो रहा है. देश के लोकतंत्र में सबकी आस्था और विश्वास बढ़ा है. आवाम मतदान के प्रति जागरूक हुआ है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान साफ देखने को मिला. अपने आप को सेक्यूलर बताने वाली पार्टियों का एक साथ लामबंद होना पूरी तरह विफल हो गया. इसलिए देश की संस्कृति और पथनिरपेक्षता पर भरोसा करने वाले हिन्दु और मुसलमान दोनों ने मिलकर भाजपा को कमान सौंपी. इस बार मतदाताओं ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और सम्प्रदाय की राजनीति करने वालों को सिरे नकार दिया और उसने विकास के नाम पर मतदान किया. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों के मन में उसके खिलाफ आक्रोश था. कांग्रेस ने महंगाई कम करने के वादे को भी पूरा नहीं किया. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 महीनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.

-अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

खत्म न हो सब्सिडी

केन्द्र सरकार तेल और गैस पर जो सब्सिडी देती है उससे तेल कंपनिया घाटे में हैं. कंपनिया बार-बार यही कहती हैं. लगता है इसलिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी खत्म करने के मूड में है. अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बृद्धि से यह घाटा बढ़ता ही जा रहा है फिर भी एक लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व है कि वह गरीब जनता को रहात दे और उसका दर्द बांटे. इसलिए रसोई गैस पर सब्सिडी जारी रहनी चाहिए. कोई आदमी कार चलाना छोड़ सकता है, बाइक की जगह साइकिल चला सकता है, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता.

-राजकिशोर पाण्डेय(प्रहरी), लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश.

कोयला घोटाला

कवर स्टोरी-ज्वाइंट वेंचर के नाम पर एक और कोयला घोटाला (15 सितंबर-28 सितंबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. शशि शेखर का आलेख पढ़कर लगता है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उद्योगपत्तियों को लाभ पहुंचाने में लगी हैं. केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या को देखते हुए राज्य सरकारों को मुफ्त कोल ब्लॉक आवंटित किए कि राज्य सरकारें सस्ती दरों पर बिजली उत्पादन कर सकें, लेकिन राज्य सरकारें बिजली उत्पादन करने के बजाय गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाएंगें न खाने देंगे, लेकिन जिन राज्यों में यह घोटाला हुआ उनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार वाले राज्य भी शामिल हैं. इस घोटाले की जांच होनी चाहिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

-राजेश कुमार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

समृद्धि लाएं प्रधानमंत्री

आलेख-भारत: एक बाज़ार या एक राष्ट्र?(15 सितंबर-28 सितंबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक विचार है. कमल मोरारका ने सही कहा है कि प्रधानमंत्री से कौन मिला कौन नहीं मिला. लेकिन अभी जनता को यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं? क्योंकि जो समस्याएं यूपीए सरकार के दौरान थीं वहीं समस्याए भी हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के सौ दिन बीतने के बाद भी जनता को महंगाई से आज तक कोई राहत नहीं मिल पाई है, जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह 100 दिन में महंगाई कम करेंगे. असल मुद्दा है कि क्या भारत एक राष्ट्र से ज्यादा एक बाजार हो गया है? लेकिन देश में चल रही गतिविधियों पर नजर डालें तो यही समझ में आता है कि भारत एक राष्ट्र से अधिक बाजार बन गया है, क्योंकि जापान, अमेरिका से लेकर चीन तक भारत को एक राष्ट्र से ज्यादा बाजार के रूप में देखते हैं. नरेंद्र मोदी को भी उद्योगपतियों का पसंदीदा माना जाता है और उद्योगपति भी अपने लिए बाजार और सरकार से अपने लिए लाभ चाहते हैं. कुछ भी हो प्रधानमंत्री ने जो देशवासियों से वादा किया है उस पर अमल करें और देश में समृद्धि लाएं.

-उपेन्द्र दीक्षित, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

जिम्मेदारी समझे कांग्रेस

जब तोप मुकाबिल हो-कांग्रेस को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए(15 सितंबर-28 सितंबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि कांग्रेस इस समय आंख फोड़कर पड़ोसी का अपशकुन करने की योजना बनाती दिखाई दे रही है. कांग्रेस पार्टी के नेता हार के बाद समीक्षा और किस प्रकार पार्टी को खड़ा किया जाए इसके बजाय पार्टी में एक दूसरे खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं. कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान जो गलती की वही गलती फिर कर रही है. अन्ना आंदोलन और रामदेव आंदोलन से देश में एक माहौल बना, जिसका फायदा भाजपा को हुआ. कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दो को लकेर लोगों के मन में गुस्सा था, जिसके कारण देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को देश की सत्ता सौंप दी. इसलिए कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों से सबक ले. कांग्रेस को चाहिए कि जनता के बीच जाए और उनकी समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाए. कांग्रेस को संसद से लेकर सड़क तक लेकर एक सशक्त विपक्ष की तरह नजर आना होगा.

-रविन्द्र सिन्हा, भागलपुर, बिहार.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कहानी

मूर्ख को सीख

एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोसला था. एक दिन कड़ाके की ठंड पड रही थी. ठंड से कांपते हुए तीन चार बंदरो ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया. एक बंदर बोला कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है. दूसरे बंदर ने सुझाया देखो, यहां कितनी सूखी पत्तियां गिरी पडी हैं. इन्हें इकट्ठा कर हम ढ़ेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं. बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढ़ेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढ़ेर को कैसे सुलगाया जाए. तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पडा. उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा देखो, हवा में चिंगारी उड रही है. इसे पकड़कर ढ़ेर के नीचे रखकर फुंक मारने से आग सुलग जाएगी. हां हां! कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौडने लगे. पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थे. उससे चुप नहीं रहा गया. वह बोली बंदर भाइयो, यह चिंगारी नहीं हैं यह तो जुगनू है. एक बंदर क्रोध से गौरैया को देखकर गुर्राया मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह. हमें सिखाने चली है. इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया. जुगनू को ढ़ेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढ़ेर में फुंक मारने. गौरैया ने सलाह दी भाइयो! आप लोग गलती कर रहें हैं. जुगनू से आग नहीं सुलगेगी. दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए. बंदरों ने गौरैया को घूरा. आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी भाइयों! आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकडियों को आपस में रगड़कर देखिए. सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खीजे हुए थे. एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा. गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई.

शिक्षा : मूर्खों को सीख देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> यह कालचक्र घुरबीगना का जीवन चक्र बन गया है. ब्रह्मबेला में मुर्गे की आवाज़ के साथ उसकी कर्मठ श्रमशिक्त दिनचर्या शुरू होती है और अर्द्धरात्रि को पारण कर उसके व्रत का पुरश्चरण होता है. उसका पूरा कुनबा इसी तरह कतरा–कतरा जी रहा है, रफ्ता–रफ्ता मर रहा है. तथापि यह तीसरा जानवर कभी कहीं किसी से कोई गिला–शिकवा नहीं करता. घुरबीगना यह शाश्वत सत्य अच्छी तरह जानता है कि कमजोर जानवर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने से शक्तिमान के विरुद्ध बुदबुदाए.

खाक हुआ दिल जलते–जलते

अनंत विजय

तुम मुझे हारमोनियम, तबला और लोता दे दो, तो मैं यादगार गीत तैयार कर सकता हूं. मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन अपने बंगाली उच्चारण की वजह से जीवनपर्यंत लता मंगेशकर को लोता ही कहते रहे. लता मंगेशकर को सचिन देव बर्मन अपने गीतों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, लेकिन दोनों के बीच लंबे वक्त तक मनमुटाव रहा. उस दौर के बॉलीवुड को जानने वाले लता मंगेशकर एवं सचिन देव बर्मन के बीच के लंबे मनमुटाव को अलग–अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं. फिल्म संगीत पर लिखने वाले कई लेखकों का दावा है कि फिल्म–सितारों से आगे के एक गाने–पग ठुमक चलत बल खाए की रिकॉर्डिंग को लेकर दादा और उनकी लोता के बीच मनमुटाव हुआ.

कहा जाता है कि सचिन देव बर्मन इस गाने की रिकॉर्डिंग को लेकर खुश नहीं थे और वह इसे फिर से गवाना चाहते थे. उन्होंने अपने सहायक जयदेव की मार्फत लता मंगेशकर को इस बावत संदेश भिजवाया, तो लता ने कहा कि अभी उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वह विदेश जा रही हैं. दादा ने एक बार फिर संदेश भेजा कि विदेश से लौटकर रिकॉर्ड करा दें, लेकिन लता की ओर से ठोस जवाब न मिलने पर वह कुपित हो गए और उनसे गाना न गवाने का फ़ैसला किया. दादा बर्मन ने जयदेव के ही मार्फत संदेश भिजवा दिया कि उन्हें लता की ज़रूरत नहीं है. अगर हम इन दोनों के बीच के रिश्तों की बारीकी में जाएं, तो यह लगता है कि पहले से कुछ गड़बड़झाला चल रहा था. लता गाती रहेगी, तो गीत– संगीत चलता रहेगा जैसी बात कहने वाले सचिन दा लता के पास जयदेव के मार्फत संदेश भिजवाते हैं. लता का गाना पसंद न आने पर उनसे खुद बात नहीं करते हैं, यह संकेत संबंधों में आए ठंडेपन को तो इंगित करता ही है. सत्या सरण की सचिन देव बर्मन की नई किताब–सुन मेरे बंधु रे में इस प्रसंग पर विस्तार से चर्चा नहीं है, सिर्फ़ संकेतों में बात की गई है.

सत्या सरण ने अपनी इस किताब में इस बात का दावा किया है कि फिल्म बंदिनी के गानों से सचिन देव बर्मन एवं लता मंगेशकर के बीच रिश्तों की बर्फ पिघली थी. सत्या सरण ने लिखा है कि फिल्म बंदिनी के गाने–मोरा गोरा अंग लै ले, मोहे शाम रंग दै दे की रिकॉर्डिंग पर दोनों मिले. सत्या सरण के इस दावे के पर भी अलग–अलग लोगों की अलग–अलग राय है. कई लोगों का कहना है कि 1962 की फिल्म डॉ. विद्या के गाने–पवन दीवानी न माने, उड़ावे मोरा घूंघटा से लता की वापसी हुई. पर मोटे तौर पर इस बात पर फिल्म के जानकारों में एक राय है कि डॉ. विद्या, बंदिनी और मेरी सूरत तेरी आंखें के गानों से लता की सचिन देव बर्मन कैंप में वापसी हुई थी. सचिन देव बर्मन की आदत थी कि वह अलग–अलग मूड के गानों के लिए अलग–अलग गायकों का चयन करते थे. जब हिंदी सिनेमा में नायकों के लिए गायकों की आवाज़ तय थी, तो उस दौर में सचिन देव बर्मन ने अलग–अलग फिल्मों के नायकों के गाने भी अलग–अलग गायकों से गवाए. देवदास में वैजयंती माला पर फिल्माए गाने–अब आगे तेरी मर्जी, मोरे सैंया, मोरे बलमा को सचिन देव बर्मन ने लता मंगेशकर से गवाया था, क्योंकि उनका मानना था कि ठुमरी एवं मुजरा शैली के गाने लता बेहतर तरीके से गा सकती हैं. इसी तरह उन्होंने देव आनंद को अलग–अलग फिल्मों में अलग–अलग गायकों की आवाज़ दी. सचिन देव बर्मन अपने संगीत को लेकर बेहद आश्वस्त रहते थे. यही आश्वस्ति उनकी ताकत

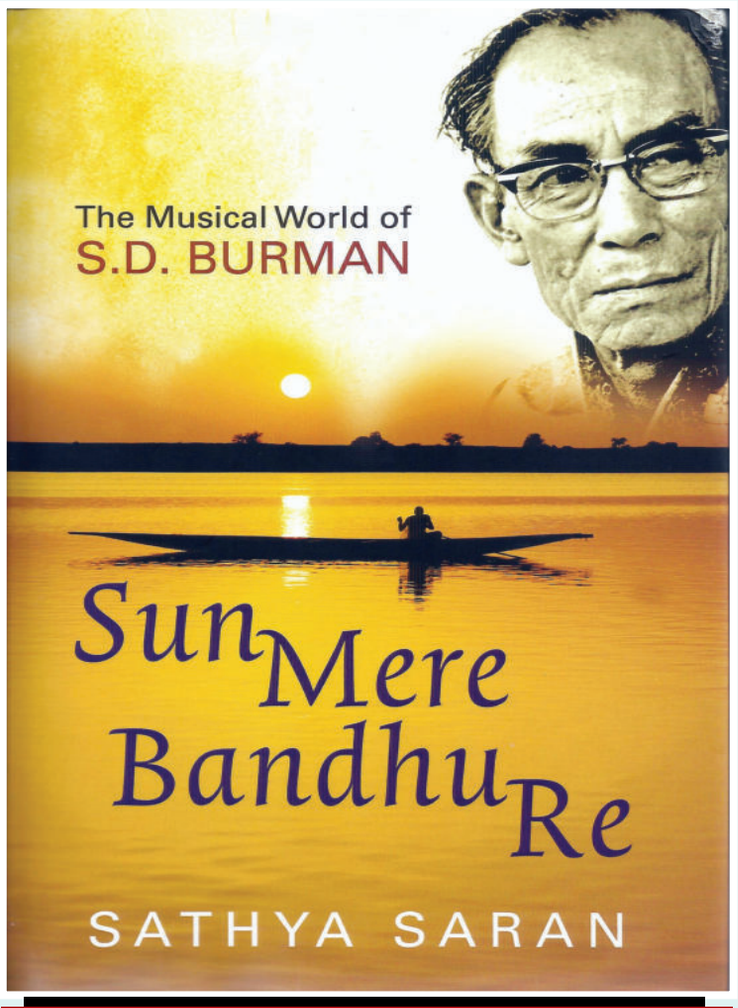

समीक्ष्य पुस्तक–सुन मेरे बंधु रे
लेखिका–सत्या सरण
प्रकाशक–हॉर्पर कॉलिंस, नोएडा, उत्तर प्रदेश
मूल्य–499 रुपये

थी और कभी–कभार यही आश्वस्ति उनके अहम को भी बढ़ा देती थी. इसी के चलते कभी उनका टकराव साहिर से हुआ, कभी उन्होंने गुलजार को नाराज़ कर दिया, कभी लता से बोलचाल बंद, तो कभी मुकेश से खुंदक.

इसी तरह सत्या सरण ने अपनी किताब में गुलजार के मोटर गैराज में काम करते हुए गीतकार बनने की कहानी का भी जिक्र किया है, लेकिन गुलजार के हवाले से. गुलजार उस वक्त एक मोटर गैराज में पेंटर का काम करते थे, लेकिन शैलेंद्र के संपर्क में थे. शैलेंद्र ने उन्हें बिमल राय से मिलने की सलाह दी. पहले गुलजार हिचकिचाए, पर शैलेंद्र के कहने पर उनसे मिलने चले गए. अब विडंबना देखिए, गुलजार ने उस वक्त शैलेंद्र से कहा था कि उनकी रुचि साहित्य में है, फिल्मों के लिए गीत लिखने में नहीं. उसके बाद मोरा गोरा अंग लै ले की सफलता ने गुलजार को पहचान दी. लेकिन, इस एक गाने के बाद सचिन देव बर्मन ने गुलजार को दरकिनार कर दिया, क्योंकि शैलेंद्र से उनके गिले–शिकवे दूर हो गए थे. गुलजार के लिए सचिन देव बर्मन की यह उपेक्षा एक अवसर लेकर आई. गुलजार के प्रति सचिन देव बर्मन के रवैये को देखते हुए बिमल रॉय ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया. सचिन देव बर्मन की ज़िंदगी में इस तरह के खट्टे–मीठे कई अनुभव हैं. उन्हीं अनुभवों एवं घटनाओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्र करके वरिष्ठ फिल्म पत्रकार सत्या सरण ने यह किताब–सुन मेरे बंधु रे तैयार की है.

सत्या सरण की इस किताब में सचिन देव बर्मन के बचपन से जुड़ी कहानियां हैं और फिर मुंबई में उनके संघर्ष और सफलता की गाथा भी. सचिन देव बर्मन के मन में बचपन से ही संगीत को लेकर एक जबरदस्त आकर्षण था. वह त्रिपुरा राज परिवार के वारिस थे. उनका जन्म कुमिल्ला शहर में हुआ था, जो त्रिपुरा राज्य का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद बांग्लादेश में चला गया. सचिन देव बर्मन को संगीत विरासत में मिला. उनके पिता गीत–संगीत के प्रेमी थे और उनके दरबार में संगीत की महफिलें आम थीं. संगीत की पहली शिक्षा उन्हें अपने पिता से ही मिली. कालांतर में सचिन ने उस्ताद बादल खान एवं भीष्म देव चट्टोपाध्याय से तालीम हासिल की. इन दोनों की संगत में शास्त्रीय संगीत में उनकी बुनियाद मजबूत हुई. उस्ताद अलाउद्दीन खान की सोहबत में उन्होंने बांसुरी बजाने में महारथ हासिल की.

फिल्मी दुनिया में उनके प्रवेश की कहानी भी दिलचस्प है. पंकज मलिक की फिल्म यहूदी की लड़की के लिए उन्होंने गाना गाया था. कुछ वजहों से उनका गाना हटाकर उसे पहाड़ी सान्याल से गवा लिया गया. सत्या सरण की इस किताब के ब्लर्ब पर इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि संस्मरणों, साक्षात्कारों एवं लेखों आदि के आधार पर इसमें सचिन देव बर्मन की ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश की गई है. तथ्यों को नैरेटिव के माध्यम से दिलचस्प बनाने का दावा भी किया गया है. किताब पढ़ने के बाद यह बात साफ़ तौर पर उभर कर आती है कि सचिन देव बर्मन पर अब तक जितना कुछ छपा है, उसके चुनिंदा अंश इकट्ठा कर उनकी जीवनी का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है. हो सकता है कि यह प्रयोग सफल हो और नए पाठकों को पसंद आए, लेकिन इससे फिल्म के गंभीर पाठकों को सचिन देव बर्मन के बारे में न तो कोई नई जानकारी मिलती है और न कोई नया तथ्य सामने आता है. हालांकि सत्या सरण ने बेहद सावधानी से अपने को विवादित प्रसंगों से अलग रखते हुए दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

तीसरा बैल

अवध बिहारी ओझा

सांझ के धुंधलके में गधबेर होने पर कार्तिक की हलवाहीं से तीन जीवों का प्रत्यागमन. दिन भर कड़ेर कठिन पथराइल करैत खेत जोतने की श्लघता और पैने की चोट से आहत तथा जवानी के मद से मत्त मस्ती को जताने के लिए गर्दन में बंधी घंटी को टुनटुनाते दो बैल. पीछे–पीछे हल जुआठ के बोझ से सिकुड़ा, दुहरा होता हुआ घुरबीगना हलवाहा. बैलों के गर्दन की घंटी की टुनटुनाहट सुनते ही दरवाजे पर उपस्थित पुरुष वर्ग बगबगा कर हरकत में आ गया. सभी फुसफुसाने लगे, बैल आ गए, बैल आ गए. बिजली के वेग से पानी, खली, दाना, भूसा, महुआ आदि भोज्य की तैयारी शुरू हो गई. एक–दो सवांग आगे बढ़कर सहलाते हुए बैलों को नाद–चरण पर ले आए, बिल्कुल वीआईपी की तरह. सभी लोग अपना काम छोड़कर वृषभ सेवा में व्यस्त हो गए, मानों बैल उनके धनसुत हों. वृषभ सेवा से फुर्सत मिलते–मिलते अंधेरा हो चला और तब जाकर कोने में सुटुके हुए बेचारे घुरबीगना हलवाहे पर नज़र पड़ी बड़े मालिक की. उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, तू यहां क्यों बैठा है रे? यह हलवाही से लौटा तीसरा बैल है, घुरबीगना हलवाहा. वस्तुत: बैल भी नहीं, पशु श्रेणी में बैल से भी निम्न स्थान पाने वाला जानवर.

मालिक के प्रश्नोत्तर में घुरबीगना सहमा–सहमा मिमियाया, बनि चाहिए. सुनते ही बुढ़ऊ मालिक डपट पड़े, रोज–रोज बनि दिया जाता है? हफ्ता पूरा होने पर बनि लेना सीखो. वैसे भी अभी दूबेरा की संधि–बेला है और ऐसी घड़ी में कुछ लेना–देना वर्जित है. इस पर घुरबीगना धीरे–से घिघियाया, घर में खर्ची के नाम पर कुछ भी नहीं है, लड़के–फड़के दिन से ही भूखे होंगे. बुढ़ऊ मालिक अभी आंख गुंडेर ही रहे थे घुरबीगना पर कि घुरबीगना की घिघियाहट पर तरस खाकर उनका अर्द्धशिक्षित पोता टुमुका, दे ना दीजिए. खाएगा नहीं, तो दिन भर देह–जांगर कैसे ठेटाएगा? पांडे बाबा के हलवाहा की तरह बीडीओ ऑफिस चला जाएगा, तब समझ में आएगा. बुढ़ऊ मालिक गरज पड़े, तुम से कौन पूछता है, जो वकालत छांट रहे हो. पढ़ाई में तो हर साल फेल ही करते हो, लेकिन मेरी बात काटने में सीआर दास बैरिस्टर बन जाते हो. चउवनिया मुस्कुराहट के साथ वह युवक पुन: टुमुका, जाइए, हम नहीं बोलेंगे. हल जुतवाने से यदि संतोष नहीं होता है, तो

घुरबीगना की नस में छुंछी लगाकर सीरिंज से दो बोतल खून निकाल लीजिए, काम आएगा. बेचारे बुढ़ऊ मालिक को दबना पड़ा. वह नरम आवाज़ में बोले, ऐ भाई, आजकल की पढ़ाई में क्या यही सिखाया जा रहा है? खैर, मारो गोली. ऐ बड़कू, बूढ़ी से बोल दो बनि देने के लिए.

छह महिनवा नन्हका पोता को तेल में अबटती और उससे बड़े गोद में खेलने वाले गोदिलवा पोता को माड़–भात खिलाती बुढ़िया मलिकाइन के कान में जब यह संदेश पड़ा, तो अपनी व्यस्तता से जरा भी विचलित हुए बिना वह बड़बड़ाईं, मार मटिलगवना रे, यह भी कोई समय है बनि का और उसी स्वर में पोती को आदेश दिया, अरे असतुरनी, देखो तो बनि वाला बटखरा कहां है? (यह ग्रामीण शाश्वत सत्य है कि बनि वाला बटखरा सामान्य बटखरा से वजन में न्यून होता है और उसका प्रयोग बनि तौलने के अतिरिक्त नहीं होता.) अंधकार में भी टटोलते हुए असतुरनी ने येन–केन–प्रकारेण बनि वाला बटखरा खोज तो लिया, लेकिन काफी समय लगाकर. तत्पश्चात मातृरूपा बुढ़िया मलिकाइन ने बनि तौल कर घुरबीगना के गमछे में बांधकर दरवाजे पर भिजवा दिया. घुरबीगना को सदा की तरह पता था कि गमछे में बंधा या तो गेहूं होगा अथवा धान, बना–बनाया आटा या चावल नहीं. इसके बावजूद उस गठरी को पाकर घुरबीगना इस तरह अगराया, जैसे कोई हुंडी मिल गई हो. इस अंतराल में बैलों को स्वाद बदलने के लिए चोकर–चलौंसी बार–बार नाद में छिड़का गया, मालिक लोगों के लिए नाश्ता आया, चाय की प्यालियां खनखनाईं, बुढ़ऊ मालिक की चिलम गरमाई, लेकिन घुरबीगना की ओर किसी ने दृष्टिपात नहीं किया.

और दिनों की तरह ही घुरबीगना के घर के सभी आबाल–वृद्ध बनि के अनाज को पीसने–छांटने में व्यस्त हो गए. इन सभी से चिंतामुक्त घुरबीगना ज्यों ही टूटी खटोली में लेटा, फोंय–फोंय उसकी नाक बजने लगी. आधी रात को रसोई तैयार होने पर घुरबीगना की पत्नी ने उसे जगाकर खाना खिलाया. अन्न की खुमारी से घुरबीगना पुन: गहरी नींद में सो गया. शुक्रतारा की चमक पराकाष्ठा पर ही थी, ब्रह्मबेला के पूर्व वाले तारे अभी भी स्पष्टत: झिलमिला रहे थे और घुरबीगना की सुषुप्ति अभी जवानी पर थी, तभी मझिला मालिक आलाप लेते पहुंचे, अर्द्धरात्रि गए कपि नहीं आवा. घुरबीगना के दरवाजे पर पहुंचते–पहुंचते कर्कश आवाज में हंकड़े, सोए ही रहोगे? आज छपटा बधार में हल चलेगा. शीघ्र तैयार हो जाओ, दो मील जाना है. जैसे रिंग मास्टर के हंटर की सांय–सांय की आवाज़ सुनते ही सर्कस के बाघ कांपने लगते हैं, वैसे ही घुरबीगना भयाक्रांत होकर खाट पर से उछल पड़ा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि पहलवान मझिला मालिक के हाथ के निछोही घावे मारे हुए चटकन से जो बाम शरीर पर पड़ता है, तो वह तीन दिनों तक परपराता है, छनछनाता है.

यह कालचक्र घुरबीगना का जीवन चक्र बन गया है. ब्रह्मबेला में मुर्गे की आवाज़ के साथ उसकी कर्मठ श्रमशिक्त दिनचर्या शुरू होती है और अर्द्धरात्रि को पारण कर उसके व्रत का पुरश्चरण होता है. उसका पूरा कुनबा इसी तरह कतरा–कतरा जी रहा है, रफ्ता–रफ्ता मर रहा है. तथापि यह तीसरा जानवर कभी कहीं किसी से कोई गिला–शिकवा नहीं करता. घुरबीगना यह शाश्वत सत्य अच्छी तरह जानता है कि कमजोर जानवर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने से शक्तिमान के विरुद्ध बुदबुदाए. कोई विधान या संविधान बने, कोई मुखिया–प्रधान चुना जाए, परंतु इस तीसरे जानवर का उद्धार नहीं हो सकता है. ■

***(लेखकीय टिप्पणी:** यह कहानी उन दिनों लिखी गई थी, जब खेती बैलों द्वारा होती थी और बैल किसान के दरवाजे की शान होते थे.)*

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय बाजार में यह 2 इन 1 कम्प्यूटर 19,990 रुपये में उपलब्ध होगा. डिवाइस में इंटेल टोम प्रोसेसर जेड3735डी और 8.1 विंडोज है. साथ इसमें 7900 एमएएच की लिथियम पॉलिमर बैटरी है. इसमें 2 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी है. डिवाइस में पहले से ही बिजनेस ऐप्स लोडेड हैं.

हार्ड डिस्क, फ़्लैश मेमोरी, सीडी रोम की क्षमता

निर्धारित क्षमता से कम क्यों ?

श्याम सुन्दर प्रसाद

जब कभी आप एक नई हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा की रैपर या कवर पर दर्शित क्षमता और कम्प्यूटर में लगाने के बाद दिख रही स्टोरेज क्षमता में अंतर दिखाई देता है. कभी–कभी आप यह देखकर चौंक जाते हैं. ऐसा आखिर हुआ क्यों यह जान बगैर कभी–कभी आप अपने दुकानदार या निर्माता कंपनी पर इस बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं. कि उसने आपको गलत जानकारी देकर चीज थमा दी है उसने आपके साथ धोखा किया है. लेकिन हक़ीकत में इसमें विक्रेता या निर्माता की कोई गलती नहीं होती है.

आखिर ऐसा क्यों होता है?

डिफाइन स्टोरेज मेमोरी और रियल स्टोरेज मेरोरी में अतर होने के कई कारण होते हैं. लेकिन इस अंतर का सबसे प्रमुख कारण आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम या कहें आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है. यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा सिस्टम की शैडो फाइल्स और फॉर्मेटिंग ओवरहेड के कारण होता है इस वजह से आपकी डिवाइस सही मेमोरी क्षमता नहीं दिखाती है. इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं मान लीजिए आपने एक 500 जीबी (गीगा बाइट) की एक हार्ड डिस्क खरीदते हैं, कंप्यूटर में ये कितनी क्षमता दिखाएगा.

एक निर्माता कंपनी के अनुसार 8 बिट (Bit) के बराबर 1 बाइट (Bytes) होता है, उसी तरह 1000 किलो बाइट (KB)के बराबर 1 मेगा बाइट (MB), 1000 मेगा बाइट (MB) बराबर 1 गीगा बाइट (GB), 1000 गीगा बाइट (GB) बराबर 1 टेरा बाइट (TB) इत्यादि होता है. यह वास्तविक मानक जैसे किलो मतलब 1000 और मेगा मतलब 1000000 (10^6) मानता है. वहीं दूसरी तरफ जहां कम्प्यूटर के प्रोग्राम्स जैसे की बायोस, विंडोज, मैक व अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाइनरी नंबर सिस्टम (बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रोग्राम केवल 0 और 1 को समझता है) का प्रयोग करता है जिसका आधार 2 होता है.

बाइनरी नंबर सिस्टम में 8 बिट (Bit) के बराबर 1 बाइट (Byte) होता है, उसी तरह 1024 किलो बाइट (KB) बराबर 1 मेगा बाइट (MB), 1024 मेगा बाइट (MB) बराबर 1 गीगा बाइट (GB), 1024 गीगा बाइट (GB) बराबर 1 टेरा बाइट (TB) इत्यादि होता है.

मेमोरी में कमी का मुख्य कारण यही गणना का अंतर का होता है, क्योंकि की एक निर्माता कंपनी 1000 केबी=1 एमबी को आधार मान कर अपना उत्पादन करता है और जबकि हम कम्प्यूटर के द्वारा प्रयोग किए जा रहे 1024 केबी =1 एमबी को आधार मान कर उसके अनुसार अपनी मेमोरी को देखते हैं.

अब एक उदहारण के जरिए गणना करते हैं और देखते है की 500जीबी के किसी हार्ड ड्राइव में कितना अंतर आता है. एक निर्माता के दृष्टिकोण के 500 जीबी के किसी हार्ड ड्राइव में 500X1000X1000X 1000=500000000000 बाइट होता है,वहीं एक कम्प्यूटर के बाइनरी डेटा के अनुसार 500 जीबी में 500X1024X1024X1024 = 536870912000 बाइट होगा. इस प्रकार हमें जो गणना के नतीजे मिले हैं उससे पता चलता है की जैसे ही 500 जीबी का हार्ड डिस्क कम्प्यूटर से जुड़ेंगी वो 536870912000–500000000000=36870912000 बाइट (लगभग 36.34) जीबी स्पेस कम दिखाई देगा, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं की 500 जीबी की खरीदी गई हार्ड ड्राइव वास्तविक में 465.66 जीबी की होती है.

इस लेख के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपके द्वारा खरीदी गई पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम एवं हार्ड ड्राइव में बताए गए स्पेस से कम स्पेस दिखाई देता है. इसलिए अब दोबारा इसके लिए किसी कंपनी या दुकानदार के साथ झगड़ा मत कीजिएगा. ये आंकड़ों का खेल है इसे समझकर आप चाचा चौधरी के दिमाग से भी ज्यादा तेज दिमाग होने का दावा कर सकते हैं. ■

smart7973@gmail.com

दिमाग पढ़ने वाला ऐप्प

अब आप अपने स्मार्ट फोन से पता लगा सकते हैं कि आप अवसाद या तनाव में हैं या नहीं. शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है, जो उपयोगकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रदर्शन और व्यवहार के बारे में जानकारी देता है. छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन, उनकी खुशी, तनाव, अवसाद और अकेलेपन के बारे में देने वाला स्टूडेंट लाइफ ऐप्प नामक इस एप्लीकेशन का प्रयोग सामान्य लोग भी मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करने, कार्यालय में कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए कर सकते हैं. शोधकर्ताओं ने 10 सप्ताह की अवधि में 48 छात्रों के स्मार्टफोन के सेंसर की रीडिंग के माध्यम से उनके मानसिक स्वास्थ्य (अवसाद,तनाव,अकेलापन) शैक्षिक प्रदर्शन और व्यवहारों का आकलन किया. यह एप्प बता सकता है कि किस तरह तनाव, नींद और जिम जाने से कॉलेज के काम, मध्यावधि और अंतिम परीक्षाओं में बदलाव आता है. सेंसर के आंकड़ों के आंकलन और उच्चस्तरीय अनुमान के लिए फोन में कंप्यूटेशनल पद्धति और मशीन लर्निग कलन विधि (अल्गोर्थम) का प्रयोग किया गया.

हालांकि स्मार्टफोन एप्प गोपनीयता की चिंताएं बढ़ाता है, लेकिन जगह में उपयुक्त सुरक्षा के साथ, तनाव के लक्षणों का इंतजार किए बिना यह ऐप्प लगातार लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर सकता है. ■

सोनी का स्मार्ट आई ग्लास

सोनी ने अपने पहले आई वियर की घोषणा की है. सोनी ने इसे स्मार्ट आई ग्लास टेक वर्ल्ड में गूगल ग्लास को मिली भारी सफलता के बाद, अब सोनी ने भी अपने इसी तरह के उत्पाद को लेकर आई है. सोनी ने इसे स्मार्ट आई ग्लास नाम दिया है. कंपनी का यह पहला स्मार्ट आई वियर है. सोनी इसे अगले साल लॉन्च करेगी. इसमें विविध रेंज की टेक्नोलॉजी के अलावा सीओमओएस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, ब्राइटनेस सेंसर, माइक्रोफोन भी है. ये फीचर्स स्मार्टफोन के जीपीएस लोकेशन में भी मदद करेगें. सोनी ने इसके लैंस को बनाने में अपनी यूनिक होलोग्राम ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है. इसकी वजह से यह 85 फीसदी हाई ट्रांसपेरेंसी एचीव करेगा. इसकी मोटाई 3.0 एमएम है. स्मार्ट आई ग्लास में मोनोक्रोम डिस्प्ले है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी. इसके हाई लूमीनेन्स की वजह से स्क्रीन बेहतर होगी और यूजर्स दूर तक लिखी हुई चीजों को भी आसानी से पढ़ सकेंगे. सोनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है. ■

सैमसंग गैलेक्सी मेगा–2

सैमसंग का गैलेक्सी मेगा–2 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है. पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी मेगा फैबलेट का लेटेस्ट मॉडल मेगा–2 को केवल थाइलैंड में लॉन्च किया गया है. इस फोन भारतीय बाजार में दिवाली से पहले आने की उम्मीद है. भारतीय रुपये के हिसाब से इसकी कीमत 24000 रुपये होगी. इस फैबलेट में 6 इंच की स्क्रीन दी गई है. सैमसंग की मेगा सीरीज में पहले ही सैमसंग गैलेक्सी मेगा 6.2 और गैलेक्सी मेगा 5.8 शामिल हैं. अब नया मेगा 2 इन दोनों के बीच के साइज 6 इंच की टीएफटी एचडी स्क्रीन के साथ आया है और यह 720 गुणा 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. यह फैबलेट एंड्रॉयड किटकैट 4.4 पर आधारित है. इसकी बैटरी 2800 एमएएच की है. साथ ही इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर और 1.5 जीबी की रैम दी गई है. इसके अलावा 8 जीबी की इंटरनल मेमोरी और एसडी कार्ड की मदद से 64 जीबी तक मेमोरी बढ़ाने की सुविधा है. इस फैबलेट में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लेड फ्लैश और 2.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4जी एलटीई, वाई–फाई, माइक्रोयूएसबी, ब्लूटूथ जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं.■

इंटेल प्रोसेसर के साथ 2 इन 1 पीसी लॉन्च

नोशन इंक कंपनी और ई–रिटेलर के साथ मिलकर इंटेल ने कैन टैबलेट भारतीय बाजार में पेश किया है. यह सबसे सस्ता टैबलेट है. इंटेल ब्रान्डिंग चिपमेकर ने टैबलेट सीरीज के लेटेस्ट टैबलेट के प्रचार–प्रसार की कमान नोशन इंक और ई–टेलर को दी है. भारतीय बाजार में यह 2 इन 1 कम्प्यूटर 19,990 रुपये में उपलब्ध होगा. डिवाइस में इंटेल टोम प्रोसेसर जेड3735डी और 8.1 विंडोज है. साथ इसमें 7900 एमएएच की लिथियम पॉलिमर बैटरी है. इसमें 2 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी है. डिवाइस में पहले से ही बिजनेस ऐप्स लोडेड हैं. इसमें ऑफिस ऐप्स है, जो एक साल के लिए फ्री है. वहीं, वायरलेस की–बोर्ड और माउस कोम्बो दिया गया है. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 19,990 रुपये रखी गई है.■

1699 CC इंजन की दमदार बाइक

पिछले कुछ दिनों में कई दमदार बाइकें लॉन्च हुई हैं. बाजार में बाइकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनिया एक के बाद एक बाइक लॉन्च कर रही है.

ट्रिम्फ थन्डरबर्ड एलटी

ट्रिम्फ मोटरसाइकिल ने थन्डरबर्ड एलटी लॉन्च की है, जिसकी कीमत लगभग 15.75 लाख रुपये है. यह बाइक 1699 सीसी की है, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है. इसका इंजन 5400 आरपीएम पर 94 बीपीएस की पावर देता है और 3550 आरपीएम पर 151 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस बाइक मे 22 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. इसका वजन 339 किलोग्राम है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

संन्यास की घोषणा के बाद बिंद्रा ने कहा कि शूटिंग अब मेरी हॉबी है अब मैं बेस्ट शूटर नहीं हूं. इसलिए मैं इन नतीजों से काफी संतुष्ट हूं. यदि मैं विश्वकप के लिए क्वालीफाई करता हूं तो उसमें हिस्सा लूंगा, यदि क्वालीफाई नहीं कर सका तो जूनियर खिलाड़ियों की मदद करूंगा.

अभिनव बिंद्रा भारतीय निशानेबाज़ी का स्वर्णिम सितारा

अभिनव बिंद्रा ने 12 साल की उम्र में जब अपने कंधे पर रायफल उठाई थी तभी से उनके कंधों पर देश की आशाओं का बोझ आ गया था. हर किसी को उनसे पदक की आस थी लंबे समय तक वह लोगों की आशाओं के बोझ से पार नहीं पा सके. इस वजह से वह लंबे समय तक एशियाई और ओलंपिक खेलों में पदक नहीं जीत सके, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब हैं, जिनपर भी इनका सुरूर चढ़ा उसे नींद नहीं आती, अभिनव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया और हर तरह के दबाव से उबरकर देश को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाया. उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश की सवा अरब जनता का उन पर विश्वास बेमानी नहीं था

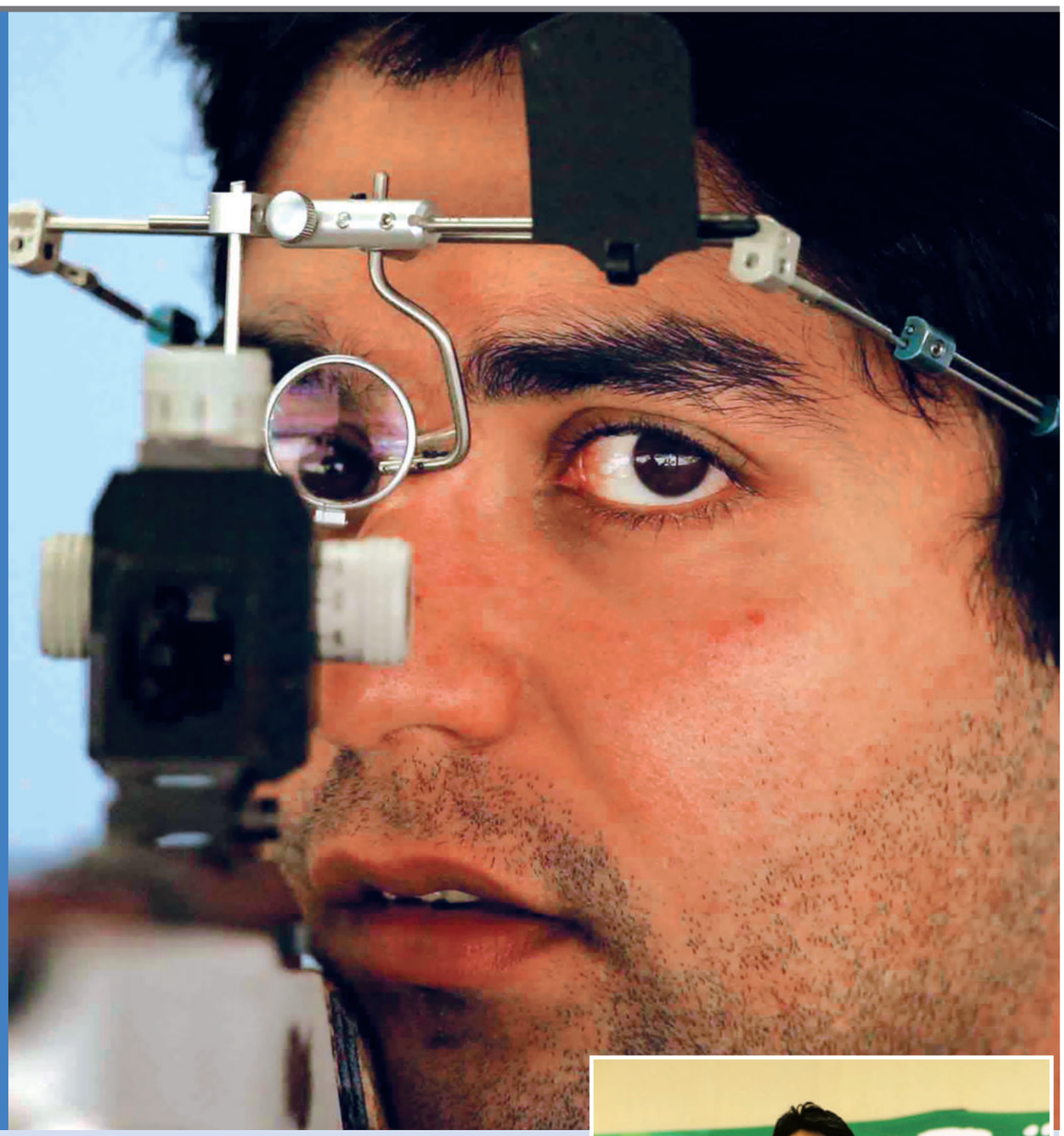

चौथी दुनिया ब्यूरो

देश के पहले और एक मात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा अब पदकों पर निशाना लगाते नहीं दिखाई देंगे. उन्होंने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में अपने प्रोफेशनल शूटिंग करियर का आखिरी निशाना लगाया और करियर का संभवतः आखिरी पदक जीता. उन्होंने 10 मीटर एयर रायफल की व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धा (संजीव राजपूत और रवि कुमार के साथ) का कांस्य पदक जीता. बिंद्रा ने कांस्य पदक जीतकर अपनी विदाई को बेरंग होने से बचा लिया. एशियाई खेलों का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने के बाद बिंद्रा ने कहा कि मैं अब अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में नहीं हूं. वह दौर बहुत पहले गुजर चुका है. बिंद्रा ने यह भी कहा कि शूटिंग अब मेरी हॉबी है अब मैं बेस्ट शूटर भी नहीं हूं. इसलिए इन नतीजों से काफी संतुष्ट हूं. यदि मैं विश्वकप के लिए क्वालीफाई करता हूं तो उसमें हिस्सा लूंगा, यदि क्वालीफाई नहीं कर सका तो जूनियर खिलाड़ियों की मदद करूंगा.

इसे किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास ही कहा जाएगा 20 साल लंबे करियर के बाद भी उसमें जीत की ललक बरकरार है. 32 साल के हो चुके अभिनव बिंद्रा ने इंचियोन में अपने इवेंट के पहले कहा कि मैं रियो ओलंपिक में पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरे जीवन में बहुत से अच्छे मौके आए, मुझे लगता है कि आगे भी कुछ और ऐसे मौके आएंगे. इसके साथ ही उन्होंने बड़ी सादगी से ट्विटर पर संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि कल के बाद मेरा प्रोफेशनल शूटिंग करियर खत्म हो जाएगा. हालांकि इसके बाद मैं शौकिया तौर पर शूटिंग करता रहूंगा और सप्ताह में दो बार अभ्यास करूंगा. 20 साल लंबे करियर के बाद भी मैं दुनिया के 15 सर्वश्रेष्ठ शूटर्स में से एक हूं. मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हूं और बेहतर करने के लिए प्रयासरत हूं.

वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक में सातवें पायदान पर रहने के बाद अभिनव ने उस समय को डार्केस्ट ऑवर इन हिस करियर (करियर का सबसे खराब समय) करार दिया था. अभिनव ने अपनी आत्मकथा अ शॉट एट हिस्ट्री में क्रिकेट और गोल्फ खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि इन खेलों में खिलाड़ी एक बार असफल होता है तो उसे स्वयं को साबित करने के लिए कई मौके मिलते हैं लेकिन एक ओलंपियन को खुद को साबित करने के लिए चार साल लंबा इंतजार करना पड़ता है.

बिंद्रा ने 12 साल की उम्र में जब अपने कंधे पर रायफल उठाई थी तभी से उनके कंधों पर देश की आशाओं का बोझ आ गया था. हर किसी को उनसे पदक की आस थी लंबे समय तक वह लोगों की आशाओं के बोझ से पार नहीं पा सके. इस वजह से वह एशियाई और ओलंपिक खेलों में लंबे समय तक पदक नहीं जीत सके, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब हैं, जिनपर भी इनका सुरूर चढ़ा उसे नींद नहीं आती, अभिनव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया और हर तरह के दबाव से उबरकर देश को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाया. उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश की सवा अरब जनता का उन पर विश्वास बेमानी नहीं था. अभिनव बचपन में बंदूको से खेलते थे. उनका रुझान इस ओर बहुत था, परिवार ने उनके इस टैलेंट को पहचाना और 11 वर्ष की उम्र में उन्हें निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिलवाना शुरू किया. जब अभिनव जिला स्तर पर एक शूटिंग प्रतियोगिता जीती तो उनके कोच ने अभिनव के पिता एएस बिंद्रा से कहा कि उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई जानी चाहिए. इसके बाद अभिनव को जर्मनी के मशहूर शूटिंग स्कूल जर्म स्कूल ऑफ राइफल शूटिंग में कोचिंग के लिए भेजा गया. अभिनव साल में दो महीने के लिए जर्मनी जाते रहे. ये सिलसिला 15 साल तक चलता रहा. उस समय भारत में अच्छे शूटिंग रेंज उपलब्ध नहीं थे, तब पिता ने अभिनव के अभ्यास के लिए घर में ही आधुनिक शूटिंग रेंज बनवा दी.

ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा हॉकी की स्वर्णिम गाथा के बाद पहला नाम अभिनव बिंद्रा का लिखा जाएगा. भले ही अभिनव एशियाई और ओलंपिक खेलों में पदकों की कतार लगाने में कामयाब नहीं हुए लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सुविधाएं मिले तो भारत खेल के क्षेत्र में भी दुनिया में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है.

15 साल की छोटी उम्र में उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने का मौका मिला. 1998 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे. इसके बाद वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के निशानेबाज थे. उनके खाते में पहली अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि वर्ष 2001 में आई, जब उन्होंने म्युनिख में हुए विश्वकप में जूनियर स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था. वर्ष 2001 में उन्होंने 6 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता इसके बाद वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 10 मी एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत और टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता.

साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड और वर्ष 2001 में देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया. उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से वनाजे जाने पर कई सवाल भी उठे कि क्या उनके पास इस पुरस्कार को पा सकने के लिए उपलब्धियां हैं. लेकिन वह इन विवादों से विचलित नहीं हुए. वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन पदक जीतने से चूक गए. उन्हें सातवें स्थान से संतष करना पड़ा. उनके मन में वह टींस बनी रही, इसके बाद उन्होंने 2006 में विश्वकप में और 2008 में ओलंपिक में निशाना स्वर्ण पदक पर लगाया और इतिहास रच दिया. अभिनव बिंद्रा उनके नाम और विशिष्ट उपलब्धि है कि वह एक साथ 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के विश्व विजेता और ओलंपिक चैंपियन रहे हैं. ऐसा दुनिया में कोई और खिलाड़ी नहीं कर सका है. इसके बाद भारत सरकार ने वर्ष 2009 में अभिनव को खेलों में अभिनव योगदान के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया. बिंद्रा अपने करियर में केवल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, उन्होंने 2010 एशियाई खेलों में पुरुषों की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था. लेकिन वह एशियाई खेलों में व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सके थे. लेकिन उन्होंने 2014 में इंचियोन में कांस्य पदक जीतकर इस कमी को भी पूरा कर दिया.

देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी होना उन्हें देश के दूसरे खेलों के खिलाड़ियों से अलग करता है. उनके ओलंपिक पदक ने देश के खिलाड़ियों के मन में विश्वास जगाया कि भारत भी ओलंपिक में अपना परचम लहरा सकता है. राजनीतिक रस्साकशी के दौर में इस बात को सिद्ध किया कि क्रिकेट के अलावा भी किसी भी खेल में करियर बनाया जा सकता है. पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया जाए तो सफलता जरुर मिलेगी. अपनी आत्मकथा अ शॉट एट हिस्ट्री में बिंद्रा ने बार-बार टाइमिंग पर बल दिया और यह भी बताया कि किसी भी बड़ी प्रतियोगिता के पहले पूरी तैयारी करना कितना जरुरी और कठिन काम है. बिंद्रा की भूमिका भारत में खेलों के लिहाज से भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चमक-दमक और मीडिया की नज़रों में रहने वाले खेलों के जरिए भी देश का नाम रोशन किया जा सकता है. लोगों को इस तरह के खेलों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया.

ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा हॉकी की स्वर्णिम गाथा के बाद पहला नाम अभिनव बिंद्रा का लिखा जाएगा. भले ही अभिनव एशियाई और ओलंपिक खेलों में पदकों की कतार लगाने में कामयाब नहीं हुए लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सुविधाएं मिले तो भारत खेल के क्षेत्र में भी दुनिया में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है. अभिनव ने 2008 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद ही एक फाउंडेशन की शुरूआत की है. वह चाहते थे कि इस फाउंडेशन के जरिए जूनियर खिलाड़ियों की मदद करें. अर्जुन के रुप में उन्होंने देश को बहुत सम्मान और गौरव दिलाया लेकिन द्रोणाचार्य के रुप में वह कितने सफल साबित होंगे यह तो वक्त ही बताएगा. लेकिन जो कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का शिष्य बनेगा उससे आशा की जा सकती है गुरु गुड़ रह जाए और चेला शक्कर हो जाए. देश की इसी में भलाई है.

ग्लासगो में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अभिनव ने स्वर्ण पदक जीता था, इसके बाद एशियाई खेलों में कांस्य पदक. इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह करियर के चरम पर ही शूटिंग को अलविदा कहना चाहते थे. हालांकि उन्होंने अभी भी रियो ओलंपिक और विश्वकप में भाग लेने के लिए संकेत दिए हैं. यदि अभिनव बीजिंग की स्वर्णिम सफलता रियो में दोहराने में सफल हो जाते हैं तो उनका नाम भारत के खेल इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बाद रोहित शेट्टी शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया है. उन्हें ऐश्वर्या की हामी का इंतजार है. यदि रोहित अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो शाहरुख और ऐश्वर्या राय की जोड़ी पूरे 12 सालों बाद बड़े पर्दे पर रोमांस करती दिखाई देगी.

इंटिमेट सीन्स में सहज महसूस करती हैं श्रद्धा कपूर

विशाल भारद्धाज द्वारा निर्देशित फिल्म हैदर में जितनी चर्चा शाहिद के लुक की हो रही है उतनी ही चर्चा शाहिद और श्रद्धा की खूबसूरत जोड़ी की भी हो रही है. फिल्म के ट्रेलर में शाहिद और श्रद्धा की कमाल की केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही है. सूत्रों का कहना है कि सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं पूरे बॉलीवुड की नज़रें इस जोड़ी पर लगी हुई है. फिल्म में शाहिद और श्रद्धा के बीच फिल्माए गए अंतरंग दृश्यों की भी चर्चा हो रही है. शाहिद ने बॉलीवुड में लंबा समय गुजारने के बाद भी अब तक अपनी किसी भी फिल्म में इस तरह के दृश्य नहीं किए हैं, वहीं श्रद्धा की आशिक़ी-2 और एक विलेन जैसी फिल्मों में इंटिमेट सीन्स दे चुकी हैं. हैदर उनकी तीसरी फिल्म होगी जिसमें उन्होंने इंटिमेट सीन को अंजाम

फिल्म में शाहिद और श्रद्धा के बीच फिल्माए गए अंतरंग दृश्य भी चर्चा हो रही है. शाहिद ने बॉलीवुड में लंबा समय गुजारने के बाद भी अब तक अपनी किसी भी फिल्म में इस तरह के दृश्य नहीं किए हैं, वहीं श्रद्धा की आशिक़ी 2 और एक विलेन जैसी फिल्मों में इंटिमेट सीन्स दे चुकी हैं. हैदर उनकी तीसरी फिल्म होगी जिसमें उन्होंने इंटिमेट सीन को अंजाम दिया है.

दिया है. दर्शकों में इस सीन्स को लेकर खासी चर्चा है तो इस पर श्रद्धा का कहना है कि मुझे इंटिमेट सीन से कोई परहेज़ नहीं है. मैं इसमें काफी कंफर्टेबल(सजह) रहती हूं विशेष रूप से हैदर की बात करूं तो इस सीन के दौरान विशाल सर और शाहिद ने मुझे इस कदर कंफर्टेबल कर दिया था कि मुझे लगा मैं सचमुच में अर्शिया हूं. अर्शिया सिर्फ हैदर की गर्लफ्रेंड ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है. एकमात्र अर्शिया है जिससे हैदर खुलकर अपने दिल की बात कहता है और उम्मीद करता है कि उसके पास उसे सुकून के कुछ पल मिले. विशाल की यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के दुखांत नाटक हैम्लेट से प्रेरित है. इस फिल्म में शाहिद और श्रद्धा के अलावा तब्बू और केके मेनन भी नज़र आए. यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

रितिक पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं

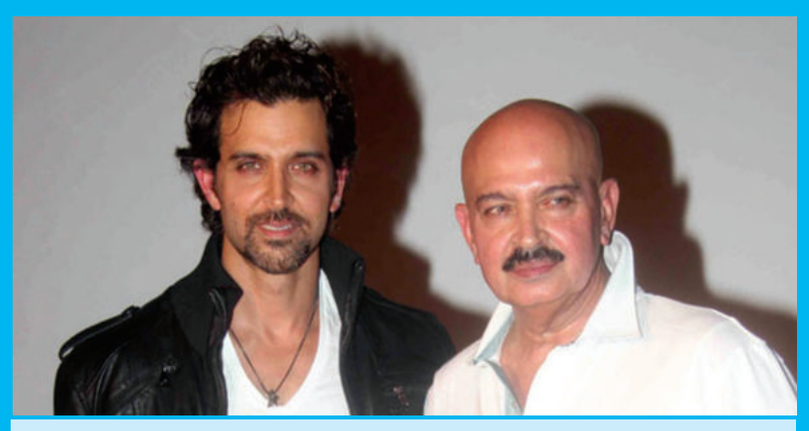

बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता रितिक रोशन अपने पिता राकेश रोशन के नक्शे कदम पर चलना चाहते है. रितिक अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण भी करना चाहते है. उनके पिता आज बॉलीवुड के एक सफल फिल्म निर्माता-निर्देशक हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत उन्होंने अभिनेता के रुप में की थी. बतौर निर्माता-निर्देशक वह कहो ना...प्यार है और क्रिश श्रृंखला की फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. रितिक के फिल्मों में आने से पहले उन्होंने शाहरुख खान के साथ कोयला और करन-अर्जुन जैसी सफल फिल्मों में निर्देशन किया था. हाल ही में रितिक ने कहा कि मौका मिलने पर फिल्म निर्माण भी करूंगा. रितिक फिल्म निर्माण को एक मुश्किल प्रक्रिया मानते हैं. उनका कहना है कि, फिल्म निर्माण करना आसान काम नहीं है. इसके लिए दर्शकों को ध्यान में रखना होता है फिल्में ऐसी होनी चाहिए जिन्हें दर्शक पसंद करें. फिलहाल रितिक अपनी नई फिल्म फिल्म बैंग-बैंग को लेकर खासा उत्साहित हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है, उनके साथ फिल्म में कैटरीना कैफ भी हैं. रितिक इस फिल्म में माइकल जैक्सन की तरह डांस करते नजर आए हैं.■

मैंने कब कहा, मैं सिंगल हूं: प्रियंका

सब कहते हैं कि मैं सिंगल हूं लेकिन मैंने कभी खुद ऐसा नहीं कहा. शादी नहीं होने तक सब सिंगल होते हैं और अगर ऐसा मानें तो कहूंगी-हां, मैं भी सिंगल हूं.

बॉक्सर मेरी कॉम के जीवन पर बनी फिल्म मेरी कॉम में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए तारीफ बटोर रही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वह इतनी भी व्यस्त नहीं है कि अपनी लव लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाएं. उनका कहना है कि मेरे प्रशंसक मेरे करियर, मेरी फिल्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन मेरी निजी जिंदगी को मैं अपने तक ही रखना चाहती हूं. सब कहते हैं कि मैं सिंगल हूं लेकिन मैंने कभी खुद ऐसा नहीं कहा. शादी नहीं होने तक सब सिंगल होते हैं और अगर ऐसा मानें तो कहूंगी-हां, मैं भी सिंगल हूं. किरण बेदी पर बनने वाली फिल्म का प्रस्ताव मिलने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि आजकल मेरे पास काफी फिल्मों के प्रस्ताव आ रहे हैं. हाल ही में मैंने जोया अख्तर की फिल्म की शूटिंग पूरी की है. अगले महीने अन्य दो फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी. एक फिल्म संजय लीला भंसाली की है और दूसरी मेरी खुद की प्रोडक्शन कंपनी की है. अगले साल तक तो मेरे पास समय नहीं है. फिलहाल प्रियंका कई फिल्मों की पटकथा सुन रही हैं.■

रिलीज से पहले ही पीके ने कमाए 85 करोड़

दिसंबर में रिलीज होने वाली आमिर की बहुप्रतीक्षित फिल्म पीके ने रिलीज होने के पहले ही कमाई करना शुरू कर दिया है. खबर है कि पीके के सैटेलाइट राइट्स के लिए बड़ी डील हुई है. पीके के सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ रुपये में बिक गए हैं. यह किसी भी हिंदी फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के लिए हुई सबसे बड़ी डील है. इससे पहले शाहरुख खान की दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सैटेलाइट राइट्स 65 करोड़ रुपये में बिकने की खबर आई थी. पीके के सैटेलाइट राइट्स की डील करते हुए निर्माताओं ने इस बात की गारंटी दी है कि पीके बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी. अगर ऐसा होता है पीके 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म बन जाएगी. आमिर की फिल्म धूम-3 भी 300 करोड़ के आंकड़े को छूने से महज 20 करोड़ के अंतर से चूक गई गई थी. ■

12 साल बाद नजर आएगी ऐश और किंग खान की जोड़ी

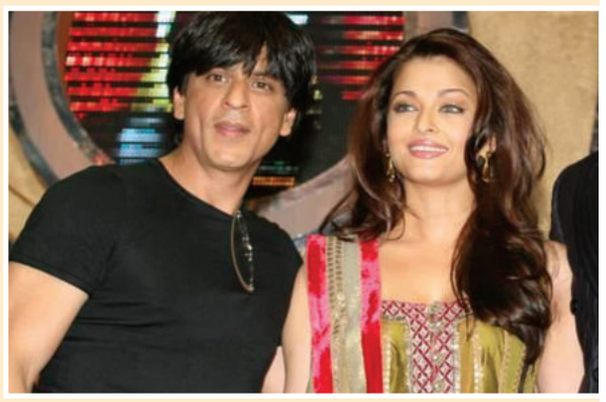

यदि सब कुछ ठीक रहा तो रुपहले पर्दे पर एक बार फिर ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान साथ नज़र आएंगे. चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बाद रोहित शेट्टी शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया है. उन्हें ऐश्वर्या की हामी का इंतजार है. यदि रोहित अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो शाहरुख और ऐश्वर्या की जोड़ी पूरे 12 सालों बाद बड़े पर्दे पर रोमांस करती दिखाई देगी. इन दोनों की जोड़ी आखिरी बार साल संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में नजर आई थी. सबसे पहले दोनों ने एक साथ फिल्म जोश में काम किया था. दोनों ने इस फिल्म में भाई-बहन का किरदार निभाया था. इसके बाद फिल्म मोहब्बतें में दोनों लव कपल बनकर सामने आए. इसके अलावा फिल्म शक्ति के एक आइटम नंबर इश्क कमीना..में भी दोनों की जोड़ी दिखाई दी थी. करीब चार साल के ब्रेक के बाद ऐश्वर्या फिल्मों में वापसी कर रही हैं. वह इरफान खान के साथ फिल्म जज्बा में नजर आएंगी.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

06 अक्टूबर–12 अक्टूबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

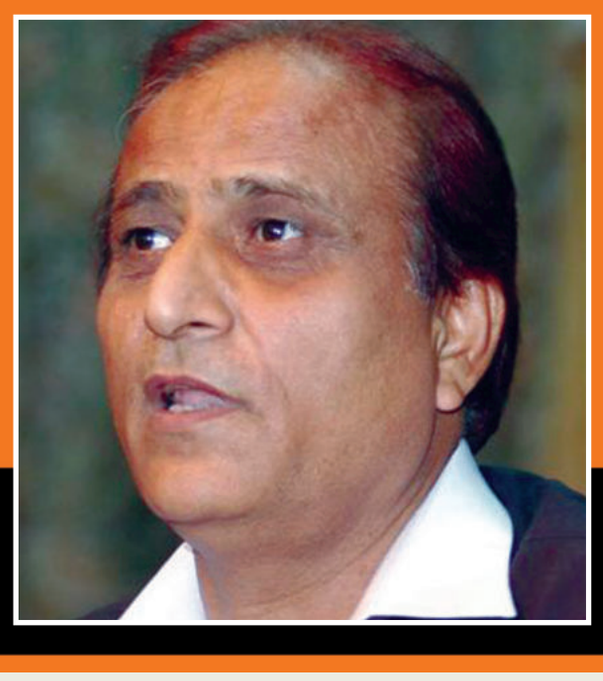

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

सपा के स्थापना के बाद पहली बार लखनऊ में होने जा रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमर सिंह के सपा में वापसी की घोषणा हो सकती है, क्योंकि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क में यह अधिवेशन होना है, उसी के लोकार्पण में मुलायम सिंह यादव के साथ अमर सिंह नजर आए थे. तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमर सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं. सपा का उप चुनाव में जीत के बाद मनोबल सातवें आसमान पर है और वह भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. सपा इसी अधिवेशन में कोयला और बिजली के मुद्दे को लेकर केंद्र से युद्ध की घोषणा कर सकती है.

अमर सिंह की वापसी हो सकती है

केंद्र से युद्ध की घोषणा कर मैदान में उतरेगी सपा

प्रभात रंजन दीन

उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी ऐतिहासिक करने की तैयारी में है. सपा की स्थापना के बाद पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है और पूरी सम्भावना है कि अमर सिंह की वापसी की घोषणा के साथ ही अधिवेशन अपनी ऐतिहासिकता में एक अध्याय और जोड़ ले. अमर सिंह की वापसी हो गई तो आजम खान के रुखसत होने का ऐतिहासिक अध्याय भी लिख जाएगा. पार्टी के अंदर इस बात की भी तैयारी है कि लखनऊ अधिवेशन में केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध की सीधी घोषणा हो. इसके लिए बिजली और कोयला जैसे मुद्दे अहम हैं, जिन्हें सामने रख कर समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेगी.

विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुट गई है. सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव अधिवेशन की तैयारियों को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं. सपा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आठ अक्टूबर से लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित होगा, जिसका लोकार्पण अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें अमर सिंह की मौजूदगी ने इस लोकार्पण समारोह को कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में लाया था. प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अधिवेशन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. अधिवेशन की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भी कि अधिवेशन को यादगार बनाना है. उन्होंने कहा कि जनता अब सभी दलों को पहचान गई है और अब उसकी सारी उम्मीद सपा पर ही टिकी है.

लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाइन क्या लेगी, इस पर मंथन चल रहा है. महागठबंधन की सम्भावनाओं पर भी चर्चा होगी और विकास के एजेंडे पर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बिजली और कोयला पर केंद्र से युद्ध का ऐलान होगा. विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. सपा सरकार पहले से ही इसकी पेशबंदी कर रही है और केंद्र पर हमला जारी रखे हुई है.

महागठबंधन की जरूरत पर भी होगा विचार

प्रजोर ताकत के साथ उभर कर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए छोटी पार्टियों को एकजुट होना होगा, लेकिन कैसे, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ अधिवेशन में माथापच्ची करेंगे. पार्टी का गठन होने के बाद लखनऊ में होने वाला यह पहला अधिवेशन है. पार्टी के स्थापना-अधिवेशन के बाद ही पिछड़ा-दलित गठबंधन का ऐतिहासिक अध्याय लिख गया था. लखनऊ में हो रहे पार्टी के नौवें अधिवेशन में कहीं वैसा ही ऐतिहासिक अध्याय तो नहीं लिखने जा रहा! पूरा अध्याय नहीं भी लिखा, भूमिका तो लिख ही जाएगी. याद करते चलें कि मुलायम सिंह यादव ने 7 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित कर समाजवादी पार्टी के गठन का ऐलान किया था. तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. मुलायम सिंह ने संघर्ष शुरू किया. पिछड़ों और अति पिछड़ों को केंद्र में रखकर बनाई गई समाजवादी पार्टी ने दलितों को भी साथ लेने की रणनीति अख्तियार की थी. उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम से हाथ मिलाया और दलित-पिछड़ों का गठबंधन कायम किया. पार्टी गठन के महज 13 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन को 176 सीटें हासिल हुई. इसमें सपा ने 109 सीटें जीतीं और बसपा को 67 सीटें मिलीं. सरकार बनाने के लिए 213 सीटों की जरूरत थी. भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस व जनता दल ने सपा को समर्थन देकर 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया. लेकिन सपा-बसपा गठबंधन अधिक दिन नहीं चल सका. इस बीच पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के अपहरण से लेकर गेस्ट हाउस कांड तक की तमाम घटना-प्रतिघटना हुई और 1 जून 1995 को गठबंधन टूट गया. बिहार में दो धुर-विरोधियों जदयू और राजद के महागठबंधन ने यह साबित किया कि राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी का कोई स्थायित्व नहीं होता. इसे दृष्टिगत रखते हुए यूपी में भी सपा-बसपा के गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं. कोशिश यह भी है कि मायावती अधिक अड़ंगे डालें, तो बसपा अपने नेतृत्व का विकल्प तलाशे और गठबंधन की अनिवार्यता देखते हुए सपा से हाथ मिला ले.

उप चुनाव में दलित वोटों को हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी का इस दिशा में आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है. यूपी में महागठबंधन की कोशिशें अगर शक्ल ले पाईं तो कई रोचक तथ्य और समीकरण सामने आएंगे, इसमें कांग्रेस की भूमिका भी दिखगी और रालोद की भी... और अमर सिंह की भी. भाजपा का विरोध करने के लिए एकजुट होने के सिवा इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है. ■

बहरहाल, अधिवेशन की तैयारियों में लगे सपा नेताओं में से एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नेतृत्व के शीर्ष गलियारे में अमर सिंह की वापसी का मन बन रहा है और अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अमर सिंह की पार्टी में वापसी की चर्चा कराने की औपचारिकता पूरी करा कर उन्हें शामिल किए जाने की घोषणा कर सकते हैं. अमर सिंह की वापसी में मुलायम परिवार में बना दो खेमा बाधा बन सकता है और रोड़ा बन सकते हैं प्रो. रामगोपाल यादव, जो परिवार के साथ-साथ पार्टी आलाकमान का हिस्सा भी हैं. मुलायम परिवार का एक बड़ा खेमा अमर सिंह के सपा परिवार में दोबारा शामिल कराने का पक्षधर है, लेकिन दूसरा छोटा खेमा इस पक्ष में नहीं है. जहां तक आजम खान का प्रश्न है, तो वे पार्टी में पहले ही किनारे लगाए जा चुके हैं. सपा के एक नेता ने यह भी कहा कि अमर सिंह को पार्टी में शामिल करा कर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है. लेकिन अगर कुछ अड़चन आए तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी समर्थन देकर सपा राज्यसभा तक पहुंचा सकती है और आगे का रास्ता साफ कर सकती है. मोदी लहर के कारण लोकसभा चुनाव में पराजय के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल की पकड़ और उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता. बिहार के महागठबंधन की तर्ज पर एक बृहत्तर छत्रप तानने की कोशिशों में अमर सिंह पार्टी की क्या मदद कर सकते हैं, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है.

राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि इतने दिनों के बाद अमर सिंह को सपा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना, आमंत्रण पर उनका आना, फिर दोबारा अमर सिंह का शिवपाल के घर पहुंचना और मुलायम के आवास पर उनसे और मुख्यमंत्री अखिलेश से मिलना कोई संयोग थोड़े ही है. सपा के नेता भी इसे संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक योग ही बताते हैं और मानते हैं कि इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है. लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद और हार के कारण इस रणनीतिक-अनिवार्यता को और मजबूती मिली है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा नेतृत्व की पेशानी पर बल पड़ रहा है कि पार्टी को कोई ऐसा चमत्कारिक मैनेजर मिले जो राजनीति और तिकड़म दोनों को संतुलन के साथ मैनेज कर ले. इसके लिए पार्टी नेतृत्व को अमर सिंह से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता. लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में अन्य मैनेजरों का परफॉर्मेंस देखा और परखा जा चुका है. मुलायम इस बात पर खास तौर पर चिंतित रहे हैं कि सपा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐसी बुरी हार देखनी पड़ी. उपचुनाव में सपा ने भले ही रेखांकित करने वाली जीत दर्ज की हो, लेकिन उपचुनाव और पूर्ण चुनाव का फर्क मुलायम सिंह जैसे नेता तो समझते ही हैं. लिहाजा, ऐसे संक्रमण काल में सपा को अपने पुराने मित्र अमर सिंह की जरूरत है. अमर सिंह समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर के सारे बारीक पेचोखम से वाकिफ हैं और राजनीतिक समस्या से निकलने और निकालने की उनमें विशेषता है. इसके साथ ही बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ अमर सिंह की घनिष्ठता और फंड मैनेजमेंट की अनिवार्यता भी सपा नेतृत्व को अच्छी तरह समझ में आती है. तभी सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि नेताजी से अमर सिंह की मुलाकात में कुछ गलत नहीं है. अमर सिंह मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे. मित्र होने के कारण नेताजी ने उनसे मुलाकात की, तो इसमें गलत क्या है? अमर सिंह मुलायमवादी हैं और उनका मुलायम सिंह से मिलना कोई अचरज वाली बात नहीं है. शिवपाल के इस बयान के निहितार्थ समझे जा सकते हैं.

बहरहाल, लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाइन क्या लेगी, इस पर मंथन चल रहा है. महागठबंधन की सम्भावनाओं पर भी चर्चा होगी और विकास के एजेंडे पर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बिजली और कोयला पर केंद्र से युद्ध का ऐलान होगा. विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. सपा सरकार पहले से ही इसकी पेशबंदी कर रही है और केंद्र पर हमला जारी रखे हुई है. इसे घनीभूत करने की रणनीति पर अधिवेशन में विचार होगा. केंद्र को कई बार पत्र लिख कर भावी राजनीति की भूमिका तैयार करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को उसके कोटे की बिजली मिलनी चाहिए. यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां बिजली की मांग भी ज्यादा है, इसे केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए. अखिलेश का कहना था कि केंद्र की अनदेखी के कारण कोयला नहीं मिल पाने से प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है. जब तक आवश्यक मात्रा में कोयला नहीं मिलता, तब तक प्रदेश में बिजली उत्पादन की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता. अभी हाल ही एक समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाइक की मौजूदगी में कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार को सौ दिन हुए हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार को छह महीने देने के लिए तैयार हैं. केंद्र को यह समझना चाहिए कि यूपी ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन केंद्र ने प्रदेश को क्या दिया है! मुख्यमंत्री ने ऐसा कह कर तभी भविष्य के राजनीतिक एजेंडे का संकेत दे दिया था.

पार्टी के पिछले अधिवेशन की तरह लखनऊ अधिवेशन उहापोहों वाला अधिवेशन साबित नहीं होगा, तैयारी इसी बात की है. पिछली बार की तरह कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को समर्थन देने की मजबूरी और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भिड़ने की अनिवार्यता का विरोधाभास और साथ-साथ आजम खान की उच्छृंखलता पर कोई कार्रवाई न कर पाने की विवशता जैसी स्थिति भी नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को लेकर सियासत गर्म

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

कैलाश मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भाजपा अब आमने-सामने हैं. नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर चीन और केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है. नया रास्ता खोलने का धर्मनगरी हरिद्वार के कई साधु-संतों ने स्वागत किया है. उत्तराखंड सरकार को नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रास नहीं आ रही है. कैलाश मानसरोवर यात्रा तीन देशों (भारत, नेपाल और चीन) के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी विश्व की एकमात्र व अनूठी पैदल यात्रा है. उत्तराखंड का मार्ग पौराणिक मार्ग है. मान्यता है कि इसी मार्ग से पांडव भी कैलाश गए थे. यात्रा मार्ग में पांडव व कुंती पर्वतों से तथा स्कंद पुराण के मानसखंड में इसकी पुष्टि होती है. इस यात्रा के दौरान करीब 230 किमी की पैदल दूरी (भारतीय क्षेत्र में 60 एवं चीनी क्षेत्र में करीब 150 किमी) चलनी पड़ती है, जिसमें से चीनी क्षेत्र के अधिकांश मार्ग में वाहन सुविधा भी उपलब्ध है. भारतीय क्षेत्र में भी करीब आधे मार्ग में बीआरओ के द्वारा सड़क बन चुकी है. इस पौराणिक मार्ग से तीर्थ यात्रियों को प्राकृतिक रूप से 'ऊं' लिए 'ऊं पर्वत' और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते हैं, साथ ही हिमालय को करीब से निहारने यहां की जैव विविधता व सीमांत क्षेत्र के जनजीवन को जानने-समझने का मौका भी मिलता है. इस मार्ग को पास किया जाने वाला लिपुपास दर्रा भारत-चीन के बीच का सबसे आसान दर्रा भी माना जाता है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को बदलने के निर्णय को उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचाने वाला बताया है. इस निर्णय से न केवल हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भावना को भी चोट पहुंची है. मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यदि व्यापार आदि के लिए अन्य मार्ग को खोला जा सकता है, तो यात्रा के लिए यही मार्ग उचित है. हमारे धर्मग्रंथों में उल्लिखित मार्ग को अपनाते रहे हैं. भगवान शिव इसी मार्ग से हिमालय में मां पार्वती (नन्दा) से मिले थे. ये स्थान यहीं मौजूद हैं, जिन्हें शिव ने स्पर्श किया था. जो पुण्य कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस मार्ग में मिलता है, वह अन्य में नहीं. महान विचारक राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का उल्लेख किया है. स्वामी परमानंद इसी मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि केन्द्र सरकार इस निर्णय को बदलेगी तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग उत्तराखंड से ही रहेगा. राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि इससे प्रदेश का पर्यटन प्रभावित होगा जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की सोच ही नकारात्मक है. भाजपा ने कहा है कि इससे प्रदेश के तीर्थाटन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत तो पिछले कई दिनों से मानसरोवर यात्रा के मार्ग में हुई तब्दीली को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं. प्रदेश के कई स्थानों पर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जोरदार आंदोलन भी शुरू किया जा चुका है. प्रदेश के पर्यटन मंत्री दिनेश धनै भी यात्रा मार्ग बदलने को लेकर केंद्र की आलोचना कर चुके हैं. धनै ने कहा कि यात्रा मार्ग बदलने से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है. अब तो प्रदेश आपदा से ही पूरी तरह से उबर नहीं पाया है. अभी तो केंद्र को हर नज़रिए से राज्य की मदद करनी चाहिए.धनै ने कहा कि प्रदेश को आपदा से उबारने की आवश्यकता है ताकि फिर से पहले की तरह तीर्थयात्री इस प्रदेश में आएं. उन्होंने कहा कि केंद्र के इस फैसले से उत्तराखंड कमजोर होगा और प्रदेश का तीर्थाटन भी प्रभावित होगा. दूसरी ओर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार या कांग्रेस के नेताओं को मानसरोवर यात्रा मार्ग के बदलाव को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग नहीं बदला गया है, नये मार्ग का सृजन किया गया है. रावत ने स्पष्ट कहा कि जो तीर्थयात्री प्रदेश के मार्ग से होकर गुजरना चाहते हैं उन्हें जाने में कोई रोक-टोक नहीं है. रावत ने कहा कि नाथुला दर्रे से मानसरोवर की ओर जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है. इससे फायदा होगा कि बुजुर्ग भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश का मार्ग बंद नहीं हो रहा है. यह मार्ग तो पहले की तरह ही खुला रहेगा. सुरक्षा के लिहाज से नाथुला दर्रे वाला मार्ग भी बेहद सुरक्षित है. लिहाजा कांग्रेस और उसकी सरकार को बेवजह कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. यह तो शुभ संकेत है कि अब ज्यादा से ज्याद तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं. कैलाश यात्रा मार्ग को लेकर कांग्रेस को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए. कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सिक्किम से नया रास्ता खोलने का धर्मनगरी हरिद्वार के कई साधु-संतों ने स्वागत किया है. साधु संतों का कहना है कि वक्त के साथ नई मान्यताएं स्थापित होती रहती हैं. पहले बद्रीनाथ सहित चारधाम की यात्रा पैदल हुआ करती थी. अब सरकार खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर बद्रीनाथ-केदारनाथ पहुंच रही है और यात्रियों को भी ले जा रही है. गंगा सभा के अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी का कहना है कि मुख्यमंत्री इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु वाहनों में बैठकर कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं. वृद्ध और लाचार भी मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे. जूना अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम गिरि कहते हैं कि यात्राओं के नए रूट तो खुलते ही रहते हैं. शहरों का विकास होता है तो कारोबार बढ़ता है, घटता नहीं. कैलाश की पैदल यात्रा में तीर्थ यात्रियों को लॉटरी सिस्टम से जाना पड़ता है और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नया रास्ता खुलने से अब पर्यटक भी इस अनूठी यात्रा का आनंद ले सकेंगे. इस बीच अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा से आय कमाने वाले व्यवसायियों ने नाथुला दर्रे से नया रास्ता शुरू किए जाने के लिए हुए समझौते के खिलाफ कुमाऊं क्षेत्र में प्रदर्शनों व धरनों का दौर शुरू हो गया है. केएमवीएन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पौराणिक यात्रा मार्ग पर नाथुला दर्रे का कोई खास असर नहीं होगा, यह भी सच है कि केएमवीएन के कर्मचारी भी इस मार्ग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि निगम के पास तीन माह तक के लिए यही काम है. ऐसे में यदि यहां यात्रा प्रभावित हुई तो फिर निगम का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है. पर्यटन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए समझौते के तहत कैलाश मानसरोवर के लिए अरुणाचल प्रदेश के नाथुला दर्रे से नये मार्ग के खोले जाने से यात्रा आयोजक कुमाऊं मंडल विकास निगम-केएमवीएन आशावादी है कि इस कदम से यात्रा को और अधिक प्रचार-प्रसार मिलेगा तथा मौजूदा पौराणिक यात्रा मार्ग से होने वाली यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा. केएमवीएन के महाप्रबंधक विनोदगिरि गोस्वामी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के साथ ही जैन, बौद्ध, सिख और बोनपा धर्म के भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, विश्व की सबसे कठिनतम और प्राचीनतम पैदल यात्राओं में शुमार 1,700 किमी लंबी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर वर्ष यात्रियों की संख्या के नए रिकार्ड बन रहे हैं. वर्ष 2012 में 774 तीर्थयात्रियों ने इस यात्रा पर जाकर रिकार्ड का नया शिखर छुआ था, जबकि इस वर्ष की यात्रा में पहली बार सर्वाधिक 18 दल इस यात्रा में शामिल हुए और 910 तीर्थयात्रियों ने अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. गोस्वामी का कहना है कि हर वर्ष ढ़ाई से तीन हजार लोग यात्रा के लिए आवेदन करते हैं, सीमित संसाधनों की वजह से सबको ले जाना संभव नहीं होता. उन्होंने उम्मीद जताई कि नया मार्ग खुलने से यात्रा का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, साथ ही प्रकृति प्रेमी, पैदल ट्रेकिंग के इच्छुक युवा एवं धार्मिक, आध्यात्मिक भावना वाले यात्री अभी भी पौराणिक मार्ग से ही यात्रा करना पसंद करेंगे. उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी नेपाल के रास्ते हवाई सेवा के जरिए भी कैलाश यात्रा के लिए अनेक मार्ग हैं, उनकी वजह से भी मौजूदा पौराणिक मार्ग की यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है. ■

शहीदों की उपेक्षा टीम तीरथ के गले की फांस बनी

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2013 सितंबर में भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पहुंचे 15 लाख के ड्राफ्ट आईटीबीपी के तीन शहीदों के परिवारों तक नहीं पहुंचने के खुलासे के बाद यह प्रकरण टीम तीरथ के लिए पुरी तरह से गले की फांस बन गया है. प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को शहीद परिवार के आश्रितों को अब तक पांच-पांच लाख राशि नहीं देने का खुलासा किया था. शहीदों के आश्रित इस धन राशि को प्राप्त करने के लिए दर दर भटके स्थानीय नेताओं ने लगातार उनकी आवाज को अनसुनी कर दी. बताते चलें कि सवा साल पहले प्रदेश में आई भीषण आपदा के दौरान आईटीबीपी के तीन जवान शहीद हो गए थे. इस दौरान ही भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शहीद परिवार के आश्रितों को पांच-पांच लाख की राशि पार्टी फंड से देने की घोषणा की थी. जिसे उनकी ओर से उत्तराखंड भाजपा कार्यालय को घोषित धनराशि के ड्राफ्ट समय पर भेज भी दिया गया, जिसे शहीद परिवार के दर्द से बेखबर लापरवाह नेताओं ने नजरअंदाज कर बेकार टोकरी में डाल दिया. सूत्रों का दावा है कि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों का खुला अपमान मानते हुए पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उत्तराखंड भाजपा द्वारा बरती गई इस लापरवाही के बारे में एक नोट भी लिखा है और शाह ने इसे गंभीरता के तौर पर लिया है. इसके बाद शाह ने तत्काल ही टीम तीरथ से इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस वजह से भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से भेजे गए 5-5 लाख की राशि अब तक शहीद परिवारों के आश्रितों तक नहीं पहुंचाई गई.

वैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उप चुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा की हार की वजह से टीम तीरथ से नाराज चल रहे हैं जिसकी वजह से शाह ने अब तक टीम तीरथ को नई दिल्ली में मिलने का समय नहीं दिया है. अब ड्राफ्ट प्रकरण ने पार्टी के अंदर दिल्ली से देवभूमि तक भूचाल खड़ा कर दिया है. टीम तीरथ विरोधी लाबी ड्राफ्ट मामले को लेकर भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं को भी यह जानकारी दी है कि खास रणनीति के तहत ही पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने शहीद परिवार के आश्रितों तक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एलान की गई राशि पहुंचाने की कोशिश नहीं की जबकि भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से 15 लाख के ड्राफ्ट बीते सितंबर 2013 में ही आ गए थे. यह गुट सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की मांग भी कर रहा है शाह खुद ही रिपोर्ट टीम तीरथ से मांग चुके हैं. इस बारे में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शहीद परिवार तक ड्राफ्ट नहीं पहुंचना एक बड़ी चूक है. शहीद परिवार के आश्रितों को भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से भेजे गए 15 लाख का ड्राफ्ट एक साल बाद भी टीम तीरथ द्वारा उन्हें नहीं सौंपे जाने का मामला अब और ज्यादा उलझता जा रहा है. भाजपा हाईकमान ने टीम तीरथ से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है जबकि प्रदेश भाजपा के ही एक गुट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से ड्राफ्ट प्रकरण की रिपोर्ट टीम तीरथ से मांगने के बजाय केंद्रीय स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में एक टीम गठित कर पड़ताल कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके. शुरू में भाजपा हाईकमान ने 48 घंटे के अंदर ही शहीद परिवारों के आश्रितों को ड्राफ्ट देने में हुई चूक की रिपोर्ट मांगी, बाद में टीम तीरथ को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा है. प्रदेश भाजपा का ही एक गुट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहा है कि टीम तीरथ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ड्राफ्ट मामल में हुई चूक की निष्पक्ष रिपोर्ट टीम तीरथ नहीं दे सकती. इस पूरे प्रकरण पर टीम तीरथ के सदस्य ही शामिल हैं, लिहाजा यदि टीम तीरथ इस मामले की पड़ताल करेगी तो वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी, मामले की हर तरह से लिपापोती ही की जाऐगी.. इस प्रकरण के कई साल पहले फंड में हुई गड़बड़ी की पड़ताल के लिए प्रदेश स्तर पर एक टीम गठित की गई सालों बीत जाने के बाद भी फंड में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है. इसलिए संगठन हित में सबसे बढ़िया यही रहेगा कि केंद्रीय नेताओं की एक टीम गठित की जाए जो इस मामले की पड़ताल करे. सूत्रों के मुताबिक संघ ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. संघ का इस मामले में स्पष्ट कहना है कि प्रदेश भाजपा सवा साल पहले प्रदेश में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेरती एवं इस पर हमला करती रही है, दुर्भाग्य यह है कि आपदा से जुड़े मामले में टीम तीरथ की ओर से लापरवाही बरती गई है जिससे पूरे प्रदेश में गलत संदेश गया है. माना जा रहा है कि संघ भी यही चाह रहा है कि ड्राफ्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेताओं को ही पड़ताल करनी चाहिए. गृहमंत्री राजनाथ की पहल एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तगड़ी फटकार के बाद प्रदेश में आई आपदा के दौरान देवभूमि में शहीद हुए तीन जवानों के परिजनों को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 5-5 लाख के चेक बांटे गए. भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने शहीद अजय लाल के बड़े भाई प्रेम हिंदवाल, शहीद नंदराम की पत्नी मंजू देवी और शहीद जयेंद्र प्रसाद की पत्नी शीला देवी को 5-5 लाख के चेक दिए. शहीदों के परिजनों को पांच-पांच लाख के चेक एक साल पहले ही दिए जाने थे. आपसी कलह में मस्त भाजपा के खच्चर नुमा नेता है कि बिना चाबूक के एक कदम आगे नही बढ़ते जिसका परिणाम है कि मोदी के शानदार मिशन पर पानी फिर रहा है. ■

गंगा की उपेक्षा का सिलसिला जारी है

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2013 जून में उत्तराखंड आपदा के दौरान गंगा में आई बाढ़ के कारण त्रिवेणीघाट में सरस्वती नाले का एक हिस्सा टूट गया था. जिसके बाद से पूरे शहर की गंदगी इस स्थान पर सीधे गंगा में मिल रही है. इसके समीप ही करोड़ों की लागत से स्थापित सीवेज पंपिंग स्टेशन का वर्क पूरा हो गया, लेकिन इस नाले से जुड़े होने के कारण भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

राष्ट्रीय धरोहर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए देश व प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते पिछले साल आई आपदा के दौरान त्रिवेणीघाट में क्षतिग्रस्त सरस्वती नाले को अभी तक सही नहीं कराया गया है, जिसके एक हिस्से से शहर की गंदगी सीधे गंगा में प्रभावित हो रही है. इस कारण यहां आने वाले हजारों देशी-विदेशी श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है. इसके बावजूद नाले के ट्रीटमेंट से जुड़ी फाइलें करीब नौ माह से सरकारी महकमों में धूल फांक रहीं हैं. वर्ष 2013 जून में उत्तराखंड आपदा के दौरान गंगा में आई बाढ़ के कारण त्रिवेणीघाट में सरस्वती नाले का एक हिस्सा टूट गया था. जिसके बाद से पूरे शहर की गंदगी इस स्थान पर सीधे गंगा में मिल रही है. इसके समीप ही करोड़ों की लागत से स्थापित सीवेज पंपिंग स्टेशन का वर्क पूरा हो गया, लेकिन इस नाले से जुड़े होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके लिए कार्यदायी संस्था निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा द्वारा 56.04 लाख रुपये की एक योजना तैयार की गई. जिसमें नाले को पंपिंग स्टेशन से जोड़ा जाना है. 19 दिसम्बर 2013 को प्रस्तावित योजना की फाइल मुख्यालय को भेजे जाने के बाद मुख्य अभियंता द्वारा चार दिन बाद 23 दिसंबर को शासन को भेज दी गई. इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने प्रस्तावित योजना की आवश्यकता व अनापत्ति को लेकर मई 2014 में नगरपालिका से जवाब मांगा. जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नगरपालिका द्वारा 10 जून 2014 जवाब भेज दिया गया. इसके तीन माह गुजर जाने के बाद भी फाइल अधर में लटकी हुई है. लगभग साढ़े तीन करोड़ की लागत से त्रिवेणीघाट में निर्मित सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) सरकारी महकमों की उदासीनता के कारण बंद पड़ा है. निर्माण के बाद स्टेशन ने 25 मई से सात जुलाई तक महज सवा महीने ही काम किया है. इस बीच गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पंपिंग स्टेशन ठप हो गया. यहीं नहीं बरसात के दिनों में त्रिवेणीघाट का समूचा प्लेटफार्म भी सीवेज की गंदगी से अट जाता है. धर्मनगरी ऋषिकेश का वक्षस्थल कहा जाने वाला त्रिवेणी घाट की स्थिति यहां के सभी नेता और अफसरों की जानकारी में है. कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं दिख रहा है. सभी की गंगा के प्रति संवेदना इस कदर शून्य हो गई है कि लोग मां कह कर दीप आरती करते है, अपने लाख-लाख कल्याण की कामना भी करते है, लेकिन मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाने से कतराते है. इससे भी खतरनाक सच यह है कि इस धर्मनगरी के तट पर गंगा का जयकारा लगा कर अकूत संपत्ति के स्वामी बने संतो के बहुतायत आश्रमों के गंदे नाले बिना रोक-टोक के गंगा में ही अबाध गति से गिराए जा रहे है जिसमें गंगा की सेवा का ढ़िंडोरा पीटने वाले परमार्थ आश्रम का गंदा नाला भी निर्वाध गंगा को मौला कर रहा है, जिस पर आश्रम परिवार और प्रशासन ने अपनी आंखे बन्द कर रखी है. गंगा के नाम पर रोटी कमाने और खाने वाले लोगों की बदनियत गंगा की सफाई में घोर बाधा बनी हुई है.

(विभाग द्वारा सरस्वती नाले को एसपीएस से जोड़ने के प्रस्ताव को शासन को भेजा गया है. धन आवंटन के अभाव में यह कार्य नहीं हो पा रहा है. जैसे ही योजना को मंजूरी मिलने के साथ धन आवंटित होगा. निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि शहर से निकलने वाले अवजल को गंगा में प्रवाहित होने से रोका जा सके. पीके गुप्ता-परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा) ■

एक नारी की व्यथा

आखिर काम क्यों नहीं करते सरकारी अफसर

पारुल उनियाल

केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को हर सुविधाएं और उनके कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता तो जताती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अधिकारियों से कहते हैं कि देश की जनता का एक कार्य भी नहीं रूकना चाहिए उनके हर कार्यों का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए. जब एक महिला किसी सरकारी कार्यलय में किसी कार्य के लिए जाती है, तो उसके कार्य को सबसे पहले निपटाना चाहिए. लेकिन आज भी देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जो भ्रष्ट, कामचोर हैं, जो न देश की सेवा करते हैं और न ही देश की नागरिकों की. लोगों को आशा थी कि सरकार बदलेगी, तो व्यवस्था भी बदलेगी, लेकिन सरकार तो बदली व्यवस्था नहीं बदली. एक ताजा उदाहरण है पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून का. मैं पारुल यूनियाल ने पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी मेरा पासपोर्ट आज तक नहीं बना. पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद जब मैं अप्पोइंमेंट के दिन पीएसके देहरादून पहुंची, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि तत्काल आवेदन के लिए संग्लक(i) एवं (F) अतिआवश्यक हैं, लेकिन यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन के समय नहीं दी गई थी और न ही कोई इमेल या एसएमएस के माध्यम से बताया गया कि कौन से दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थान पर जाना है. टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज के जो कस्टमर हैंडलिंग/सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वहां उपस्थित थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि यदि कोई पीएसके आता है, तो उसको यहां आने के पूर्व इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जाती है. उसी समय जानकारी न होने के कारण तहसील का बार-बार चक्कर काटना पड़ता है और 100 रुपये के नोटरी के कार्य के लिए 500 रुपये देना पड़ता है. मैंने वहां जाने के बाद देखा कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए किवोस्क भी लगे हैं, लेकिन ऑपरेट स्वयं करना है, जिस व्यक्ति को कम्प्यूटर की जानकारी नहीं होगी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोई कैसे आवेदन करेगा? सरकार को समझना चाहिए कि देश की एक बड़ी संख्या है, जो आज भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाती है, तो उन लोगों की मदद कौन करेगा. इसलिए गांवो और छोटे शहरों में उसके पास एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए होना चाहिए. पीएसके से ये पता चलने के बाद की संग्लक (i) एवं (F) के बिना कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. उसके बाद मैं ऋषिकेश तहसली पहुंची और वहां से संग्लक (i) एवं (F) बनवाया नोटरी से संग्लक (i) सत्यापित करवाया, लेकिन एसडीएम के अनुपस्थिति के कारण संग्लक(F) सत्यापित नहीं हो पाया. शाम 5 बजे तक एसडीएम का इंतजार करते-करते तहसील की समय अवधि समाप्त हो गई और अंतत: मैं हार कर घर वापस आ गई. अगले दिन 19-09-2014 को मैं पुन: तहसील गई और वहां जाकर एसडीएम से मिली उनसे पीएसके का हाल बताया, तो उन्होंने मदद के तौर पर मेरे सभी दस्तावेज सत्यापित कर दिया. उसके बाद मैं उस पर मुहर लगवाने के लिए दूसरे विभाग में गई. वहां जानकारी न होने के कारण मैं गलत लाइन में लग गई और वहां पर एक महिला कर्मचारी दस्तावेजों की जांच कर रही थी. उसने सभी दस्तावेज लिए और उसके बाद मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी और दस्तावेजों को लेकर कहने लगी कि ये आगे पीछे क्यों लगाया है. आपको पता नहीं कि कैसे लगाने चाहिए और फिर उसके बाद मेरी उससे कहा सुनी हुई. उस समय भी मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि जब हम जैसे युवा और पढ़े-लिखे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उन लोगों का क्या जो लोग दूर से आते हैं और भूखे, प्यासे परे दिन लाइन में खड़े रहते हैं. शायद उनके साथ भी यही होता होगा कि उनको जानकारी देने के बजाय सरकारी विभागों में कुर्सी पर बैठे कामचोर कर्मचारी, दुर्व्यवहार करते होंगे.

यहां मदद और जानकारी न मिल पाने के कारण मैं तहसलीदार की मुहर लगवाने के लिए कोर्ट परिसर में प्रतिक्षा करती रही, लेकिन कार्य न होने के कारण मैं एक बार फिर एसडीएम के पास गई और उनसे पूरा वाकया बताया. उसके बाद उन्होंने चपरासी को बुलाकर मुहर लगावाकर सभी दस्तावेजों की पुष्टिकरण का एक प्रमाणपत्र बनाकर अपनी उप-जिलाधिकरी की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ मुझे दे दिया.

यहां मदद और जानकारी न मिल पाने के कारण मैं तहसलीदार की मुहर लगवाने के लिए कोर्ट परिसर में प्रतिक्षा करती रही, लेकिन कार्य न होने के कारण मैं एक बार फिर एसडीएम के पास गई और उनसे पूरा वाकया बताया. उसके बाद उन्होंने चपरासी को बुलाकर मुहर लगावाकर सभी दस्तावेजों की पुष्टिकरण का एक प्रमाणपत्र बनाकर अपनी उप-जिलाधिकरी की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ मुझे दे दिया. लेकिन संग्लक (F) सत्यापित नहीं किया. यह कहकर कि उनके पास राजपत्रित अधिकारी की सील नहीं है और ये अन्चछेद देहरादून के एडीएम सत्यापित कर सकते हैं. उसके बाद मैं तुरंत संग्लक(F) को लेकर मैं देहरादून कोर्ट गई कि वहां दो एडीएम हैं, लेकिन शाम चार बजे ही वहां कोई उपस्थित नहीं था. ऑफिस के लोगों ने बताया कि न तो एडीएम सर न ही एडीएम मैम इस संग्लक को सत्यापित करके सील देंगे. प्रशासन के आगे आम आदमी कितना मजबूर है, यह उस दिन पता चला. कोर्ट से मदद न मिलने के बाद मैं देहरादून सत्यापन सेल गई, तो वहां पता चला की ऋषिकेश के सीओ क्षेत्राधिकारी इसे सत्यापति कर सील लगा सकते हैं. उसी शाम मैं ऋषिकेश थाना पहुंची, तो पता चला कि सीओ अपने ऑफिस में हैं उम्मीद थी कि शायद सीओ अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे मैं उनसे मिलने सीओ ऑफिस गई, लेकिन वे नहीं मिले. उसके बाद वहां कार्यरत बाबू लोगों की बाते सुनकर मैं अचंभित रह गई. वे लोग कहने लगे की क्या आप सीओ को जानती है? क्या कोई जान-पहचान है? मैंने उत्तर दिया नहीं, तो वे लोग कहने लगे की बिना व्यक्तिगत जान-पहचान के सीओ सर राजपत्रित अधिकारी की सील और आईडी नहीं देंगे. अब सवाल यह उठता है कि जब कोई हमारीमदद नहीं कर सकता जबकि हमारे पास सभी सच्चे दस्तावेज हैं वह चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या चाहे हमारे शिक्षा प्रमाणपत्र हों. उन्हें देखकर सत्यापित नहीं कर सकते तो सरकार चुनाव के समय वोटर-आईडी क्यों बनवाती है? क्यों बिना वोटर-आईडी कार्ड के हम वोट नहीं दे सकते? क्यों बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते? जब इन दस्तावेजों के होने के बावजूद कोई हमें सत्यापन का प्रमाण नहीं दे सकता तो क्यों सरकार इन दस्तावेजों को निरस्त नहीं कर देती. क्यों ऐसे लोगों को सरकार कुर्सी पर बैठा रखी है? जिनके पास राजपत्रित अधिकारी की मुहर तक मुहैया नहीं करा सकती. क्यों इतनी परिक्षा पास करने के बाद ये आईएएस, पीसीएस जैसे अधिकारी बनते है, जब ये हमारी मदद नहीं कर सकते? आज जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उसके पास 1 नहीं 4 पासपोर्ट मिलते हैं, तो इतनी जांच के बावजूद उनको अलग-अलग देशों के इतने पासपोर्ट कैसे मिल जाते हैं? इसका जवाब कौन देगा? यही अधिकरी जांच के नाम पर सीधे-साधे लोगों को दौड़ाते हैं फिर भी उनका कार्य नहीं होता है. भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पैसे देकर खतरनाक आतंकवादियों का पासपोर्ट बन जाता है. उन्हें सभी दस्तावेज प्रमाणपत्र के साथ मिल जाते हैं, लेकिन हमको अपने दस्तावेज बनावने और प्रमाणपत्र के लिए कई बार सरकारी ऑफिसों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके बावजूद भी उनके प्रणाणपत्र नहीं बन पाते. हम जैसी महिलाओं की मदद करने में सरकारी महकमें क्यों पीछे रहते हैं. क्या यह अधिकरी एक महिला की मदद नहीं कर सकते? क्या एक महिला होने के कारण आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल पुछ रही हूं कि क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के लोगों की मदद क्यों नहीं करते? इसलिए सरकार से निवेदन करती हूं कि ऐसे कामचोर और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि फिर दोबारा हमारी जैसे किसी महिला के साथ यह अन्याय न हो. ■

आजम खान की मुश्किले बढ़ीं

वैष्णवी वंदना feedback@chauthiduniya.com

अच्छे दिन लौटने का इंतजार कर रहे आजम खान को अपने राजनीतिक करियर के बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं. एक तरफ आजम अपनी नियति और अपने कृत्यों से समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक करियर पर ही काली छाया पड़ रही है. लाभ के दो-दो पदों पर काम करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अभी तो नोटिस ही जारी किया है. आगे क्या होगा, इसका अभी से अनुमान लगाया जाने लगा है. 25 सितम्बर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज देवी प्रसाद सिंह और अरविंद कुमार त्रिपाठी (द्वितीय) ने आजम खान को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि वे लाभ के दो पदों पर एक साथ कैसे काबिज हैं. न्यायालय ने उनसे छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है. आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद भी सम्भाल रहे हैं. हाईकोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर किया है कि मंत्री रहते हुए आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कैसे रह सकते हैं. उल्लेखनीय है कि लखनऊ के शिया धर्मगुरु इमाम राजा हुसैन और एस आमिर हैदर रिजवी ने आजम खां के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडेय ने तर्क दिया कि आजम खान मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है. संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति विधायक नहीं हो सकता. ऐसे में जिस दिन आजम खान कुलाधिपति बने उसी दिन वे मंत्री पद के अयोग्य हो गए. याचिका में मांग की गई है कि आजम खान को मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनका चुनाव भी रद्द किया जाए. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को 10 सितम्बर 2014 को सरकार के पक्ष के साथ पेश होने का निर्देश दिया है. साफ है कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय अब उनकी सियासी कुर्सी पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद से शुरू हुई आजम खान की लड़ाई अब बेहद गंभीर रूप अख्तियार कर चुकी है. अब तक जिस संविधान का जिक्र कर आजम खान वक्फ बोर्ड का चुनाव करवाकर मौलाना को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वहीं संविधान और कानून अब आजम के विधायक और मंत्री होने पर उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहा है. लाभ के दो-दों पर रहने का मसला इसके पहले भी सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, अमर सिंह, जया बच्चन समेत कई प्रमुख हस्तियों को संकट में डाल चुका है. प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति चुनाव इसी मसले को लेकर अधर में फंस गया था, जिस संकट से वे बहुत मुश्किल उबरे थे. प्रणब पर तो आरोप था कि वे एक साथ लाभ के कई पदों पर काम कर रहे थे. वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष, बीरभूम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष और रवींद्र भारती सोसायटी के अध्यक्ष थे. याद रहे कि जया बच्चन की राज्यसभा से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद देशभर में लाभ के पद का विवाद सुर्खियों और बृहद चर्चा में आया. जया बच्चन की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा से इस्तीफ़ा देकर फिर चुनाव लड़ा. उन्हें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. लोकसभा के निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा में विपक्ष के तत्कालीन उपनेता विजय कुमार मल्होत्रा और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान वरिष्ठ नेता अमर सिंह सहित कई सांसद लाभ के दो-दो पदों पर आसीन होने का मामला झेल चुके हैं. ■

शिवालिक के जंगल अफ्रीकी चींटियों के हमले की जद में

रेनु शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड के शिवालिक के जंगल अफ्रीकी चींटियों के हमले की जद में आ गए हैं, इससे इन जंगलों में हरे पेड़ तेजी से सुख रहे है. जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले उत्तर पश्चिमी हिमालय के शिवालिक के जंगलों में अफ्रीका महाद्वीप और इंडोमलाया क्षेत्र की खतरनाक चींटियों ने हमला बोल दिया है. वन के जानकारों का मानना है कि इन अफ्रीकी चीटीयों से बचाव के उपाय नहीं किए गए, तो हमारे वनों की अपूर्णीय क्षति हो सकती है. विदेशी हमलावर चीटिंयों का यह हमला इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. वह इसलिए कि इन चींटियों का पाया जाना इस बात का संकेत है कि ये जंगल धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं. पिछले 14 वर्षों से चल रहे एक एक जंतु वैज्ञानिक अध्ययन में जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले शिवालिक के जंगलों में चींटियों के 30 हजार नमूने एकत्र किए गए. इसमें पता चला कि शिवालिक की पहाड़ियों के जंगलों में पाई जाने वाली 188 चींटी प्रजातियों में से 20 प्रजातियां इस क्षेत्र की नहीं हैं और विदेशी हमलावर प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरनाक हैं. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर हिमेंद्र भारती के अध्ययन स्टडी ऑफ एंट स्पेशीज अबंडेंस एंड कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम शिवालिक रेंज ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज(जम्मू टू उत्तराखंड) के मुताबिक शिवालिक रेंज में पहली बार चींटियों की ऐसी प्रजातियां पाई गई हैं जो पहले कभी यहां नहीं देखी गईं. इनमें से 9 चींटी प्रजातियों में से तीन को तो भारत में पहली बार देखा गया है. अन्य छह प्रजातियां दक्षिणी भारत के जंगलों में पाई जाती हैं जो शिवालिक में पहली बार देखी गई हैं. इन चींटियों को किसी भी क्षेत्र के जैविक संकेतक भी माना जाता है. जो हमलावर चींटियां पाई गई हैं इनमें सोलेनोप्सिस जेमिनाटा (ट्रॉपिकल फायर एंट), टेट्रामोरियम कैल्डेरियम (स्मॉल रैडिश एंट), टेक्नोमायरमेक्स एल्बाइप्स (व्हाइट फुटेड एंट), स्ट्रमिजेनिस मेंब्रेनिफेरा (क्रिप्टिक प्रेडेटरी एंट) आदि शामिल हैं. यह माना जाता है कि ये विदेशी हमलावर चींटी प्रजातियां केवल उन्हीं स्थानों में पाई जाती हैं जहां का पारिस्थितिकीय तंत्र तेजी से खराब हो रहा हो. शिवालिक पहाड़ियों में इन चींटियों की ढेरों प्रजातियों की मौजूदगी इस बात की तसदीक करती है कि इस पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकीय तंत्र अपना स्वरूप खो रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्था के वरिष्ठ कीट विज्ञानी वीके उनियाल का कहना है कि भविष्य में इन प्रजातियों की संख्या बढ़ती है, तो साफ है कि वनों का पारिस्थितिकीय तंत्र और बिगड़ गया है. शोध के अनुसार खतरे की बात यह है कि इन चींटियों की मौजूदगी इन क्षेत्रों में भी पाई गई है, जो शिवालिक की विशिष्ट जैव विविधता वाले इलाके रहे हैं और जहां मानव गतिविधि शून्य है या न के बराबर है. शिवालिक की पहाड़ियों के जंगलों में पाई गई 20 हमलावर विदेशी चींटियां 14 वर्ष के अध्ययन में नौ चींटी प्रजातियों में से तीन को तो भारत में पहली बार देखा गया है. राज्य का वन विभाग इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से ही बचाव की मुद्रा में आ गया है. ■

शिवालिक पहाड़ियों में इन चींटियों की ढेरों प्रजातियों की मौजूदगी इस बात की तसदीक करती हैं कि इस पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकीय तंत्र अपना स्वरूप खो रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्था के वरिष्ठ कीट विज्ञानी वीके उनियाल का कहना हैं कि भविष्य में इन प्रजातियों की संख्या बढ़ती हैं, तो साफ है कि वनों का पारिस्थितिकीय तंत्र और बिगड़ गया है.

गौरी-गणेश की पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य की शर्मनाक टिप्पणी

बसपा प्रमुख मायावती की हर वक्त पूजा करने वाले बसपा नेताओं में सबसे वरिष्ठ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में आयोजित एक सभा में सार्वजनिक मंच से कहा कि शादियों या किसी शुभ अवसर पर गौरी-गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए. यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है.

राजनीतिक दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बसपा नेता के समाज विरोधी बयान पर राजनीतिक दलों की शातिराना चुप्पी को आम नागरिकों ने पहचाना.

हालांकि बाद में मायावती ने ही अपने नेता के बयान की दूरगामी नजाकत समझीं और फिर से बयान जारी कर कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के धर्म-निरपेक्षता के मूल सिद्धान्त के अनुरूप सभी धर्मों, सर्वसमाज के लोगों के रहन-सहन, शादी-विवाह, पूजा-पाठ और उनकी संस्कृति के तौर-तरीकों का आदर करती है. मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनकी निजी राय बता कर पल्ला झाड़ लिया. मायावती ने इतना संभालने की कोशिश जरूर की कि बसपा दलितों, पिछड़ों, अगड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को साथ लेकर समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करना चाहती है. भाजपा ने मायावती और उनकी पार्टी को अगड़ी जातियों के लिए नफरत से भरी पार्टी करार दिया. भाजपा के प्रवक्ता विजय पाठक ने कहा कि बसपा समाज में घृणा फैलाने की राजनीति करती हैं. मायावती ने मौर्य के बयान को खारिज किया तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की. मौर्य के इस उन्मादी बयान को लेकर अन्य दलों ने कुछ नहीं बोला. सड़कों पर कुछ धरना-प्रदर्शन जरूर हुए. आम लोगों का भी कहना था कि यही बयान मुस्लिमों को लेकर आया रहता तो सारे राजनीतिक दल नफरत की मशालें लिए हुए बयान-मंच पर एक दूसरे से भिड़े रहते. ■

feedback@chauthiduniya.com

दीनबंधु क़बीर

लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार और उपचुनाव में दलित वोट बैंक के खिसक जाने से बहुजन समाज पार्टी बौखला गई है. अब वह इस आपाधापी में है कि किसी भी तरह दलितों का वोट बचाया जाए और मुसलमानों का वोट खींचा जाए. वोट बचाने और वोट खींचने की बेचैनी में बसपा के नेता अपने मुखिया के इशारे पर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. अपने नीचे के नेताओं से बयान दिलवा कर खुद को अलग करने के मायावती के तौर-तरीके बहुत ही जाने-पहचाने हैं. आम आदमी भी यह जानता है कि मायावती की आज्ञा के बिना कोई जोर से सांस नहीं ले सकता, बयान जारी करना तो दूर की बात है. लिहाजा यह साफ है कि बसपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गणेश-लक्ष्मी की पूजा को लेकर जो अमर्यादित बात सार्वजनिक मंच से कही, वह बिना सहमति के नहीं कही होगी. उस बयान से जो हित सधना था, वह सध गया. समाज का जितना अहित होना था, उतना हो गया. मायावती को हित से मतलब था. समाज के अहित से नेताओं को क्या लेना-देना! मौर्य के बयान पर बवाल मचते ही मायावती ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान से किनारा भी कर लिया.

बसपा प्रमुख मायावती की हर वक्त पूजा करने वाले बसपा नेताओं में सबसे वरिष्ठ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में आयोजित एक सभा में सार्वजनिक मंच से कहा कि शादियों या किसी शुभ अवसर पर गौरी-गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए. यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है. मौर्य ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में सुअर को वराह भगवान कहकर सम्मान दिया जा सकता है. गधे को भवानी, चूहे को गणेश और उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कहकर पूजा की जाती है, लेकिन शूद्र को सम्मान नहीं दिया जाता. मौर्य ने पिछड़ों व दलितों की एकता के राजनीतिक लाभ पर निशाना साधते हुए कहा कि मनुवादियों की भाषा में दलित व पिछड़े सब शूद्र हैं, तो फिर उन्हें अलग क्यों रहना चाहिए. दलित, आदिवासी और पिछड़े मूल रूप से एक हैं. पिछड़ी जाति के तमाम लोगों ने अपने नाम के साथ क्षत्रिय जोड़ने के चक्कर में अपना नुकसान किया है. स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ आसानी से निकाले जा सकते हैं. इस बयान में दलित वोट बैंक के खत्म होने का उनका गुस्सा और पार्टी की बौखलाहट साफ-साफ दिख रही है.

लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से प्रदेश में कोई राजनीतिक बवाल नहीं मचा. भाजपा को छोड़ कर सारे राजनीतिक दलों ने तकरीबन चुप्पी ही साध रखी है. हर बयान पर प्रतिक्रिया जारी करने में पीछे नहीं रहने वाली तमाम बड़ी छोटी पार्टियों ने चुप्पी साध ली. उन्हें डर था कि पता नहीं क्या बोला और कौन खिसका! मायावती ने बोल कर पल्ला झाड़ा. बाकी पार्टियों ने चुप रह कर पल्ला झाड़ लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर दिए गए सकारात्मक बयान को घिनौनी शक्ल देने में

मौर्य के खिलाफ मुकदमा

बसपा के महासचिव एवं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रतापगढ़ के सीजेएम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है. कोतवाली क्षेत्र के पूरे ओझा चकबन तोड़ निवासी आशुतोष त्रिपाठी ने सीजेएम इश्तियाक अली की अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद ने 21 सितम्बर को अपने बयान में हिंदू धर्म में प्रचलित गौरी गणेश की पूजा करने की परंपरा की अवमानना की है. इससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है. साथ ही इस बयान से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है. विपक्षी भड़काऊ भाषण देकर हिंदू समाज की विभिन्न जातियों एवं दलित वर्ग को उत्तेजित कर रहे हैं. कुंडा और सोरों की अदालतों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया. ■

श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अब मीलों की दूरी मिनटों में तय करेगा लखनऊ

राजधानी लखनऊ में बढ़ती यातायात की समस्या के दृष्टिगत जनसामान्य को बेहतर एवं त्वरित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेट्रो रेल परियोजना पर प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ।

निविदा जारी-जून -2014

कार्य आरंभ-सितम्बर-2014

दिसम्बर-2016 में चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ तक 8 किमी लंबी मेट्रो शुरू

लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन

twitter.com/yadavakhilesh facebook.com/yadavakhilesh

http://information.up.nic.in

बन रहा है आज, सँवर रहा है कल

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

06 अक्टूबर–12 अक्टूबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

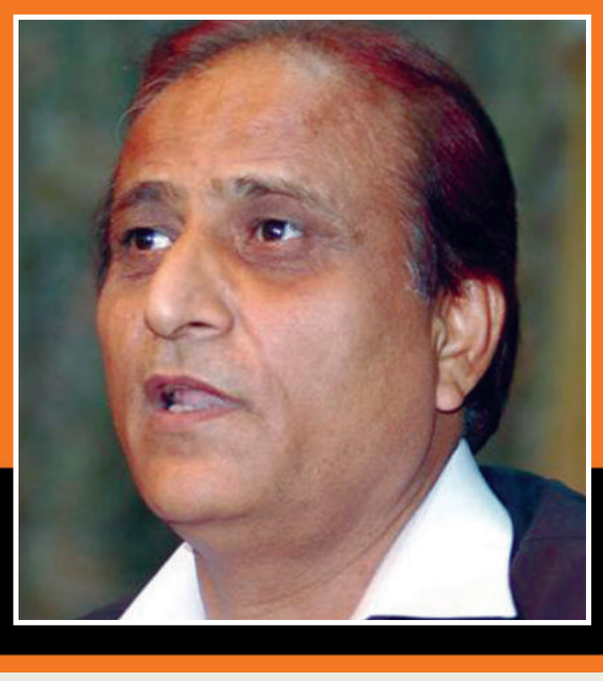

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

सपा के स्थापना के बाद पहली बार लखनऊ में होने जा रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमर सिंह के सपा में वापसी की घोषणा हो सकती है, क्योंकि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क में यह अधिवेशन होना है, उसी के लोकार्पण में मुलायम सिंह यादव के साथ अमर सिंह नजर आए थे. तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमर सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं. सपा का उप चुनाव में जीत के बाद मनोबल सातवें आसमान पर है और वह भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. सपा इसी अधिवेशन में कोयला और बिजली के मुद्दे को लेकर केंद्र से युद्ध की घोषणा कर सकती है.

अमर सिंह की वापसी हो सकती है

केंद्र से युद्ध की घोषणा कर मैदान में उतरेगी सपा

प्रभात रंजन दीन

उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी ऐतिहासिक करने की तैयारी में है. सपा की स्थापना के बाद पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है और पूरी सम्भावना है कि अमर सिंह की वापसी की घोषणा के साथ ही अधिवेशन अपनी ऐतिहासिकता में एक अध्याय और जोड़ ले. अमर सिंह की वापसी हो गई तो आजम खान के रुखसत होने का ऐतिहासिक अध्याय भी लिख जाएगा. पार्टी के अंदर इस बात की भी तैयारी है कि लखनऊ अधिवेशन में केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध की सीधी घोषणा हो. इसके लिए बिजली और कोयला जैसे मुद्दे अहम हैं, जिन्हें सामने रख कर समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेगी.

विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुट गई है. सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव अधिवेशन की तैयारियों को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं. सपा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आठ अक्टूबर से लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित होगा, जिसका लोकार्पण अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें अमर सिंह की मौजूदगी ने इस लोकार्पण समारोह को कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में लाया था. प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अधिवेशन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. अधिवेशन की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भी कि अधिवेशन को यादगार बनाना है. उन्होंने कहा कि जनता अब सभी दलों को पहचान गई है और अब उसकी सारी उम्मीद सपा पर ही टिकी है.

लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाइन क्या लेगी, इस पर मंथन चल रहा है. महागठबंधन की सम्भावनाओं पर भी चर्चा होगी और विकास के एजेंडे पर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बिजली और कोयला पर केंद्र से युद्ध का ऐलान होगा. विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. सपा सरकार पहले से ही इसकी पेशबंदी कर रही है और केंद्र पर हमला जारी रखे हुई है.

महागठबंधन की जरूरत पर भी होगा विचार

प्रजोर ताकत के साथ उभर कर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए छोटी पार्टियों को एकजुट होना होगा, लेकिन कैसे, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ अधिवेशन में माथापच्ची करेंगे. पार्टी का गठन होने के बाद लखनऊ में होने वाला यह पहला अधिवेशन है. पार्टी के स्थापना-अधिवेशन के बाद ही पिछड़ा-दलित गठबंधन का ऐतिहासिक अध्याय लिख गया था. लखनऊ में हो रहे पार्टी के नौवें अधिवेशन में कहीं वैसा ही ऐतिहासिक अध्याय तो नहीं लिखने जा रहा! पूरा अध्याय नहीं भी लिखा, भूमिका तो लिख ही जाएगी. याद करते चलें कि मुलायम सिंह यादव ने 7 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित कर समाजवादी पार्टी के गठन का ऐलान किया था. तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. मुलायम सिंह ने संघर्ष शुरू किया. पिछड़ों और अति पिछड़ों को केंद्र में रखकर बनाई गई समाजवादी पार्टी ने दलितों को भी साथ लेने की रणनीति अख्तियार की थी. उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम से हाथ मिलाया और दलित-पिछड़ों का गठबंधन कायम किया. पार्टी गठन के महज 13 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन को 176 सीटें हासिल हुई. इसमें सपा ने 109 सीटें जीतीं और बसपा को 67 सीटें मिलीं. सरकार बनाने के लिए 213 सीटों की जरूरत थी. भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस व जनता दल ने सपा को समर्थन देकर 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया. लेकिन सपा-बसपा गठबंधन अधिक दिन नहीं चल सका. इस बीच पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के अपहरण से लेकर गेस्ट हाउस कांड तक की तमाम घटना-प्रतिघटना हुई और 1 जून 1995 को गठबंधन टूट गया. बिहार में दो धुर-विरोधियों जदयू और राजद के महागठबंधन ने यह साबित किया कि राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी का कोई स्थायित्व नहीं होता. इसे दृष्टिगत रखते हुए यूपी में भी सपा-बसपा के गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं. कोशिश यह भी है कि मायावती अधिक अड़ंगे डालें, तो बसपा अपने नेतृत्व का विकल्प तलाशे और गठबंधन की अनिवार्यता देखते हुए सपा से हाथ मिला ले.

उप चुनाव में दलित वोटों को हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी का इस दिशा में आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है. यूपी में महागठबंधन की कोशिशें अगर शक्ल ले पाईं तो कई रोचक तथ्य और समीकरण सामने आएंगे, इसमें कांग्रेस की भूमिका भी दिखगी और रालोद की भी... और अमर सिंह की भी. भाजपा का विरोध करने के लिए एकजुट होने के सिवा इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है. ■

बहरहाल, अधिवेशन की तैयारियों में लगे सपा नेताओं में से एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नेतृत्व के शीर्ष गलियारे में अमर सिंह की वापसी का मन बन रहा है और अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अमर सिंह की पार्टी में वापसी की चर्चा कराने की औपचारिकता पूरी करा कर उन्हें शामिल किए जाने की घोषणा कर सकते हैं. अमर सिंह की वापसी में मुलायम परिवार में बना दो खेमा बाधा बन सकता है और रोड़ा बन सकते हैं प्रो. रामगोपाल यादव, जो परिवार के साथ-साथ पार्टी आलाकमान का हिस्सा भी हैं. मुलायम परिवार का एक बड़ा खेमा अमर सिंह के सपा परिवार में दोबारा शामिल कराने का पक्षधर है, लेकिन दूसरा छोटा खेमा इस पक्ष में नहीं है. जहां तक आजम खान का प्रश्न है, तो वे पार्टी में पहले ही किनारे लगाए जा चुके हैं. सपा के एक नेता ने यह भी कहा कि अमर सिंह को पार्टी में शामिल करा कर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है. लेकिन अगर कुछ अड़चन आए तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी समर्थन देकर सपा राज्यसभा तक पहुंचा सकती है और आगे का रास्ता साफ कर सकती है. मोदी लहर के कारण लोकसभा चुनाव में पराजय के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल की पकड़ और उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता. बिहार के महागठबंधन की तर्ज पर एक बृहत्तर छत्रप तानने की कोशिशों में अमर सिंह पार्टी की क्या मदद कर सकते हैं, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है.

राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि इतने दिनों के बाद अमर सिंह को सपा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना, आमंत्रण पर उनका आना, फिर दोबारा अमर सिंह का शिवपाल के घर पहुंचना और मुलायम के आवास पर उनसे और मुख्यमंत्री अखिलेश से मिलना कोई संयोग थोड़े ही है. सपा के नेता भी इसे संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक योग ही बताते हैं और मानते हैं कि इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है. लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद और हार के कारण इस रणनीतिक-अनिवार्यता को और मजबूती मिली है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा नेतृत्व की पेशानी पर बल पड़ रहा है कि पार्टी को कोई ऐसा चमत्कारिक मैनेजर मिले जो राजनीति और तिकड़म दोनों को संतुलन के साथ मैनेज कर ले. इसके लिए पार्टी नेतृत्व को अमर सिंह से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता. लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में अन्य मैनेजरों का परफॉर्मेंस देखा और परखा जा चुका है. मुलायम इस बात पर खास तौर पर चिंतित रहे हैं कि सपा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐसी बुरी हार देखनी पड़ी. उपचुनाव में सपा ने भले ही रेखांकित करने वाली जीत दर्ज की हो, लेकिन उपचुनाव और पूर्ण चुनाव का फर्क मुलायम सिंह जैसे नेता तो समझते ही हैं. लिहाजा, ऐसे संक्रमण काल में सपा को अपने पुराने मित्र अमर सिंह की जरूरत है. अमर सिंह समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर के सारे बारीक पेचोखम से वाकिफ हैं और राजनीतिक समस्या से निकलने और निकालने की उनमें विशेषता है. इसके साथ ही बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ अमर सिंह की घनिष्ठता और फंड मैनेजमेंट की अनिवार्यता भी सपा नेतृत्व को अच्छी तरह समझ में आती है. तभी सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि नेताजी से अमर सिंह की मुलाकात में कुछ गलत नहीं है. अमर सिंह मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे. मित्र होने के कारण नेताजी ने उनसे मुलाकात की, तो इसमें गलत क्या है? अमर सिंह मुलायमवादी हैं और उनका मुलायम सिंह से मिलना कोई अचरज वाली बात नहीं है. शिवपाल के इस बयान के निहितार्थ समझे जा सकते हैं.

बहरहाल, लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाइन क्या लेगी, इस पर मंथन चल रहा है. महागठबंधन की सम्भावनाओं पर भी चर्चा होगी और विकास के एजेंडे पर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बिजली और कोयला पर केंद्र से युद्ध का ऐलान होगा. विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. सपा सरकार पहले से ही इसकी पेशबंदी कर रही है और केंद्र पर हमला जारी रखे हुई है. इसे घनीभूत करने की रणनीति पर अधिवेशन में विचार होगा. केंद्र को कई बार पत्र लिख कर भावी राजनीति की भूमिका तैयार करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को उसके कोटे की बिजली मिलनी चाहिए. यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां बिजली की मांग भी ज्यादा है, इसे केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए. अखिलेश का कहना था कि केंद्र की अनदेखी के कारण कोयला नहीं मिल पाने से प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है. जब तक आवश्यक मात्रा में कोयला नहीं मिलता, तब तक प्रदेश में बिजली उत्पादन की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता. अभी हाल ही एक समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाइक की मौजूदगी में कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार को सौ दिन हुए हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार को छह महीने देने के लिए तैयार हैं. केंद्र को यह समझना चाहिए कि यूपी ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन केंद्र ने प्रदेश को क्या दिया है! मुख्यमंत्री ने ऐसा कह कर तभी भविष्य के राजनीतिक एजेंडे का संकेत दे दिया था.

पार्टी के पिछले अधिवेशन की तरह लखनऊ अधिवेशन उहापोहों वाला अधिवेशन साबित नहीं होगा, तैयारी इसी बात की है. पिछली बार की तरह कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को समर्थन देने की मजबूरी और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भिड़ने की अनिवार्यता का विरोधाभास और साथ-साथ आजम खान की उच्छृंखलता पर कोई कार्रवाई न कर पाने की विवशता जैसी स्थिति भी नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को लेकर सियासत गर्म

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

कैलाश मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भाजपा अब आमने-सामने हैं. नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर चीन और केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है. नया रास्ता खोलने का धर्मनगरी हरिद्वार के कई साधु-संतों ने स्वागत किया है. उत्तराखंड सरकार को नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रास नहीं आ रही है. कैलाश मानसरोवर यात्रा तीन देशों (भारत, नेपाल और चीन) के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी विश्व की एकमात्र व अनूठी पैदल यात्रा है. उत्तराखंड का मार्ग पौराणिक मार्ग है. मान्यता है कि इसी मार्ग से पांडव भी कैलाश गए थे. यात्रा मार्ग में पांडव व कुंती पर्वतों से तथा स्कंद पुराण के मानसखंड में इसकी पुष्टि होती है. इस यात्रा के दौरान करीब 230 किमी की पैदल दूरी (भारतीय क्षेत्र में 60 एवं चीनी क्षेत्र में करीब 150 किमी) चलनी पड़ती है, जिसमें से चीनी क्षेत्र के अधिकांश मार्ग में वाहन सुविधा भी उपलब्ध है. भारतीय क्षेत्र में भी करीब आधे मार्ग में बीआरओ के द्वारा सड़क बन चुकी है. इस पौराणिक मार्ग से तीर्थ यात्रियों को प्राकृतिक रूप से 'ऊं' लिए 'ऊं पर्वत' और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते हैं, साथ ही हिमालय को करीब से निहारने यहां की जैव विविधता व सीमांत क्षेत्र के जनजीवन को जानने-समझने का मौका भी मिलता है. इस मार्ग को पास किया जाने वाला लिपुपास दर्रा भारत-चीन के बीच का सबसे आसान दर्रा भी माना जाता है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को बदलने के निर्णय को उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचाने वाला बताया है. इस निर्णय से न केवल हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भावना को भी चोट पहुंची है. मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यदि व्यापार आदि के लिए अन्य मार्ग को खोला जा सकता है, तो यात्रा के लिए यही मार्ग उचित है. हमारे धर्माचार्य इसी मार्ग को अपनाते रहे हैं. भगवान शिव इसी मार्ग से हिमालय में मां पार्वती (नन्दा) से मिले थे. वे स्थान यहीं मौजूद है, जिन्हें शिव ने स्पर्श किया था. जो पुण्य कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस मार्ग से मिलता है, वह अन्य से नहीं. महान विचारक राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का उल्लेख किया है. स्वामी परमानंद इसी मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि केन्द्र सरकार इस निर्णय को बदलेगी तथा कैलाश

मानसरोवर यात्रा मार्ग उत्तराखंड से ही रहेगा. राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि इससे प्रदेश का पर्यटन प्रभावित होगा जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की सोच ही नकारात्मक है. भाजपा ने कहा है कि इससे प्रदेश के तीर्थाटन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत तो पिछले कई दिनों से मानसरोवर यात्रा के मार्ग में हुई तब्दीली को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं. प्रदेश के कई स्थानों पर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जोरदार आंदोलन भी शुरू किया जा चुका है. प्रदेश के पर्यटन मंत्री दिनेश धने भी यात्रा मार्ग बदलने को लेकर केंद्र की आलोचना कर चुके हैं. धने ने कहा कि यात्रा मार्ग बदलने से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है. अब तो प्रदेश आपदा से ही पूरी तरह से उबर नहीं पाया है. अभी तो केंद्र को हर नजरिए से राज्य की मदद करनी चाहिए.धने ने कहा कि प्रदेश को आपदा से उबारने की आवश्यकता है ताकि फिर से पहले की तरह तीर्थयात्री इस प्रदेश में आएं. उन्होंने कहा कि केंद्र के इस फैसले से उत्तराखंड कमजोर होगा और प्रदेश का तीर्थाटन भी प्रभावित होगा. दूसरी ओर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार या कांग्रेस के नेताओं को मानसरोवर यात्रा मार्ग के बदलाव को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग नहीं बदला गया है, नये मार्ग का सृजन किया गया है. रावत ने स्पष्ट कहा कि जो तीर्थयात्री प्रदेश के मार्ग से होकर गुजरना चाहते हैं उन्हें जाने में कोई रोक-टोक नहीं है. रावत ने कहा कि नाथुला दर्रे से मानसरोवर की ओर जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है. इससे फायदा होगा कि बुजुर्ग भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश का मार्ग बंद नहीं हो रहा है. यह मार्ग तो पहले की तरह ही खुला रहेगा. सुरक्षा के लिहाज से नाथुला दर्रे वाला मार्ग भी बेहद सुरक्षित है. लिहाजा कांग्रेस और उसकी सरकार को बेवजह कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. यह तो शुभ संकेत है कि अब ज्यादा से ज्याद तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं. कैलाश यात्रा मार्ग को लेकर कांग्रेस को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए. कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सिक्किम से नया रास्ता खोलने का धर्मनगरी हरिद्वार के कई साधु-संतों ने स्वागत किया है. साधु संतों का कहना है कि वक्त के साथ नई मान्यताएं स्थापित होती रहती हैं. पहले बद्रीनाथ सहित चारधाम की यात्रा पैदल हुआ करती थी. अब सरकार खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर बद्रीनाथ-केदारनाथ पहुंच रही है और यात्रियों को भी ले जा रही है. गंगा सभा के अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी का कहना है कि मुख्यमंत्री इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु वाहनों में बैठकर कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं. वृद्ध और लाचार भी मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे. जूना अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम गिरि कहते हैं कि यात्राओं के नए रूट तो खुलते ही रहते हैं. शहरों का विकास होता है तो कारोबार बढ़ता है, घटता नहीं. कैलाश की पैदल यात्रा में तीर्थ यात्रियों को लॉटरी सिस्टम से जाना पड़ता है और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नया रास्ता खुलने से अब पर्यटक भी इस अनूठी यात्रा का आनंद ले सकेंगे. इस बीच अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा से आय कमाने वाले व्यवसायियों ने नाथुला दर्रे से नया रास्ता शुरू किए जाने के लिए हुए समझौते के खिलाफ कुमाऊं क्षेत्र में प्रदर्शनों व धरनों का दौर शुरू हो गया है. केएमवीएन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पौराणिक यात्रा मार्ग पर नाथुला दर्रे का कोई खास असर नहीं होगा, यह भी सच है कि केएमवीएन के कर्मचारी भी इस मार्ग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि निगम के पास तीन माह तक के लिए यही काम है. ऐसे में यदि यहां यात्रा प्रभावित हुई तो फिर निगम का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है. पर्यटन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए समझौते के तहत कैलाश मानसरोवर के लिए अरुणाचल प्रदेश के नाथुला दर्रे से नये मार्ग के खोले जाने से यात्रा आयोजक कुमाऊं मंडल विकास निगम-केएमवीएन आशावादी है कि इस कदम से यात्रा को और अधिक प्रचार-प्रसार मिलेगा तथा मौजूदा पौराणिक यात्रा मार्ग से होने वाली यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा. केएमवीएन के महाप्रबंधक विनोदगिरि गोस्वामी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के साथ ही जैन, बौद्ध, सिख और बोनपा धर्म के भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, विश्व की सबसे कठिनतम और प्राचीनतम पैदल यात्राओं में शुमार 1,700 किमी लंबी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर वर्ष यात्रियों की संख्या के नए रिकार्ड बन रहे हैं. वर्ष 2012 में 774 तीर्थयात्रियों ने इस यात्रा पर जाकर रिकार्ड का नया शिखर छुआ था, जबकि इस वर्ष की यात्रा में पहली बार सर्वाधिक 18 दल इस यात्रा में शामिल हुए और 910 तीर्थयात्रियों ने अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. गोस्वामी का कहना है कि हर वर्ष ढ़ाई से तीन हजार लोग यात्रा के लिए आवेदन करते हैं, सीमित संसाधनों की वजह से सबको ले जाना संभव नहीं होता. उन्होंने उम्मीद जताई कि नया मार्ग खुलने से यात्रा का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, साथ ही प्रकृति प्रेमी, पैदल ट्रेकिंग के इच्छुक युवा एवं धार्मिक, आध्यात्मिक भावना वाले यात्री अभी भी पौराणिक मार्ग से ही यात्रा करना पसंद करेंगे. उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी नेपाल के रास्ते हवाई सेवा के जरिए भी कैलाश यात्रा के लिए अनेक मार्ग हैं, उनकी वजह से भी मौजूदा पौराणिक मार्ग की यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है. ■

शहीदों की उपेक्षा टीम तीरथ के गले की फांस बनी

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2013 सितंबर में भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पहुंचे 15 लाख के ड्राफ्ट आईटीबीपी के तीन शहीदों के परिवारों तक नहीं पहुंचने के खुलासे के बाद यह प्रकरण टीम तीरथ के लिए पुरी तरह से गले की फांस बन गया है. प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को शहीद परिवार के आश्रितों को अब तक पांच-पांच लाख राशि नहीं देने का खुलासा किया था. शहीदों के आश्रित इस धन राशि को प्राप्त करने के लिए दर दर भटके स्थानीय नेताओं ने लगातार उनकी आवाज को अनसुनी कर दी. बताते चलें कि सवा साल पहले प्रदेश में आई भीषण आपदा के दौरान आईटीबीपी के तीन जवान शहीद हो गए थे. इस दौरान ही भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शहीद परिवार के आश्रितों को पांच-पांच लाख की राशि पार्टी फंड से देने की घोषणा की थी. जिसे उनकी ओर से उत्तराखंड भाजपा कार्यालय को घोषित धनराशि के ड्राफ्ट समय पर भेज भी दिया गया, जिसे शहीद परिवार के दर्द से बेखबर लापरवाह नेताओं ने नजरअंदाज कर बेकार टोकरी में डाल दिया. सूत्रों का दावा है कि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों का खुला अपमान मानते हुए पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उत्तराखंड भाजपा द्वारा बरती गई इस लापरवाही के बारे में एक नोट भी लिखा है और शाह ने इसे गंभीरता के तौर पर लिया है. इसके बाद शाह ने तत्काल ही टीम तीरथ से इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस वजह से भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से भेजे गए 5-5 लाख की राशि अब तक शहीद परिवारों के आश्रितों तक नहीं पहुंचाई गई.

वैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उप चुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा की हार की वजह से टीम तीरथ से नाराज चल रहे हैं जिसकी वजह से शाह ने अब तक टीम तीरथ को नई दिल्ली में मिलने का समय नहीं दिया है. अब ड्राफ्ट प्रकरण ने पार्टी के अंदर दिल्ली से देवभूमि तक भूचाल खड़ा कर दिया है. टीम तीरथ विरोधी लाबी ड्राफ्ट मामले को लेकर भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं को भी यह जानकारी दी है कि खास रणनीति के तहत ही पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने शहीद परिवार के आश्रितों तक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एलान की गई राशि पहुंचाने की कोशिश नहीं की जबकि भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से 15 लाख के ड्राफ्ट बीते सितंबर 2013 में ही आ गए थे. यह गुट सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की मांग भी कर रहा है शाह खुद ही रिपोर्ट टीम तीरथ से मांग चुके हैं. इस बारे में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शहीद परिवार तक ड्राफ्ट नहीं पहुंचना एक बड़ी चूक है. शहीद परिवार के आश्रितों को भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से भेजे गए 15 लाख का ड्राफ्ट एक साल बाद भी टीम तीरथ द्वारा उन्हें नहीं सौंपे जाने का मामला अब और ज्यादा उलझता जा रहा है. भाजपा हाईकमान ने टीम तीरथ से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है जबकि प्रदेश भाजपा के ही एक गुट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से ड्राफ्ट प्रकरण की रिपोर्ट टीम तीरथ से मांगने के बजाय केंद्रीय स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में एक टीम गठित कर पड़ताल कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके. शुरू में भाजपा हाईकमान ने 48 घंटे के अंदर ही शहीद परिवारों के आश्रितों को ड्राफ्ट देने में हुई चूक की रिपोर्ट मांगी, बाद में टीम तीरथ को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा है. प्रदेश भाजपा का ही एक गुट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहा है कि टीम तीरथ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ड्राफ्ट मामल में हुई चूक की निष्पक्ष रिपोर्ट टीम तीरथ नहीं दे सकती. इस पूरे प्रकरण पर टीम तीरथ के सदस्य ही शामिल हैं, लिहाजा यदि टीम तीरथ इस मामले की पड़ताल करेगी तो वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी, मामले की हर तरह से लिपापोती ही की जाऐगी.. इस प्रकरण के कई साल पहले फंड में हुई गड़बड़ी की पड़ताल के लिए प्रदेश स्तर पर एक टीम गठित की गई सालों बीत जाने के बाद भी फंड में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है. इसलिए संगठन हित में सबसे बढ़िया यही रहेगा कि केंद्रीय नेताओं की एक टीम गठित की जाए जो इस मामले की पड़ताल करे. सूत्रों के मुताबिक संघ ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. संघ का इस मामले में स्पष्ट कहना है कि प्रदेश भाजपा सवा साल पहले प्रदेश में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेरती एवं इस पर हमला करती रही है, दुर्भाग्य यह है कि आपदा से जुड़े मामले में टीम तीरथ की ओर से लापरवाही बरती गई है जिससे पूरे प्रदेश में गलत संदेश गया है. माना जा रहा है कि संघ भी यही चाह रहा है कि ड्राफ्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेताओं को ही पड़ताल करनी चाहिए. गृहमंत्री राजनाथ की पहल एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तगड़ी फटकार के बाद प्रदेश में आई आपदा के दौरान देवभूमि में शहीद हुए तीन जवानों के परिजनों को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 5-5 लाख के चेक बांटे गए. भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने शहीद अजय लाल के बड़े भाई प्रेम हिंदवाल, शहीद नंदराम की पत्नी मंजू देवी और शहीद जयेंद्र प्रसाद की पत्नी शीला देवी को 5-5 लाख के चेक दिए. शहीदों के परिजनों को पांच-पांच लाख के चेक एक साल पहले ही दिए जाने थे. आपसी कलह में मस्त भाजपा के खच्चर नुमा नेता है कि बिना चाबूक के एक कदम आगे नही बढ़ते जिसका परिणाम है कि मोदी के शानदार मिशन पर पानी फिर रहा है. ■

गंगा की उपेक्षा का सिलसिला जारी है

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय धरोहर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए देश व प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते पिछले साल आई आपदा के दौरान त्रिवेणीघाट में क्षतिग्रस्त सरस्वती नाले को अभी तक सही नहीं कराया गया है, जिसके एक हिस्से से शहर की गंदगी सीधे गंगा में प्रभावित हो रही है. इस कारण यहां आने वाले हजारों देशी-विदेशी श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है. इसके बावजूद नाले के ट्रीटमेंट से जुड़ी फाइलें करीब नौ माह से सरकारी महकमों में धूल फांक रहीं हैं. वर्ष 2013 जून में उत्तराखंड आपदा के दौरान गंगा में आई बाढ़ के कारण त्रिवेणीघाट में सरस्वती नाले का एक हिस्सा टूट गया था. जिसके बाद से पूरे शहर की गंदगी इस स्थान पर सीधे गंगा में मिल रही है. इसके समीप ही करोड़ों की लागत से स्थापित सीवेज पंपिंग स्टेशन का वर्क पूरा हो गया, लेकिन इस नाले से जुड़े होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके लिए कार्यदायी संस्था निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा द्वारा 56.04 लाख रुपये की एक योजना तैयार की गई. जिसमें नाले को पंपिंग स्टेशन से जोड़ा जाना है. 19 दिसम्बर 2013 को प्रस्तावित योजना की फाइल मुख्यालय को भेजे जाने के बाद मुख्य अभियंता द्वारा चार दिन बाद 23 दिसंबर को शासन को भेज दी गई. इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने प्रस्तावित योजना की आवश्यकता व अनापत्ति को लेकर मई 2014 में नगरपालिका से जवाब मांगा. जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नगरपालिका द्वारा 10 जून 2014 जवाब भेज दिया गया. इसके तीन माह गुजर जाने के बाद भी फाइल अधर में लटकी हुई है. लगभग साढ़े तीन करोड़ की लागत से त्रिवेणीघाट में निर्मित सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) सरकारी महकमों की उदासीनता के कारण बंद पड़ा है. निर्माण के बाद स्टेशन ने 25 मई से सात जुलाई तक महज सवा महीने ही काम किया है. इस बीच गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पंपिंग स्टेशन ठप हो गया. यहीं नहीं बरसात के दिनों में त्रिवेणीघाट का समूचा

वर्ष 2013 जून में उत्तराखंड आपदा के दौरान गंगा में आई बाढ़ के कारण त्रिवेणीघाट में सरस्वती नाले का एक हिस्सा टूट गया था. जिसके बाद से पूरे शहर की गंदगी इस स्थान पर सीधे गंगा में मिल रही है. इसके समीप ही करोड़ों की लागत से स्थापित सीवेज पंपिंग स्टेशन का वर्क पूरा हो गया, लेकिन इस नाले से जुड़े होने के कारण भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

प्लेटफार्म भी सीवेज की गंदगी से अट जाता है. धर्मनगरी ऋषिकेश का वक्षस्थल कहा जाने वाला त्रिवेणी घाट की स्थिति यहां के सभी नेता और अफसरों की जानकारी में है. कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं दिख रहा है. सभी की गंगा के प्रति संवेदना इस कदर शून्य हो गई है कि लोग मां कह कर दीप आरती करते है, अपने लाख-लाख कल्याण की कामना भी करते है, लेकिन मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाने से कतराते है. इससे भी खतरनाक सच यह है कि इस धर्मनगरी के तट पर गंगा का जयकारा लगा कर अकूत संपत्ति के स्वामी बने संतो के बहुतायत आश्रमों के गंदे नाले बिना रोक-टोक के गंगा में ही अबाध गति से गिराए जा रहे है जिसमें गंगा की सेवा का ढ़िडोरा पीटने वाले परमार्थ आश्रम का गंदा नाला भी निर्बाध गंगा को मौला कर रहा है, जिस पर आश्रम परिवार और प्रशासन ने अपनी आंखे बन्द कर रखी है. गंगा के नाम पर रोटी कमाने और खाने वाले लोगों की बदनियत गंगा की सफाई में घोर बाधा बनी हुई है.

(विभाग द्वारा सरस्वती नाले को एसपीएस से जोड़ने के प्रस्ताव को शासन को भेजा गया है. धन आवंटन के अभाव में यह कार्य नहीं हो पा रहा है. जैसे ही योजना को मंजूरी मिलने के साथ धन आवंटित होगा. निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि शहर से निकलने वाले अवजल को गंगा में प्रवाहित होने से रोका जा सके. पीके गुप्ता-परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा) ■

एक नारी की व्यथा

आखिर काम क्यों नहीं करते सरकारी अफसर

पारुल उनियाल

केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को हर सुविधाएं और उनके कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता तो जताती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अधिकारियों से कहते हैं कि देश की जनता का एक कार्य भी नहीं रूकना चाहिए उनके हर कार्यों का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए. जब एक महिला किसी सरकारी कार्यलय में किसी कार्य के लिए जाती है, तो उसके कार्य को सबसे पहले निपटाना चाहिए. लेकिन आज भी देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जो भ्रष्ट, कामचोर हैं, जो न देश की सेवा करते हैं और न ही देश की नागरिकों की. लोगों को आशा थी कि सरकार बदलेगी, तो व्यवस्था भी बदलेगी, लेकिन सरकार तो बदली व्यवस्था नहीं बदली. एक ताजा उदाहरण है पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून का. मैं पारुल यूनियाल ने पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी मेरा पासपोर्ट आज तक नहीं बना. पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद जब मैं अप्पोइंमेंट के दिन पीएसके देहरादून पहुंची, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि तत्काल आवेदन के लिए संग्लक(i) एवं (F) अतिआवश्यक हैं, लेकिन यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन के समय नहीं दी गई थी और न ही कोई इमेल या एसएमएस के माध्यम से बताया गया कि कौन से दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थान पर जाना है. टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज के जो कस्टमर हैंडलिंग/सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वहां उपस्थित थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि यदि कोई पीएसके आता है, तो उसको यहां आने के पूर्व इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जाती है. उसी समय जानकारी न होने के कारण तहसील का बार-बार चक्कर काटना पड़ता है और 100 रुपये के नोटरी के कार्य के लिए 500 रुपये देना पड़ता है. मैंने वहां जाने के बाद देखा कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए किवोस्क भी लगे हैं,

यहां मदद और जानकारी न मिल पाने के कारण मैं तहसलीदार की मुहर लगवाने के लिए कोर्ट परिसर में प्रतिक्षा करती रही, लेकिन कार्य न होने के कारण मैं एक बार फिर एसडीएम के पास गई और उनसे पूरा वाकया बताया. उसके बाद उन्होंने चपरासी को बुलाकर मुहर लगावाकर सभी दस्तावेजों की पुष्टिकरण का एक प्रमाणपत्र बनाकर अपनी उप-जिलाधिकरी की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ मुझे दे दिया.

लेकिन ऑपरेट स्वयं करना है, जिस व्यक्ति को कम्प्यूटर की जानकारी नहीं होगी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोई कैसे आवेदन करेगा? सरकार को समझना चाहिए कि देश की एक बड़ी संख्या है, जो आज भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाती है, तो उन लोगों की मदद कौन करेगा. इसलिए गांवो और छोटे शहरों में उसके पास एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए होना चाहिए. पीएसके से ये पता चलने के बाद की संग्लक (i) एवं (F) के बिना कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. उसके बाद मैं ऋषिकेश तहसली पहुंची और वहां से संग्लक (i) एवं (F) बनवाया नोटरी से संग्लक (i) सत्यापित करवाया, लेकिन एसडीएम के अनुपस्थिति के कारण संग्लक(F) सत्यापित नहीं हो पाया. शाम 5 बजे तक एसडीएम का इंतजार करते-करते तहसील की समय अवधि समाप्त हो गई और अंततः मैं हार कर घर वापस आ गई. अगले दिन 19-09-2014 को मैं पुनः तहसील गई और वहां जाकर एसडीएम से मिली उनसे पीएसके का हाल बताया, तो उन्होंने मदद के तौर पर मेरे सभी दस्तावेज सत्यापित कर दिया. उसके बाद मैं उस पर मुहर लगवाने के लिए दूसरे विभाग में गई. वहां जानकारी न होने के कारण मैं गलत लाइन में लग गई और वहां पर एक महिला कर्मचारी दस्तावेजों की जांच कर रही थी. उसने सभी दस्तावेज लिए और उसके बाद मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी और दस्तावेजों को लेकर कहने लगी कि ये आगे पीछे क्यों लगाया है. आपको पता नहीं कि कैसे लगाने चाहिए और फिर उसके बाद मेरी उससे कहा सुनी हुई. उस समय भी मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि जब हम जैसे युवा और पढ़े-लिखे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उन लोगों का क्या जो लोग दूर से आते हैं और भूखे, प्यासे परे दिन लाइन में खड़े रहते हैं. शायद उनके साथ भी यही होता होगा कि उनको जानकारी देने के बजाय सरकारी विभागों में कुर्सी पर बैठे कामचोर कर्मचारी, दुर्व्यवहार करते होंगे.

यहां मदद और जानकारी न मिल पाने के कारण मैं तहसलीदार की मुहर लगवाने के लिए कोर्ट परिसर में प्रतिक्षा करती रही, लेकिन कार्य न होने के कारण मैं एक बार फिर एसडीएम के पास गई और उनसे पूरा वाकया बताया. उसके बाद उन्होंने चपरासी को बुलाकर मुहर लगावाकर सभी दस्तावेजों की पुष्टिकरण का एक प्रमाणपत्र बनाकर अपनी उप-जिलाधिकरी की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ मुझे दे दिया. लेकिन संग्लक (F) सत्यापित नहीं किया. यह कहकर कि उनके पास राजपत्रित अधिकारी की सील नहीं है और ये अन्चछेद देहरादून के एडीएम सत्यापित कर सकते हैं. उसके बाद मैं तुरंत संग्लक(F) को लेकर मैं देहरादून कोर्ट गई कि वहां दो एडीएम हैं, लेकिन शाम चार बजे ही वहां कोई उपस्थित नहीं था. ऑफिस के लोगों ने बताया कि न तो एडीएम सर न ही एडीएम मैम इस संग्लक को सत्यापित करके सील देंगे. प्रशासन के आगे आम आदमी कितना मजबूर है, यह उस दिन पता चला. कोर्ट से मदद न मिलने के बाद मैं देहरादून सत्यापन सेल गई, तो वहां पता चला की ऋषिकेश के सीओ क्षेत्राधिकारी इसे सत्यापति कर सील लगा सकते हैं. उसी शाम मैं ऋषिकेश थाना पहुंची, तो पता चला कि सीओ अपने ऑफिस में हैं उम्मीद थी कि शायद सीओ अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे मैं उनसे मिलने सीओ ऑफिस गई, लेकिन वे नहीं मिले. उसके बाद वहां कार्यरत बाबू लोगों की बाते सुनकर मैं अचंभित रह गई. वे लोग कहने लगे की क्या आप सीओ को जानती है? क्या कोई जान-पहचान है? मैंने उत्तर दिया नहीं, तो वे लोग कहने लगे की बिना व्यक्तिगत जान-पहचान के सीओ सर राजपत्रित अधिकारी की सील और आईडी नहीं देंगे. अब सवाल यह उठता है कि जब कोई हमारीमदद नहीं कर सकता जबकि हमारे पास सभी सच्चे दस्तावेज हैं वह चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या चाहे हमारे शिक्षा प्रमाणपत्र हों. उन्हें देखकर सत्यापित नहीं कर सकते तो सरकार चुनाव के समय वोटर-आईडी क्यों बनवाती है? क्यों बिना वोटर-आईडी कार्ड के हम वोट नहीं दे सकते? क्यों बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते? जब इन दस्तावेजों के होने के बावजूद कोई हमें सत्यापन का प्रमाण नहीं दे सकता तो क्यों सरकार इन दस्तावेजों को निरस्त नहीं कर देती. क्यों ऐसे लोगों को सरकार कुर्सी पर बैठा रखी है? जिनके पास राजपत्रित अधिकारी की मुहर तक मुहैया नहीं करा सकती. क्यों इतनी परिक्षा पास करने के बाद ये आईएएस, पीसीएस जैसे अधिकारी बनते है, जब ये हमारी मदद नहीं कर सकते? आज जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उसके पास 1 नहीं 4 पासपोर्ट मिलते हैं, तो इतनी जांच के बावजूद उनको अलग-अलग देशों के इतने पासपोर्ट कैसे मिल जाते हैं? इसका जवाब कौन देगा? यही अधिकरी जांच के नाम पर सीधे-साधे लोगों को दौड़ाते हैं फिर भी उनका कार्य नहीं होता है. भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पैसे देकर खतरनाक आतंकवादियों का पासपोर्ट बन जाता है. उन्हें सभी दस्तावेज प्रमाणपत्र के साथ मिल जाते हैं, लेकिन हमको अपने दस्तावेज बनावने और प्रमाणपत्र के लिए कई बार सरकारी ऑफिसों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके बावजूद भी उनके प्रणाणपत्र नहीं बन पाते. हम जैसी महिलाओं की मदद करने में सरकारी महकमें क्यों पीछे रहते हैं. क्या यह अधिकरी एक महिला की मदद नहीं कर सकते? क्या एक महिला होने के कारण आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल पुछ रही हूं कि क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के लोगों की मदद क्यों नहीं करते? इसलिए सरकार से निवेदन करती हूं कि ऐसे कामचोर और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि फिर दोबारा हमारी जैसे किसी महिला के साथ यह अन्याय न हो. ■

आजम खान की मुश्किले बढ़ीं

वैष्णवी वंदना
feedback@chauthiduniya.com

अच्छे दिन लौटने का इंतजार कर रहे आजम खान को अपने राजनीतिक करियर के बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं. एक तरफ आजम अपनी नियति और अपने कृत्यों से समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक करियर पर ही काली छाया पड़ रही है. लाभ के दो-दो पदों पर काम करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अभी तो नोटिस ही जारी किया है. आगे क्या होगा, इसका अभी से अनुमान लगाया जाने लगा है. 25 सितम्बर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज देवी प्रसाद सिंह और अरविंद कुमार त्रिपाठी (द्वितीय) ने आजम खान को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि वे लाभ के दो पदों पर एक साथ कैसे काबिज हैं. न्यायालय ने उनसे छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है. आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद भी सम्भाल रहे हैं. हाईकोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर किया है कि मंत्री रहते हुए आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कैसे रह सकते हैं. उल्लेखनीय है कि लखनऊ के शिया धर्मगुरु इमाम राजा हुसैन और एस आमिर हैदर रिजवी ने आजम खां के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडेय ने तर्क दिया कि आजम खान मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है. संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति विधायक नहीं हो सकता. ऐसे में जिस दिन आजम खान कुलाधिपति बने उसी दिन वे मंत्री पद के अयोग्य हो गए. याचिका में मांग की गई है कि आजम खान को मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनका चुनाव भी रद्द किया जाए. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को 10 सितम्बर 2014 को सरकार के पक्ष के साथ पेश होने का निर्देश दिया है. साफ है कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय अब उनकी सियासी कुर्सी पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद से शुरू हुई आजम खान की लड़ाई अब बेहद गंभीर रूप अख्तियार कर चुकी है. अब तक जिस संविधान का जिक्र कर आजम खान वक्फ बोर्ड का चुनाव करवाकर मौलाना को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वहीं संविधान और कानून अब आजम के विधायक और मंत्री होने पर उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहा है. लाभ के दो-दों पर रहने का मसला इसके पहले भी सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, अमर सिंह, जया बच्चन समेत कई प्रमुख हस्तियों को संकट में डाल चुका है. प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति चुनाव इसी मसले को लेकर अधर में फंस गया था, जिस संकट से वे बहुत मुश्किल उबरे थे. प्रणब पर तो आरोप था कि वे एक साथ लाभ के कई पदों पर काम कर रहे थे. वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष, बीरभूम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष और रवींद्र भारती सोसायटी के अध्यक्ष थे. याद रहे कि जया बच्चन की राज्यसभा से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद देशभर में लाभ के पद का विवाद सुर्खियों और बृहद चर्चा में आया. जया बच्चन की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा से इस्तीफ़ा देकर फिर चुनाव लड़ा. उन्हें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. लोकसभा के निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा में विपक्ष के तत्कालीन उपनेता विजय कुमार मल्होत्रा और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान वरिष्ठ नेता अमर सिंह सहित कई सांसद लाभ के दो-दो पदों पर आसीन होने का मामला झेल चुके हैं. ■

शिवालिक के जंगल अफ्रीकी चींटियों के हमले की जद में

रेनु शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड के शिवालिक के जंगल अफ्रीकी चींटियों के हमले की जद में आ गए हैं, इससे इन जंगलों में हरे पेड़ तेजी से सुख रहे है. जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले उत्तर पश्चिमी हिमालय के शिवालिक के जंगलों में अफ्रीका महाद्वीप और इंडोमलाया क्षेत्र की खतरनाक चींटियों ने हमला बोल दिया है. वन के जानकारों का मानना है कि इन अफ्रीकी चीटीयों से बचाव के उपाय नहीं किए गए, तो हमारे वनों की अपूर्णीय क्षति हो सकती है. विदेशी हमलावर चीटिंयों का यह हमला इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. वह इसलिए कि इन चींटियों का पाया जाना इस बात का संकेत है कि ये जंगल धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं. पिछले 14 वर्षों से चल रहे एक एक जंतु वैज्ञानिक अध्ययन में जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले शिवालिक के जंगलों में चींटियों के 30 हजार नमूने एकत्र किए गए. इसमें पता चला कि शिवालिक की पहाड़ियों के जंगलों में पाई जाने वाली 188 चींटी प्रजातियों में से 20 प्रजातियां इस क्षेत्र की नहीं हैं और विदेशी हमलावर प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरनाक हैं. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर हिमेंद्र भारती के अध्ययन स्टडी ऑफ एंट स्पेशीज अबंडेंस एंड कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम शिवालिक रेंज ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज(जम्मू टू उत्तराखंड) के मुताबिक शिवालिक रेंज में पहली बार चींटियों की ऐसी प्रजातियां पाई

शिवालिक पहाड़ियों में इन चींटियों की ढेरों प्रजातियों की मौजूदगी इस बात की तसदीक करती हैं कि इस पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकीय तंत्र अपना स्वरूप खो रहा हैं. भारतीय वन्यजीव संस्था के वरिष्ठ कीट विज्ञानी वीके उनियाल का कहना हैं कि भविष्य में इन प्रजातियों की संख्या बढ़ती हैं, तो साफ हैं कि वनों का पारिस्थितिकीय तंत्र और बिगड़ गया हैं.

गई हैं जो पहले कभी यहां नहीं देखी गईं. इनमें से 9 चींटी प्रजातियों में से तीन को तो भारत में पहली बार देखा गया है. अन्य छह प्रजातियां दक्षिणी भारत के जंगलों में पाई जाती हैं जो शिवालिक में पहली बार देखी गई हैं. इन चींटियों को किसी भी क्षेत्र के जैविक संकेतक भी माना जाता है. जो हमलावर चींटियां पाई गई हैं इनमें सोलेनोप्सिस जेमिनाटा (ट्रॉपिकल फायर एंट), टेट्रामोरियम कैल्डेरियम (स्मॉल रैडिश एंट), टेक्नोमायरमेक्स एल्बाइप्स (व्हाइट फुटेड एंट), स्ट्रमिजेनिस मेंब्रेनिफेरा (क्रिप्टिक प्रेडेटरी एंट) आदि शामिल हैं. यह माना जाता है कि ये विदेशी हमलावर चींटी प्रजातियां केवल उन्हीं स्थानों में पाई जाती हैं जहां का पारिस्थितिकीय तंत्र तेजी से खराब हो रहा हो. शिवालिक पहाड़ियों में इन चींटियों की ढेरों प्रजातियों की मौजूदगी इस बात की तसदीक करती है कि इस पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकीय तंत्र अपना स्वरूप खो रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्था के वरिष्ठ कीट विज्ञानी वीके उनियाल का कहना है कि भविष्य में इन प्रजातियों की संख्या बढ़ती है, तो साफ है कि वनों का पारिस्थितिकीय तंत्र और बिगड़ गया है. शोध के अनुसार खतरे की बात यह है कि इन चींटियों की मौजूदगी इन क्षेत्रों में भी पाई गई है, जो शिवालिक की विशिष्ट जैव विविधता वाले इलाके रहे हैं और जहां मानव गतिविधि शून्य है या न के बराबर है. शिवालिक की पहाड़ियों के जंगलों में पाई गई 20 हमलावर विदेशी चींटियां 14 वर्ष के अध्ययन में नौ चींटी प्रजातियों में से तीन को तो भारत में पहली बार देखा गया है. राज्य का वन विभाग इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से ही बचाव की मुद्रा में आ गया है. ■